



# संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट

ऐक्ट नं० ३६ सन् १९४७ ई०

[ गाँव में दीवानी, माल और कौजदारी के मुकदमों का निर्णय तथा सरपञ्च कैसे बनेगा तथा सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि की स्थापना अब कैसे होगी, सफाई, रोशनी, पानी का इन्तजाम कैसे होगा—कानूनी नोट सहित ]

लेखक एवं प्रकाशक  
श्री सुरेन्द्र नारायण एंडवोकेट, हाईकोर्ट,  
इलाहाबाद

लेखक यू० पी० काश्तकारी ( तरमास ) ऐक्ट ४७ यू० पी०,  
रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट ४७ यू० पी०, विक्रीकर ऐक्ट मय  
संशोधन, ग्राम सुधार भूमि अधिकृत ऐक्ट  
सम्पादक तथा कानून सीरीज ।

मिलने का पता :—

**कानून महल**

१ सी० वार्ड० चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद

तृतीय संस्करण ५००० ]

[ संशोधित व पूर्ण नोट सहित ]

All Rights Reserved.

## दो शः

जनता ने प्रथम और द्वितीय संस्करण हृदय से स्वागत किया। उनकी प्रियता से ही शंशोधित तृतीय संस्करण आपकी सेवा में आया है।

अहा स्वतंत्रता के पुजारी भातर के नवयुग और आधुनिक स्नेह और अनुकम्पा की मूर्ति शबरी कितने ही गाँव सुशोभित कर रही है ! उनके त्याग, सरलता, और साहस, राज्य संचालन की दक्षता व प्रगतिशील व उत्थान की योजना सराहनीय है। “चेरी छांड़ि होई न रानी” का युग बीत गया अब नवयुग है अपने ही जीवन में हर स्त्री, पुरुष राज्य शासक या राज्य संचालिका होने के स्वप्न व्यवहारिक रूप में परिणित करते पाये जाते हैं। पंचायत राज के एकट व अंतरगत नियम के हर एक पहलू को अच्छी प्रकार समझ कर, जन सेवा और लोक प्रियता के आदर्श को सामने रख कर निरंतर जो धैर्य के साथ चलता रहेगा तो राज्य सत्ता उसके पैरों पर लौटिगी। वे प्रेसोडेंट, गवर्नर मिनिस्टर आदि यथा समय होंगे।

प्रम प्रेम, कटरा प्रयाग।

# भूमिका

संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट—ग्रामीण भाइया क जावन एक विशेष अङ्ग है। सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक, शारीरिक स्थिति को एक उन्नतशील श्रेणी का बनाने में सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण चेष्टा है। इससे ग्रामीण वासियों की नसों में नवीन अन्तर्गतता का संचार होगा। स्थानीय ग्राम शासन की बागडोर गीण भाइयों के हाथ में होगी वे सामूहिक रूप से हर एक क्षेत्र अग्रगामी होंगे। अदालत क्षेत्र में दीवानी, फौजदारी तथा माल मुकदमें पञ्च अदालत में आसानी से स्वयं सुलझा सकेंगे। कोर्ट में, पेशकार, चपरासी, अदालती की धाँधली से बचेंगे और कामों और जजों को गलत रास्ता सुझानेवाले मुकदमों को उलट-पीठा कराने वाले जो हथकंडों पर चढ़ा कर न्याय का गला घुटाने की चेष्टा करते हैं सब दूर हो जायेंगे।

सामाजिक क्षेत्र में सड़क बनवाना, सफाई, रोशनी, पानी का अन्तर्जाप करना, स्वयं-सेवक तथा विद्या की शिक्षा देना खेती में उन्नति करना अस्पताल खोलना मृतकों को ठिकाने लगाना पैदा-इश, मृत्यु तथा विवाह का सही रजिस्टर तैयार करना जिससे गाँव के बहुत से मुकदमेवाजी की जड़ खत्म हो जायगी। सारांस यह है कि जीवन के हर एक पहलू में हस्तक्षेप करने का मौका है और ऊपरी रुकावट के बिना पुनः निर्माण करने का और अपनी उन्नति करने और अग्रसर होने का सुअवसर प्राप्त है। ग्रामीण भाई जागृत हो जाये तो देश के एक भारी अङ्ग का उद्धार अवश्यभावी है।

प्रगतिशील उद्देश्यों को पूरा करने के लिये हर एक गाँव में, गाँव

सभा, गाँव पञ्चायत, पञ्चायती अदालत की स्थापना की जायेगी ये संस्थाएँ न्याय करेंगी तथा शासन गाँव का बहुत अंश में चलायेगी।

गाँव-सभा—प्रान्तीय सरकार ने गाँव और ग्राम समूह के लिये गाँव-सभा स्थापित होने के नाम गजट कर दिये हैं उनका अधिकार क्षेत्र विस्तृत होगा। गाँव-क्षेत्र के सब स्त्री, पुरुष जिनकी आयु २१ वर्ष या उससे अधिक हो गाँव-सभा के जीवन पर्यन्त जब तक उनमें कोई अयोग्यता न आ जावे, सदस्य रहेंगे ऐसे सदस्यों का एक रजिस्टर नियमानुसार रक्खा जायेगा सभा अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनेगी जो तीन वर्ष तक उस पद पर रहेंगे। गाँव सभा को अधिकार होगा कि कर लगाए, भूमि प्राप्त करे, ऋण ले तथा सभा की सम्पति का प्रबन्ध करे, अथवा उसके विषय में भगड़े तय करे।

प्रति वर्ष गाँव सभा की दो बैठकें, एक खरीफ और दूसरी रबी की फसल के पश्चात् होगी। सभा की नियमित संख्या (कोरम) सदस्यों की कुल संस्था का पाँचवाँ हिस्सा की होगी। गाँव सभा आगामी वर्ष के आय व्यय (वजट) के ऊपर विचार खरीफ की बैठक में करेगी और उसे स्वीकार करेगी। गत वर्ष के हिसाब किताब पर विचार पञ्चायत रबी के बैठक में करेगी। कुल वसूली का धन जमा करने के लिये गाँव सभा के अधिकार में एक गाँव कोष खोला जायेगा उसका धन एक्ट के बताये हुए कार्यों में गाँव पञ्चायत लाएगी।

गाँव-पञ्चायत—गाँव सभा को अपनी कार्य-कारिणी समिति निर्वाचन करने का आदेश है गाँव-पञ्चायत ऐसी ही निर्वाचित कार्य-कारिणी समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या सरकारी आह्वा-नुसार ३० से ५२ तक होगी। इस सभा के सभापति तथा उपसभा-

पति गाँव-पंचायत के भी सभापति और उपसभापति होंगे। निवचित सदस्य तीन वर्ष के लिए पंचायत सदस्य रहेंगे परन्तु सदस्यों की संख्या में से एक तिहाई सदस्य हर साल विश्राम (रिटायर) रोटेशन Rotation से करते रहेंगे।

यह पञ्चायत उन पञ्चों की एक सूची रखेंगी, जो पञ्चायती अदालत के कार्यवाही करने योग्य अर्थात् साक्षर होंगे। गाँव-पञ्चायत के ऊपर इन सार्वजनिक-उपयोगिता के कार्य करने का विशेष भार है सफाई, रोशनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मार्ग आदि। और पतरौल, पटवारी, मुखिया, कान्सटेबिल, सेक्रेटरी तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, बदली या उनके हटाने के लिये सिफारिस भी कर सकती है उनके दुराचरण पर रिपोर्ट कर सकती हैं जिससे हाकिम को लाजमी होगा कि तहकीकात करे।

### पञ्चायती-अदालत

ज़िले को क्षेत्रों (circle) में बांटा जायेगा और हर क्षेत्र में एक पंचायती अदालत होगी और उस क्षेत्र में जितनी गाँव सभायें हों प्रत्येक ५ पंच चुनेंगी। इस प्रकार चुने हुये पंचों का पंच मण्डल होगा पंचमण्डल एक विवरण लिखने योग सरपञ्च चुनेगा। पञ्चों की अवधि निर्वाचन से ३ साल की है।

पंचायती अदालत को छोटे माल, दीवानी तथा फौजदारी विवादों (मुकदमों) को फैसल करने का अधिकार दिया गया है। उनके निर्णय (फैसले) अन्तिम और मान्य होंगे जिसका पुनर्विचार (अपील) नहीं होगी, परन्तु गडबड़ी बचाने के लिये ऐसे निर्णय की नज़रसानी मुन्सिफ़ अथवा सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के यहाँ ६० दिन के अन्दर हो सकेगी। इन हाकिमों को यह भी अधिकार होगा कि पञ्चायत विचाराधीन मुकदमों के कागजात को पञ्चायती

अदालत द्वारा निर्णय किये जाने के पूर्व अपने यहाँ मँगावा कर सुनवाई का के आदेश दें।

सब कार्यवाई संक्षिप्त रूप में होगी और साक्षियों का बयान न्यायालय के सामने होगा उसका संक्षिप्त विवरण लिखा जायगा। कारावास के दण्ड देने का अधिकार इन न्यायालयों को नहीं है। इन न्यायालय का शुल्क (कोर्टफीस) रसीद देकर नगद वसूल किया ज वेगा।

सीमा—दीवानी के मुकदमें जिनमें मुअहिदा या चल, सम्पत्ति की मालियत (१००) एक सौ रुपया तक हो और माल के मुकदमें जो मालगुजारी आराजी कानून नं० ३ स० १६०१ की धारा ३३ सालाना रजिस्टर हक इन्दराज का सही रखना ३४ हक पाना या कब्जा बदलने की रिपोर्ट ३५ ऐसी रिपोर्ट पर कार्यवाई ३६ तबदीली कब्जा का रिकार्ड ४० भगड़ा सही रजिस्टर का तै करना ४१ हद बन्दी आराजी के भगड़े तै करना उल्लिखित है और फौजदारी के मुकदमें जो भारतीय दंड विधान की धाराएँ १४०, सैनिक की वर्दी या चिन्ह पहिनना १६० भगड़ा करना, १७२ सम्मन तामील से भागना, १७४ हाकिम के हुक्म पर भी हाजिर न होना, १७६ हाकिम के पृथ्वी पर भी जवाब न देना २७७ जन तालाब या भरने के पानी को गन्दा करना, २७६ अधाधुन्य सवारी चलाना, २८३ खतरा या रक्कावट जन मार्ग या जल मार्ग पर करना, २८५ आग लगने का काम करना जिससे जान को खतरा हो, २८६ बारूद आदि का लापरवाही से काम करना, २८६ जानवरों को लापरवाही से रखना जिससे जान खतरे में हों, २८७ जन मार्ग पर खुराकात फैलाने के लिये सजा २६४ गन्दे गाने या कर्म ३२३ चोट लगाना, ३३४ जान-पर चोट लगाना उद्दिग्न होकर, ३३६ कार्य जिससे जनता के लिये नुकसान हो, ३४१ गैर कानूनी रोक करना, ३५२ हमला, ४५६

चोरी की कोशिश में हमला. ३५७ गैर कानूनी बन्दी करने की कोशिश में हमला. ३५८ उद्विग्नता में हमला करना; ३७४ गैर कानूनी जबरदस्ती वेगारी. ३७६ चोरी सजा. ४०३ गबन, ४११ जान बूझ कर चोरी का माल रखना ( जब कि चोरी या गबन, किया हुआ माल रु० पचास से अधिक न हो ). ४२६ शराब, ४२८ जानवर को मारना या अंग काट देना जिसकी १० रु० से अधिक कीमत न हो । ४३० नहर के पानी का रख बदलना, ४४७ अनाधिकार प्रवेश, ४४८ अनाधिकार ग्रह प्रवेश. ५०४ जान बूझ कर अपमान करना जिससे भगड़ा हो. ५०६ जान की धमकी, ५०६ स्त्री अपमान और ५१० शराबी का अनुचित पब्लिक में व्यवहार, जानवर से खेत चरा देना ऐक्ट नं० १ सन् १८७१ की धारा २० से २४ तक आदि सब पंचायती अदालत द्वारा निर्णय किये जायेंगे ।

पैरवी मुकदमें की वादी, प्रतिवादी तथा अभियुक्त को स्वयम् बिना वकील की सहायता के करना होगा क्योंकि कानून व्यवसायी को न्यायालय के सामने पैरवी करना मना है ।

भाषा—पञ्चायती-अदालत की भाषा हिन्दी होगी और वो अपनी मुहर ( सील ) रखेगी । दीवानी नियम संग्रह के अनुसार जो व्यक्ति दीवानी न्यायालय में जाने के लिये बाध्य नहीं किए जा सकते उनके लिए भी पञ्चायती अदालत में उपस्थित होने पर बाध्य न करने की व्यवस्था है ।

भीतरी बातें जानने के लिये ऐक्ट तथा उसके अवगत नियमों का पढ़ना आवश्यक है ।

सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल, एडवोकेट, हाईकोर्ट

१ सी० वाई० चिन्तामणि रोड, इलाहाबाद ।



## उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सन् १९२० ई० का संयुक्त प्रान्त का गाँव-पञ्चायती ऐक्ट, इसलिये पास किया गया था कि देहात के क्षेत्रों में दीवानी और फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने में सहायता मिले और गाँव का सफाई एवं वहाँ के दूसरे सार्वजनिक कामों को उन्नत किया जा सके। अब सभी स्वीकार करते हैं कि उक्त ऐक्ट के अधीन उन्नति अल्प हुई। उक्त ऐक्ट में कुछ मौलिक दोष थे वे नये पञ्चायतों में दूर किये हैं। उनमें से सब से मुख्य यह है कि इसके अधीन जो पञ्चायतें बनाई गई थीं वह सर्वजनिक मत का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं और उनका कार्यक्षेत्र बहुत संकुचित था सरकार ने अब इससे अधिक विस्तृत कानून दिया है जिसमें यह दोष नहीं है और जिसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण वासियों की उचित आकांक्षाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

इस ऐक्ट में अधिक विस्तृत सार्वजनिक आधार पर अधिकांश सभी गाँवों में पञ्चायतें स्थापित करने की व्यवस्था है। इसके द्वारा उनको अधिकार दिया गया है कि वे कुछ कर लगा सकें, अपने क्रोशों ( फण्डों ) का प्रबन्ध कर सकें, उप-नियम ( वाइलाज ) बना सकें, अपने बजट तैयार कर सकें और स्कूल व शफाखाने स्थापित कर सकें और उन्हें चला सकें। इसका उद्देश्य यह भी है कि गाँव में स्वयंसेवकों की एक संस्था रक्षा और देख-भाल के लिये संगठित की जाय और पंचायती अदालतें स्थापित की जायें जो गाँव-पञ्चायतों से भिन्न हों और माल और फौजदारी के मुकदमों का फैसला

करने के अधिकार प्राप्त हो। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि गाँव के सामूहिक जीवन को फिर से जागृति किया जाय और लोगों में आत्मविश्वास और सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना पैदा की जाय जिससे कि वे सरकार पर बहुत अधिक निर्भर रहे बिना अपनी दशा स्वयं सुधार सकें और ग्रामीण जीवन में स्वतन्त्रता की नई लहर आवे उनका जीवन उल्लास और साहस से भर जावे और अपनी उन्नति शिखर पर पहुँचा कर अपनी बुद्धि और कार्यक्षमता का परिचय दे सकें।

### सम्मति

हर्ष के साथ मैं सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल एडवोकेट हाईकोर्ट की प्रगतिशील बुद्धिमर्त्ता की सराहना करता हूँ जिस कौशल से उन्होंने पञ्चायत राज को आम जानता के सामने सुलभ बना दिया है।

दैगौर टाउन प्रयाग )

गोपाल बिहारी  
एडवोकेट हाई कोर्ट

# विषय-सूची

## अध्याय १

प्रारम्भिक बातें	१८-२४
१—संक्षिप्त शीर्षक, सीमा, और प्रारम्भ.	१८
२—परिभाषायें	१९

## अध्याय २

गाँव-सभाओं का स्थापित किया जाना और उनका विधान	२३-२७
३—गाँव-सभाओं का स्थापित किया जाना और उनका विधान और उनका अधिकार-क्षेत्र	२३
४—गाँव-सभा की स्थापना	२४
५—गाँव-सभा की मेम्बरी	२४
६—मेम्बर रहने की अवधि	२५
७—नियुक्ति या नामजदगी से संबन्धित किसी अयोग्यता या त्रुटि से कोई कार्य या कार्यवाही रह नहीं होगी	२६
८—गाँव-सभा की जन-संख्या घट-बढ़ जाने या उसके क्षेत्र की म्युनिसिपैलिटी आदि में सम्मिलित करने का असर	२७
९—मेम्बरों का रजिस्टर	२७
१०—गाँव-सभा स्थापित करने और किसी गाँव पञ्चायत की कार्य-विधि में कठिनाई का दूर किया जाना	२८

## अध्याय ३

गाँव-सभा— उसकी बैठक और कार्य	२७-३०
११—गाँव-सभा के कर्त्तव्य और कार्य	... २७
१२—गाँव-सभा पञ्चायत की स्थापना और उसका संगठन	... २८
१३—गाँव-सभा का वज्रट	... ३०
१४—गाँवसभा के सभापति या उप-सभापति को हटाया जाना और इस प्रकार खाली होने वाली जगहों की पूर्ति	३०

## अध्याय ४

गाँव-पञ्चायत के अधिकार, कर्त्तव्य, काम और शासन-प्रबन्ध	३०-४५
१५—कर्त्तव्य और काम	... ३०
१६—ऐच्छिक कार्य	... ३३
१७—जन-मार्गों जल-मार्गों और दूसरी बातों के सम्बन्ध में गाँव-पञ्चायत का अधिकार	... ३५
१८—सफाई सम्बन्धी सुधार	... ३६
१९—स्कूलों और अस्तालों को चलाना और उनमें सुधार करना	... ३७
२०—कुछ गाँव-सभाओं के समूह में प्राइमरी स्कूल और कुछ या सफाखाना खोलना	... ३८
२१—सरकारी कर्मचारियों को सहायता	... ३९
२२—गाँव-पञ्चायतों की ओर से प्रार्थना पत्र और सिफारिशें	... ३९
२३—कुछ अफसरों के दुराचरण के बारे में जाँच करने और रिपोर्ट देने का अधिकार	... ३९

२४—मालिकों के लिये टैक्स और दूसरे महसूल वसूल करने के बारे में मुआहिदा करने का अधिकार	४०
२५—कर्मचारी	४०
२६—व्यक्तिगत मेम्बरों का अधिकार	४१
२७—गाँव-पञ्चायत के धन या सम्पत्ति की हानि, उसके अप-व्यय या बेजा इस्तेमाल के लिये सजा	४२
२८—मेम्बर और कर्मचारी जन-सेवक सकम्मे जायेंगे	४२
२९—कमेटी	४२
३०—संयुक्त कमेटी	४३
३१—अधिकारों का सौंपना	४३
३२—गाँव-कोष ( फण्ड )	४४

## अध्याय ५

भूमि, गाँव-कोष ( फण्ड ) और सम्पत्ति प्राप्त करना	४५-५१
३३—भूमि प्राप्त करने का अधिकार	४५
३४—सम्पत्ति, जिस पर गाँव-सभा का अधिकार होगा	४६
३५—दावों का निबटाया जाना	४६
३६—ऋण लेने का अधिकार	४७
३७—टैक्स जो लगाये जा सकते हैं	४७
३८—मतालियों की वसूली कोष ( फण्ड ) की रक्षा और हिसाब	४८
३९—पञ्चायती अदालतों का खर्च	४८
४०—हिसाब की जाँच	४०
४१—चजट	४८

## अध्याय ६.

पंचायती अदालत	५१-५६
४२—पंचायती अदालत का क्षेत्र	५१
४३—पंचायती अदालत का विधान	५१
४४—सरपंच का चुनाव	५२
४५—पंचायती अदालतों की अवधि	५२
४६—पदग्रहण की शपथ	५२
४७—इस्तीफे	५२
४८—अलग किया जाना	५२
४९—पंचों की बैठ	५३
५०—इत्तफाकिया खाली होने वाली जगहों का भरा जाना	५४
५१—अधिकार-सीमा का क्षेत्र	५४
५२—जुर्म जिनकी पंचायती अदालत सुनवाई करेगी	५५
५३—शान्ति बनाये रखने के लिये जमानत	५७
५४—दंड	७५
५५—नालिशों की सुनवाई इत्यादि	५७
५६—कुछ सूरतों में फौजदारी की कार्रवाइयों का पंचायती अदालत में भेजना	५८
५७—इस्तगासों को सरकारी तौर पर खारिज करना	५८
५८—इस्तगासे को वापस करना	५८
५९—कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई पञ्चायत नहीं कर सकती	५९
६०—मुस्तगीसों को मुआवजा	६०
६१—मुल्जिम ( अभियुक्त ) को मुआवजा	६०
६२—मुजरिमों ( अपराधियों ) को आजमाइश पर रिहा करना	६०

६३—मजिस्ट्रेटों के भेजे हुये मुकदमों की तहकीकात ...	६१
६४ अधिकार-सीमा ...	६१
६५ फरीकों ( पत्तों ) की रजामन्दी से अधिकार-सीमा का विस्तार ...	६२
६६—नालिशों जो पंचायती अदालत के अधिकार-सीमा से बाहर होगी ...	६२
६७—नालिशों में पूरा मुतालवा शामिल होना चाहिये...	६३
६८—मियादें ...	६३
६९—पंचायती अदालत के निर्णय का प्रभाव ...	६४
७०—एक्ट मालगुजारी नं० ३, सन् १९०१ ई० के अधीन कार्रवाइयाँ ...	६४
७१—नजरसानी ...	६५
७२—कार्यवाहियाँ ...	६५
७३—निबटाये हुये झगड़े और ऐसी नालिशों जिनका फैसला न हुआ हो ( निर्णीत और विचाराधीन नालिशों )...	६५
७४—अदालतों का बराबर अधिकार ...	६६
७५—नालिशों और मुकदमों का दायर किया जाना ...	६६
७६—दरखास्त का सारांश जो रजिस्टर में लिख लिया जायगा	६६
७७ - कार्रवाही का तरीका ...	६७
७८—सम्बन्धित फरीक के उपस्थित न होने की दशा में नालिशों और मुकदमों का खारिज किया जाना...	६७
७९—पंचायती अदालत अपने फैसले ( निर्णय ) की नजरसानी न करेगी या उसको न बदलेगी ...	६८
८०—कानून का पेशा करने वाला कोई व्यक्ति परवा न करेगा	६८
८१—अदालत में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना	६८

८२ - ऐसे मामलों के बारे में जिसमें राजीनामा इत्यादि हो गया हो विशेष अधिकार-सीमा	६६
८३—सच्चाई का पता चलाने का अधिकार और तरीका	६९
८४—बहुमत का निर्णय मान्य होगा	७०
८५—पंचायती अदालतों के सम्बन्ध में हाकिम परगना सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ) और मुन्सिफों के अधिकार	७०
८६—गवाहों से नाम सम्मन जारी करना	७२
८७—पंचायती अदालत के सामने उपस्थित न हो सकने के लिये दण्ड	७३
८८—नालिशों वगैरह का खारिज किया जाना	७३
८९—नजरसानी	७४
९०—मुद्दाअलेह या अभियुक्त ( मुलजिम ) के नाम सम्मन जारी होना	७४
९१—वारंट	७४
९२—डिगरी के अदा किये जाने के बारे में इन्दराज किया जायगा	७५
९३—डिगरी का इजरा होना	७५
९४—जुमाने की वमूली विधि	७६

### अध्याय ७

वाह्य नियंत्रण	७६-७८
९५—मुआइना	७६
९६—कुछ कार्यवाहियों की मनाही	७७

### अध्याय ८

दण्ड और कार्य विधि	७८-८६
९७—इस एक्ट के आदेशों को उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दण्ड	७८



८८—नियमों और उपनियमों ( वाईलाज ) का उल्लंघन करना	७६
८९—गाँव-पंचायत की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का दण्ड	८०
१००—जारी किये हुये नोटिस का उल्लंघन करना	८०
१०१—नोटिस नाजायज नहीं होगी	८१
१०२—अपील	८१
१०३—कुछ दशाओं में मुकदमों का स्थगित होना	८२
१०४—अपराध के सम्बन्ध में राजीनामा कराने का अधिकार	८२
१०५—दखल ( प्रवेश ) और मुआइना	८३
१०६—गाँव-पंचायतों या उसके अफसरों के विरुद्ध नालिशें	८४
१०७—गाँव और अदालती पंचायतों की रक्षा	८५
१०८—अपराधों के बारे में पंचायतों की सहायता देने के सम्बन्ध में पुलिस के अधिकार और कर्तव्य	८५
१०९—स्थानीय बोर्डों से गाँव पंचायत के बीच झगड़ा और उसका निर्णय	८६

## अध्याय ९

नियम, उपनियम ( वाईलाज ) और उनकी मंजूरी	८६-९६
११०—प्रान्तीय सरकार का नियम बनाने का अधिकार	८६
१११—डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को उपनियम ( वाईलाज ) बनाने का अधिकार	८९
११२—गाँव-पंचायतों के उपनियम ( वाईलाज ) बनाने का अधिकार	८३
११३—मंजूरी और स्थाई आदेश	८४
परशिष्ट	८६
चुनाव की रूप रेखा	आखीर में १ से ५
अन्तरगत नियम	५ से १२

# संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट

सन् १९४७ ई०

संयुक्त प्रान्तीय धारा सभा के निम्नलिखित ऐक्ट को गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट सन् १९३५ ई० की धारा ७६ के अधीन जैसा कि उसका संशोधन इण्डिया ( प्राविजनल कान्स्टीट्यूशन ) आर्डर सन् १९४७ ई० द्वारा हुआ है । ७ दिसम्बर, सन् १९४७ ई० को आमान् गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नम्बर २६ सन् १०४७ ई०

[ जैसा कि उसे संयुक्त प्रान्तीय धारा सभाओं ने पास किया ]

संयुक्त प्रान्त के देहाती क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन ( लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ) स्थापित करने और उसे उन्नत करने के लिए ।

## एक ऐक्ट

### प्राक्कथन

चूँकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्त के देहाती क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित किया जाय और उसकी उन्नति की जाय, एवं गाँवों के शासन और उनकी उन्नति की ओर अधिक अच्छी व्यवस्था की जाय ।

नोट—प्राक्कथन से जब कभी किसी बात के समझने में संदेह हो तो सहायता मिलती है । किसी कानून के प्राक्कथन से या धाराओं के शीर्षकों (headings) से आशयों को समझने में सहायता मिलती है ।

इसलिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है -

## अध्याय १

### प्रारम्भिक बातें

### संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारम्भ

१—( १ यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट सन् १९४७ ई० कहलायेगा ।

नोट—पञ्चायतों का इतिहास इस प्रकार है—प्राचीन काल से भारत वर्ष में पञ्चायत और पञ्चों की परम परा चली आ रही है जो विशेषकर छोटे आपस के झगड़े सामूहिक रूप से न्यायोचित धारण करके व्यक्तिगत को बाध्य करती है । पर इसके न्याय को मानने का बन्धन सामाजिक है । सरकार ने सरकारी पञ्चायतों स्थापित करने के लिये जिसका न्याय उच्चारण सरकारी तौर पर लागू हो और छोटे झगड़े गाँव वालों के सरलता से फैसल हो इसके अनुसन्धान के लिये १९०६ में सेन्ट्रल कमीशन बैठाया जिसके प्रस्ताव पर छान बीन कर उस कानून का बिल बनाया था जिस पर सन् १९१५ में भारत सरकार ने सहानुभूत प्रकट की थी । पुनः एक विशेष कमेटी के विचाराधीन दिया गया जिसने विशेष अनुसन्धान, जाँच पड़ताल सब प्रान्तों के राय व लोकमत लेने के बाद एक बृहद रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर बिल बना और १९२० में संयुक्त प्रान्त का पञ्चायत राज ऐक्ट नं० ४ बना जिनके आधार पर पुरानी पंचायतें चल रही हैं और वे वर्तमान ऐक्ट के अन्दर पंचायतें बनने पर तोड़ दी जायेंगी पुरानी पंचायतें में कुछ चुने हुये गाँवों के परमित न्याय व शासन व्यवस्था कर दी थी पर अब नये ऐक्ट ने उनको पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया है वस्तुतः वे ग्राम शासक व अधिकारी हो गये हैं ।

( २ ) यह ऐक्ट सारे संयुक्त प्रान्त पर लागू होगा, सिवाय देहरादून जिला के जौनसार बाबर परगना के और मिर्जापुर जिला के उस हिस्से के, जो कैमूर की पहाड़ियों के दक्षिण में है और सिवाय उस क्षेत्र के जो संयुक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटियों के ऐक्ट, १९१६ ई० के आदेशों के अधीन म्युनिसिपैलिटि या नोटीफाइड एरिया या कैंटोनमेंट ऐक्ट सन् १९२४ के आदेशों के अधीन कैंटोमेन्ट या संयुक्त प्रान्तीय टाउन एरिया ऐक्ट, सन् १९१४ ई० के अधीन टाउन एरिया घोषित किया जा चुका है या उसमें सम्मिलित है या जो इसके बाद इस प्रकार घोषित किया या सम्मिलित किया जाय।

( ३ ) यह ऐक्ट तुरन्त लागू होगा।

नोट—७ दिसम्बर, सन् ४७ को गवर्नर-जनरल की स्वीकृत हुई और २७ दिसम्बर ४७ को गजट में छपा उसी समय से यह ऐक्ट चालू हो या है।

### परिभाषायें

२—इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इसके विषय या संदर्भ के विपरीत न हो—

( क ) “पञ्चायती अदालत” से तात्पर्य किसी ऐसी पञ्चायती अदालत से जो धारा ४२ के अधीन स्थापित की गई हो और इसमें उसकी कोई बैठ भी सम्मिलित हो।

नोट—अब तक संयुक्त प्रान्त में अदालत दीवानी, अदालत माल और अदालत फौजदारी प्रचलित थी वे भी रहेंगी पर इस ऐक्ट द्वारा एक नई उपरोक्त अदालत स्थापित की गई है जिसको थोड़े-थोड़े अधिकार दिये गये हैं।

( ख ) “प्रौढ़” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जिसने अपनी आयु का २१ वाँ वर्ष पूरा कर लिया हो।

नोट—भारत में बालिग साधारणतः १८ वर्ष की आयु पूरी होने पर होता है। ( बालिग ऐक्ट सं० १८७१ ई० के अनुसार ) किन्तु जिसकी सम्पत्ति का प्रधान कोर्ट आफ़ वार्ड्स के अधीन है तो जिसकी सम्पत्ति का संरक्षक उक्त ऐक्ट के अनुसार नियुक्त किया गया है २१ वर्ष के पूरे होने पर बालिग होता था—पंचायतों में २१ वर्ष के सब स्त्री पुरुष को मतदाताधिकार है।

( ग ) “मुकदमे” से तात्पर्य ऐसी फौजदारी की कार्रवाई से है जो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में की जाय जिसकी सुनवाई पञ्चायती अदालत कर सकती हैं।

( घ ) “क्षेत्र” से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसमें कोई पञ्चायती अदालत धारा ४२ के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करे।

( ङ ) किसी गाँव—सभा के सम्बन्ध में “क्लेक्टर” या “डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट” या “सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट” से तात्पर्य, स्थिति के अनुसार, उस जिले या परगने, जिसमें ऐसी गाँव-सभा बनाई गई हो, के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिवीजनल मजिस्ट्रेट से है।

( च ) किसी गाँव पंचायत के सम्बन्ध में “डिस्ट्रिक्ट बोर्ड” से तात्पर्य किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से है जो संयुक्त प्रान्तीय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, सन् १८२२ ई० के अधीन उस जिले में स्थापित किया गया हो जिसमें ऐसी गाँव—पंचायत बनाई गई हो।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १० सन् १९२२ ई०

( छ ) “गाँव-सभा” से तात्पर्य किसी ऐसी गाँव-सभा से है जो धारा ३ के अधीन स्थापित की गई हो।

नोट—“गाँव-सभा” ऐसे गाँवों में स्थापित की जायगी जिसकी आबादी साधारणतया कम से कम एक हजार हो। अगर कम आबादी हो तो ग्राम समूह में स्थापित हो।

( ज ) “गाँव-पंचायत से तात्पर्य गाँव-सभा की उस कार्य-कारिणी कमेटी से है जो धारा १२ के अधीन स्थापित की गई हो ।

( झ ) “संयुक्त निर्वाचन पद्धति” से तात्पर्य उस पद्धति से है जिसके आधीन सब जातियों के निर्वाचक नियत प्राणाली के अनुसार संयुक्त रूप से न कि अलग-अलग जातियों के निर्वाचकों की हैसियत से वोट दें ।

( ञ ) “अल्प संख्यक जाति” से तात्पर्य किसी मुस्लिम या गैर-मुस्लिम जाति से है। यदि अन्तिम सरकारी जनगणना के अनुसार ऐसी जाति की कुल जनसंख्या, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या की ४५ प्रतिशत से अधिक न हो जो उक्त गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो ।

( ट ) किसी गाँव पंचायत के सम्बन्ध में “मुन्सिफ” से तात्पर्य उस मुन्सिफ से है, जिसे उस क्षेत्र में, जहाँ ऐसी गाँव पंचायत बनाई गई हो, स्थानीय मुकदमों में सुनने का अधिकार प्राप्त हो ।

( ठ ) “आवादी” से तात्पर्य किसी गाँव या क्षेत्र की उस जनसंख्या से है जो इस सम्बन्ध में नियत ढंग से निश्चित की गई हो ।

( ड ) “कार्रवाई से तात्पर्य ऐसी कार्रवाई से है, जिसकी व्याख्या धारा ७० के अधीन कर दी गई है ।

नोट—जो कार्यवाही अब तक ऐक्ट मालगुजारी नं० ३ सन् १९०१ के आधीन आगजी के कब्जे के उत्तराधिकार व हस्तान्तरित व सालाना रजिस्टर में आगजी हदबन्दी के विषय में सही तहसीलदार करत था वह जॉच पंचायत द्वारा की जावेगी ।

( ढ ) “जन-सेवक” से तात्पर्य किसी ऐसे राज-कर्मचारी से है जिसकी व्याख्या भारतीय दण्ड-विधान सन १८६० ई० की धारा २१ में की गई है ।

( ग ) "जन-मार्ग" से तात्पर्य किसी ऐसी सड़क, गली, पुल, कूचा, चौक, सहन, तंग गली या रास्ते से है, जिस पर सर्वसाधारण को चलने का अधिकार हो और जिसमें दोनों ओर की नालियाँ या मोरियाँ और उस से मिली हुई किसी सम्पत्ति की नियत सीमा तक की कोई भूमि सम्मिलित है भले ही किसी बरामदे या दूसरी ऊपर की इमारत का छज्जा ऐसी भूमि के ऊपर हो।

( त ) "नियत" से तात्पर्य इस ऐक्ट के अनुसार या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नियत किये हुये से है।

( थ ) "नियत अधिकारी" ( अथारटी ) से तात्पर्य उस अफसर से है, जिसको प्रान्तीय सरकार ने सूचना द्वारा ऐसा अफसर नियत कर दिया हो।

### संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० ३ सन् १९०१ ई०

( द ) किसी गाँव के सम्बन्ध में "मालिक" में कोई ऐसा माल-हतदार या मालिक अदना सम्मिलित है, जिसकी व्यवस्था संयुक्त प्रान्त को मालगुजारी के ऐक्ट सन् १९०१ ई० की धारा ४ के बाक्य-खण्ड ( १५ ) और १६ में की गई है और इसमें उक्त ऐक्ट धारा ७६ और ७७ के आशय के अनुसार कोई मालिक आला और मालिक अदना सम्मिलित है, लेकिन इसमें कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, जो अपने गाँव में अपने हिस्से का लगान या मुनाफा, किसी हस्तान्तरण (मुन्तकिली) के कारण, उस समय पाने का अधिकारी न हो और ऐसी दशा में मालिक से-तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उस समय ऐसा लगान या मुनाफा पाने का अधिकारी हो।

( ध ) "नालिश" से तात्पर्य किसी ऐसी नालिश दीवानी से है, जिसकी मुनवाई पञ्चायती अदालत कर सकती है।

( न ) “गाँव” से तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो उस जिले के जिसमें वह स्थित हो, माल के कागजात में गाँव की तरह दर्ज हो ।

नोट—इस ऐक्ट में गाँव उसी क्षेत्र को संबोधित करता है जो माल के कागजात में बतौर गाँव के दर्ज हो और उन स्थानीय आबादी के क्षेत्रों को नहीं लागू होता जिसमें सिर्फ कुछ भोपड़े हों ।

( प ) “आसामी” और “शिकर्मा” के वही अर्थ होंगे जो इनके अर्थ ऐक्ट कब्जा आराजी. संयुक्त प्रान्त सन् १९३६ ई० में दिए हुये हैं ।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० १७ सन् १९३९ ई०

( फ ) “सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि” से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो बिना किसी साझीदार के किसी एक व्यक्ति के इस्तेमाल में न हो बल्कि जिसे किसी गाँव में रहने वाले सम्मिलित रूप से काम में लाते हों ।

## अध्याय २

गाँव सभाओं का स्थापित किया जाना और उनका विधान

३—( १ ) प्रान्तीय सरकार. सरकारी गजट में सूचना देकर हर एक गाँव या गाँवों के हर समूह के लिये गाँव-सभा स्थापित करेगी ।

( २ ) प्रान्तीय सरकार उपधारा [ १ ] में उल्लिखित सूचना द्वारा गाँव सभा का नाम और उसका अधिकार-क्षेत्र घोषित कर देगा और वह किसी समय भी सरकारी गजट में सूचना देकर अपने प्रस्ताव से या गाँव-सभा के या किसी गाँव के निवासियों के प्रार्थना-पत्र पर, गाँव-सभा के क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है या उससे किसी क्षेत्र को निकाल सकती है ।



३) जब उपधारा [ २ ] के अधीन सूचना देकर कोई क्षेत्र गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय, तो उक्त सूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र पर ऐसी सब सूचनार्य, ऐसे सब नियम, रेगुलेशन, उपनियम और आदेश लागू होंगे जो इस ऐक्ट या किसी ऐसे दूसरे ऐक्ट के अधीन बनाये गये हों. या दिये गये हों जो उस क्षेत्र में लागू हों जो उपयुक्त गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में हों।

### गाँव सभा की स्थापना

४—हर गाँव-सभा, उस नाम से जो धारा ३ के अधीन सरकारी गजट में सूचना प्रकाशित किया जाय, एक संयुक्त संस्था होगी जो बराबर अस्थापित होती रहेंगी और इसकी एक ही मुहर होगी, और उसका किसी ऐसे प्रतिबन्ध या ऐसी दशा की पाबन्दी के साथ जो इस ऐक्ट या ऐसे किसी दूसरे ऐक्ट द्वारा या उसके अधीन लगाई गई हो, चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को मोल लेकर प्राप्त करने, दान स्वरूप या अन्य प्रकार से स्वीकार करने, उस पर कब्जा रखने, उसका प्रबन्ध करने और उसको हस्तान्तरण (मुन्तकिल) करने और (उसके सम्बन्ध में) मुआहिदा करने का अधिकार होगा, और वह उसके नाम अ मुकदमा चला सकेगी, या उस पर उसी नाम से मुकदमा चलाया जा सकेगा।

### गाँव सभा की मेम्बरी

५ - किसी गाँव-सभा में वे सब प्रौढ़ सम्मिलित होंगे जो उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हो जिसके लिये सभा स्थापित की गई हो, लेकिन ऐसा कोई प्रौढ़ किसी गाँव-सभा का न तो मेम्बर बन सकेगा और न उसका मेम्बर रह सकेगा यदि :—

(क) उसका दिमान खराब हो, या

(ख) उसको काढ़ हो या

( ग ) वह दीवालिएपन से बरी नहीं किया गया हो. या

( घ ) वह श्रीमान—सम्राट या स्थानीय किसी अधिकारी लोकल अथारिटी का ऐसा कर्मचारी हो जो किसी गांव-सभा के क्षेत्र या उसके किसी भाग में कर्मचारी हो या कोई ऐसा आननेरी मजिस्ट्रेट, आननेरी मुन्सिफ या आननेरी आसिस्टेन्ट कलेक्टर हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में किसी गांव-सभा का कोई क्षेत्र वा उसका कोई भाग हो. या

सन् १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

( ङ ) उसे चुनाव—सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दण्ड मिल चुका हो; या

( च ) उसको नैतिक अधःपतन से सम्बन्धित किसी अपराध में अपराधी ठहराया जा चुका हो। उसे दण्डविधिसंग्रह, सन् १८६८ ई० की धारा ११० के अधीन नेकचलनी के लिए जमानत जमा करने की आज्ञा दी गई हो।

पर शर्त यह है कि वाक्य-खण्ड ( ग ) या ( ङ ) या वाक्य खण्ड (च) के अधीन अयोग्यता का प्रतिबन्ध प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी की आज्ञा से हटाया जा सकता है।

नोट—गांव-सभा को विस्तृत किया गया है जिसके मेम्बर अस्मन सब स्त्री, पुरुष जो २१ वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके होंगे वगैरें वह गांव के बाशिन्दे हो और उनका दिल, दिमाग, सेहत सही सलामत हो। यह गांव को एक उन्नत पारिवारिक जीवन में लाने की चेष्टा है।

मेम्बर रहने की अवधि

६—कोई मेम्बर गांव-सभा का उस समय तक मेम्बर रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाय या जब तक कि वह धारा ५ के अधीन किसी प्रकार अयोग्य न बन जाय या जब तक कि वह क्षेत्र जिसमें

वह रहता हो धारा ७ के अधीन उक्त गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र से ग्रथक न कर दिया जाय या जब तक कि वह उक्त गाँव में स्थायी रूप से रहना न छोड़ दे।

पर शर्त यह है कि कोई व्यक्ति, जिसका उल्लेख धारा ५ में किया गया और जो उसमें दी हुई किसी अयोग्यता के कारण या गाँव में स्थायी रूप से रहना छोड़ देने के कारण मेम्बर न रह गया हो, अयोग्यता के प्रतिबन्ध के हटा दिए जाने पर या फिर से गाँव में स्थायी रूप से रहना शुरू करने पर, जैसी भी स्थिति हो, और इस सम्बन्ध में गाँव-सभापति के पास मेम्बर बनाये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजने पर ऐसी जाँच के बाद जो नियत की जाय फिर से उस सभा का मेम्बर बनाया जायगा।

**नियुक्त या नामजदगी से सम्बन्धित किसी अयोग्यता या**

**त्रुटि से कोई कार्य या कार्यवाही रद्द नहीं होगी**

७—किन्हीं मेम्बर के बनाये जाने में किसी प्रकार की अयोग्यता, त्रुटि या कोई बात रह जाने के कारण किसी गाँव-सभा का कोई कार्य या कार्यवाही रद्द नहीं होगी, यदि उन मेम्बरों की कम से कम दो-तिहाई संख्या उक्त गाँव-सभा की नियमानुकूल मेम्बर हों, जिनकी उपस्थिति में वह कार्य हुआ हो या कार्यवाही की गई हो।

**गाँव सभा की जन संख्या घट बढ़ जाने या उसके क्षेत्र**

**म्युनिसिपैलिटी आदि में सम्मिलित करने का असर**

८—यदि किसी गाँव-सभा का सारा क्षेत्र किसी म्युनिसिपैलिटी, कैंटोनमेंट ( छावनी ), नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में सम्मिलित कर दिया जाय, तो गाँव-सभा टूट जायगी और उसके देन-पालन का भुगतान नियत दृढ़ से किया जायगा। यदि ऐसे ऐसे क्षेत्र का केवल एक हिस्सा हो इस प्रकार सम्मिलित किया जाय, तो उसके अधिकार क्षेत्र से उतना हिस्सा कम कर दिया जायगा।

## मेम्बरों का रजिस्टर

६—गाँव-सभा के स्थापित किये जाने पर नियत अधिकारी नियत ढङ्ग पर एक रजिस्टर ऐसे सब प्रौढ़ व्यक्तियों का तयार करा-एगा जो ऐसी गाँव सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हों और ऐसे रजिस्टर में दूसरी बातों के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज होगा जो गाँव-सभा के स्थापित किए जाने की तारीख को धारा ५ के आदेशों के अधीन उसके मेम्बर बनने का अधिकारी हो। यह रजिस्टर नियत ढङ्ग के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार सुहराया जायगा।

गाँव-सभा स्थापित करने और किसी गाँव पञ्चायत की कार्य विधि में कठिनाई का दूर किया जाना

१०—यदि किसी गाँव-सभा के स्थापित करने में किसी गाँव पञ्चायत की कार्य विधि में इस ऐक्ट के किसी आदेश या उसके अधीन बनाये हुए किसी नियम के आशय के सम्बन्ध या किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो ऐसे आशय से सम्बन्ध रखती हो या उससे पैदा होती हो या जिसके बारे में इस ऐक्ट में आदेश न हो, कोई झगड़ा या कठिनाई पैदा हो जाय तो उसे प्रान्तीय सरकार के पास भेज दिया जायगा और उसका निर्णय अंतिम और पूर्ण होगा।

## अध्याय ३

गाँव सभा के कर्त्तव्य और कार्य

११—(१) हर गाँव-सभा प्रति वर्ष दो सार्वजनिक बैठकें करेगी—एक खरौरु को फसल के तुरन्त बाद (जिसको बाद में खरीक की बैठक कहा गया है) और दूसरी रबी को फसल के तुरन्त बाद (जिसको बाद में रबी की बैठक कहा गया है)।

पर शर्त यह है कि सभापति स्वयं या कम से कम  $\frac{1}{4}$  मेम्बरों की लिखित मांग पर ऐसी लिखित मांग के प्राप्त होने के ३० दिन के अन्दर किसी भी समय एक असाधारण सावजनिक बैठक बुला सकता है गांव-सभा की सब बैठकों के बारे में, नियत ढङ्ग से, यह सूचना प्रकाशित कर दी जायगी कि वे कब और कहाँ होंगी।

( २ ) गांव-सभा की किसी बैठक के लिये गांव-सभा के कुल मेम्बरों की संख्या के  $\frac{1}{4}$  का कोरम होगा। पर शर्त यह है कि ऐसी बैठक के लिए जो कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित हो गई थी, किसी कोरम की आवश्यकता न होगी।

( ३ ) गांव-सभा अपने मेम्बरों में से एक सभापति और एक उप-सभापति चुनेगी, जो क्रमानुसार प्रधान या सदर और उप-प्रधान या नायब सदर कहलायेंगे और उनके पद की अवधि ३ वर्षों होगी।

### गांव-पञ्चायत की स्थापना और उसका सङ्गठन

१०—( १ ) हर गांव सभा स्थापित होने के बाद, शीघ्र से शीघ्र अपने मेम्बरों में से एक कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव करेगी जो 'गांव-पञ्चायत' कही जायगी।

नोट—“गांव-पञ्चायत” में २१ वर्षों प्रौढ़ स्त्री, पुरुष सब हो सकते हैं जिसको गांव-सभा चुनाव में चुन ले। वह एक तरह से साइसी, गांव के अग्रगामी और प्रगत्शील मनुष्यों की कमेटी होगी।

( २ ) गांव-सभा के सभापति और उप-सभापति के अतिरिक्त जो गांव पञ्चायत के क्रम से सभापति और उप-सभापति, होंगे, गांव-पञ्चायत के मेम्बरों की ३० और ५१ के बीच ऐसी संख्या होगी जो प्रान्तीय सरकार नियत करे।

( ३ ) सभापति या उप-सभापति या ऐसे मेम्बर के अतिरिक्त जो किसी आकस्मिक खाली जगह को भरने के लिए चुना गया हो, गांव

पञ्चायत के हर मेम्बर के पद की अवधि ३ वर्ष होगी और एक-तिहाई मेम्बर हर वर्ष रिटायर होंगे ।

पर शर्त यह है कि जब कोई गाँव-पञ्चायत पहिली बार बनाई जाय, तो नियत किया हुआ अधिकारी उस समय चुने गये कुछ मेम्बरों के पदों की अवधि घटा देगा, जिससे इस बात की व्यवस्था की जा सके कि जहाँ तक सम्भव हो लगभग एक-तिहाई मेम्बर हर वर्ष रिटायर हो जाय ।

(४) नियत किया हुआ अधिकारी गाँव-सभा के क्षेत्र को चुनाव के प्रयोजन के लिये उतने निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँट सकता है जितने चुनाव के लिये आवश्यक हों ।

पर शर्त यह है कि जहाँ कोई अल्पसंख्यक जाति हो वहाँ हर निर्वाचन-क्षेत्र का इस प्रकार बनाया जायगा कि कम से कम एक अल्पसंख्यक जाति का मेम्बर चुना जा सके ।

(५) किसी गाँव-सभा या उसके किसी निर्वाचन-क्षेत्र की गाँव पंचायत के मेम्बरों का चुनाव संयुक्त-निर्वाचन पद्धति के अनुसार किया जायगा ।

(६) अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक जातियों को जो जगहें दी जायगी उनकी संख्या गाँव-सभा के क्षेत्र में क्रम से उनकी जन-संख्या के अनुपात से होंगी ।

नोट :—गाँव क्षेत्र के अन्दर रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम जिस अनुपात (ratio) में आबाद हो उसी अनुपात में उनकी गाँव-पंच यत में जगहें दी जायेंगी (Proportional Representation)

(७) जब कि किसी गाँव-सभा के क्षेत्र में परिगणित जाति के लोग हों, तो पहले चुनाव के लिये उन्हें इतनी जगहें दी जायगी जहाँ ऐसे गाँव-सभा के क्षेत्र में उनकी जन-संख्या के अनुपात से हों बाँट

के चुनाव के लिये उनके प्रतिनिधित्व की संख्या ऐसी संख्या होगी, जो प्रान्त की धारा सभा नियत कर।

## गाँव सभा का बजट

१३—गाँव-सभा हर खरीफ की बैठक में अगले वर्ष के बजट पर विचार करेगी और उसको स्वीकार करेगी और रबी की बैठक में विगत वर्ष के हिसाब-किताब पर विचार करेगी। दोनों बैठकों में, गाँव-सभा सभापति द्वारा पेश की गई कार्य-वाहियों की द्विवर्षीय रिपोर्ट पर विचार करेगी।

गाँव-सभा के सभापति या उप-सभापति का हटाया जाना  
और इस प्रकार खाली होने वाली जगहों की पूर्ति

१४—गाँव-सभा किसी साधारण बैठक में सभापति या उप-सभापति को उपस्थित मेम्बरों को दो-तिहाई वोटों के बहुमत से हटा सकती है। ऐसी दशा में और ऐसी दूसरी दशा में; जब कोई जगह खाली हो, तो गाँव-सभा नियत किए हुए ढंग पर तुरन्त दूसरा सभापति या उप-सभापति चुनेगी।

## अध्याय ४

गाँव पञ्चायत के अधिकार, कर्त्तव्य, काम और  
शासन प्रबन्ध

१५—प्रत्येक गाँव-पञ्चायत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने अधिकार-क्षेत्र में, जहाँ तक उसका कोष (फंड) इजाजत दे, नीचे दी हुई बातों के लिये समुचित व्यवस्था करे :—

( क ) जन-मार्ग बनवाना और उनकी मरम्मत कराना, उन्हें अच्छी दशा में रखना. उनकी सफाई तथा उनमें रोशनी का प्रबन्ध करना;

( ख ) चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता;

( ग ) साफ़ई के लिये और संक्रामक रोगों को दूर करने और उनको फैलने से रोकने के लिये चिकित्सा-सम्बन्धी और रोक-थाम के उपायों को काम में लाना;

( घ ) ऐसी इमारतों या दूसरी सम्पत्ति का जो गाँव-सभा की हों या जो प्रबन्ध करने के लिये उसको हस्तान्तरित की गई हों अच्छी दशा में रखना उनकी रक्षा करना और उनकी देख-रेख करना;

( ङ ) जन्म, मृत्यु और विवाहों के व्यौरे रजिस्टर में चढ़ा कर रखना और धारा ६ में बताये हुये रजिस्टर को बनाये रखना;

नोट—पंचायत का कार्य बहुत विस्तृत है। जो म्युनिस्पैलिटी करती है उसके अलावा रजिस्टर रखना जिससे ठीक ठीक, जन्म, मृत्यु, और विवाह का पता चल सके और शिक्षा, रोशनी, सफाई, कुआँ, ग्वेती-बड़ी व्यापार, आग बुझाना, पशु-गणना जन-गणना सब है।

( च ) जन-मार्ग, सार्वजनिक स्थानों एवं, उस सम्पत्ति पर से जिनकी गाँव-सभा मालिक हो 'मदाखलत बेजा' को दूर करना,

( छ ) मनुष्यों और पशुओं की लाशों और किसी दूसरे दुर्गन्ध वाले पदार्थ का ठीक प्रबन्ध करने के लिये स्थानों की व्यवस्था करना;

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० १६ सन् १९३८ ई०

( ज ) संयुक्त प्रान्त के मेलों के ऐक्ट, सन् १९३८ ई० के आदेशों के विपरीत गये बिना ऐसे मेलों, बाजारों और हाटों को नियन्त्रित करना जो उसके क्षेत्र में लगते हैं और जिनमें वे मेलें, बाजार और हाट सम्मिलित नहीं हैं, जिनका प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार करती है;



( क ) बालकों और बालिकाओं के लिये प्रारम्भिक शिक्षा के (प्राइमरी) स्कूल खोलना और कायम रखना;

( ब ) उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों के सामान्य लाभ के लिये सार्वजनिक चरागाहों और भूमि को छोड़ना या कायम करना और उनका प्रबन्ध तथा देख-रेख करना;

( ट ) पीने, कपड़ा धोने और नहाने के लिये पानी सप्लाई करने (पहुँचाने) के वास्ते सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों को बनवाना, सुधारना और उनको अच्छी दशा में बनाये रखना और पीने का पानी प्राप्त करने के साधनों को नियन्त्रित करना;

( ठ ) नई इमारत के बनवाने और वर्तमान इमारत के बढ़ाये जाने या उसमें परिवर्तन के लिये नियम बनाना;

( ड ) खेती-बड़ी व्यापार और उद्योग-धन्धों की उन्नति में सहायता करना;

( ढ ) आग लग जाने पर आग बुझाने और लोगों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने में सहायता करना;

( ग ) दीवानी और कौजदारी की अदालती कार्यवाई का प्रबन्ध और इस पेंक्ट के आदेशों और उसके अधीन बनाये हुये नियमों के अनुसार पञ्चायती अदालत के पञ्चों की सूची में रखे जाने के लिये पञ्चों का निर्वाचन करना;

( न ) पशु-गणना जन-गणना और ऐसे दूसरे आंकड़ों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण लेख रखना जो नियत किये जायें ।

( थ ) मृतिका और शिशु का हित साधन करना;

( द ) खाद इकट्ठा करने के लिये स्थान नियत करना;

( ध ) ऐसे दूसरे दायित्वों को पूरा करना, जो किसी दूसरे कानून द्वारा किसी गाँव-सभा पर लगाये गये हों;

( न ) कुमायूँ डिवीजन की पहाड़ी पट्टियों में दर्जा २ और कैसरे

हिन्द जङ्गल. बेनाप पानी की नालियों और पानी पीने के स्थानों ( पनघटों ) को अच्छी दशा में बनाये रखना और उनकी निगरानी करना।

## ऐच्छिक कार्य

१६ - कोई गाँव पंचायत अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर नीचे दी हुई बातों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था कर सकती है:—

( क ) जन-मार्ग के दोनों ओर तथा दूसरे सार्वजनिक स्थानों में पेड़ों को लगाना और उन्हें अच्छी दशा में रखना;

( ख ) मवेशियों की नस्ल सुधारना, उनकी चिकित्सा और उनके रोगों की रोक-थाम करना;

( ग ) गन्दे गड्डों को भरवाना और भूमि को समतल करना;

( घ ) नियत किये हुये नियमों के अधीन गाँव की रक्षा और चौकी-पहरे के लिये गाँव-पंचायत और पंचायती अदालत को उनके काम पूरा करने में सहायता करने के लिये और उनके द्वारा जारी किये हुये सम्मनों और नोटिसों की तामील करने के लिये. गाँव-स्वयं-सेवक दल का संगठन करना;

( ङ ) सरकारी कर्ज ( ऋण ) प्राप्त करने और उन्हें आपस में बाँटने और उनके चुकाये जाने के सम्बन्ध में और पुराने कर्जों को भुगतान करने और साधारणतः कानून के अनुसार कर्ज लेने और देने की प्रणाली को अच्छे ढङ्ग पर चलाने के सम्बन्ध में किसानों की सहायता करना और उनको परामर्श देना,

( च ) सहयोग सम्बन्धी कामों की उन्नति और उन्नत बीजों और औजारों के गोदाम स्थापित करना;

( छ ) दुर्भिक्ष या दूसरी विपत्तियों के समय सहायता करना;

( ज ) गाँव-सभा के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के क्षेत्र के सम्बन्ध

में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ऐसे कामों के करने के लिये अनुरोध करना जो गाँव-सभा के अधिकारों से बाहर हैं;

( भ ) आवादी के क्षेत्र को बढ़ाना;

( ब ) एक पुस्तकालय या वाचनालय का स्थापित करना और उसे कायम रखना;

( ट ) मनोविनोद और खेलों के लिए अखाड़े या क्लब या दूसरे स्थान का स्थापित करना और कायम रखना;

( ठ ) खाद और वहारन ( कूड़ा-कंकट ) जमा करने हटाने और उसका प्रबन्ध करने के लिए नियम बनाना;

( ड ) आवादी के २२० गज के अन्दर चमड़े को साफ़ करने, कमाने और रखने की मनाही करना वा उसके सम्बन्ध में नियम बनाना ।

( ढ ) विभिन्न जातियों में सद्भाव और सामाजिक एकता बढ़ाने के लिये संस्थायें स्थापित करना;

( ण ) सार्वजनिक रेडियो सेट और ग्रामोफोनों का प्रबन्ध करना;

( त ) सार्वजनिक उपयोगिता का कोई ऐसा दूसरा काम करना, जिसेसे गाँव के लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति हो या जिसेसे उनकी सुविधायें बढ़ें;

( थ ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पहले से अनुमति लेकर गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कोई ऐसा दूसरा काम करना जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कामों के अन्तर्गत आता हो; और

( द ) कोई ऐसा काम करना, जिसके सम्बन्ध में किये गए खर्च को प्रान्तीय सरकार या प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति से कोई नियत अधिकारी वह घोषणा कर दें कि वह गाँव सभा के कोष ( फण्ड ) पर एक उपयुक्त भार हैं ।

नोट—जिला ( डिस्ट्रिक्ट ) बोर्ड से मिलते जुलते बहुत से अधिकार इस धारा १६ में सार्वजनिक भलाई व उन्नति के लिये गांव पंचायतों को मिल गये हैं ।

सन् १८७३ ई० का ऐक्ट न० ८

१७—गांव पंचायत का नियन्त्रण ऐसे सब जन-मार्गों पर और ऐसे सब जल-मार्गों पर रहेगा, जिनमें नहरें सम्मिलित नहीं हैं; जैसी कि उनकी व्याख्या उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई के ऐक्ट, सन् १८७३ ई० की धारा ३ की उपधारा ( १ ) में की गई है, जो उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर हों और जो न तो किसी के जन-मार्ग या जल-मार्ग हों और न प्रान्तीय सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या किसी ऐसे दूसरे अधिकारी के, जिसको प्रान्तीय सरकार ने नियत किया हो; नियन्त्रण में हों, और वह ऐसे सब काम करेगी जो उनकी अच्छी दशा में बनाये रखने और उनकी मरम्मत करने के लिये आवश्यक हों और वह—

( क ) नये पुल या पुलिया बनवायेगी,

( ख ) किसी जन-मार्ग, पुलिया या पुल को या तो बदल देगी या छोड़ देगी या बन्द कर देगी,

( ग ) किसी जन-मार्ग, पुलिया या पुल को आस-पास के खेतों को कम से कम नुकसान पहुँचाते हुए चौड़ा करेगी; विस्तृत करेगी, बढ़ाएगी या उनमें किसी और तरह से सुधार करेगी,

( घ ) पानी के रास्तों ( जल-मार्गों ) को और गहरा करेगी या उनमें किसी और तरह से सुधार करेगी.

सन् १८७३ ई० का ऐक्ट न० ८

( ङ ) नियत किये हुए अधिकारी की स्वीकृति से और जहाँ उत्तरी भारत की नहर और सिंचाई के ( नार्दन इण्डिया केनाल एण्ड्नेज ) ऐक्ट, सन् १८७३ ई० के अधीन कोई नहर हो, ऐसे

अफसर की भी स्वीकृति लेकर, जिसे प्रान्तीय सरकार करे, सिंचाई की छोटी योजनायें चालू करेगी;

( च ) ऐसी भाड़ी या पेड़ की शाख को काटेगी जो जन-मार्ग पर झुक आई हों;

( छ ) सार्वजनिक उपयोग में आने वाले किसी स्रोत ( चश्मे ) को केवल पानी पीने या खाना बनाने इत्यादि के काम के लिये सुरक्षित रखने की घोषणा करेगी, और उसे नहाने, कपड़े धोने और जानवरों को नहलाने या ऐसे दूसरे काम के लिये उपयोग में लाने को मनाही कर देगी, जिससे ऐसे सुरक्षित रखे हुये स्रोत के गन्दा होने की आशंका हो ।

पर शर्त यह है कि किसी ऐसे अधिकारी की पहले आज्ञा लिये बिना जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में नियत किया हो, चाक्य-खण्ड ( छ ) के अधीन कोई ऐसा काम न किया जायगा जो किसी ऐसी नहर के बारे में हों जिस पर उत्तरी भारत के नहर और सिंचाई के ( नार्दन इण्डिया कैनाल एन्ड ड्रेनेज ) ऐक्ट नं० ८ सन् १८७३ ई० लागू हो ।

### सफ़ाई सम्बन्धी सुधार

१८—सफ़ाई-सम्बन्धी सुधार के लिये किसी गाँव-पंचायत को अधिकार होगा कि वह एक नोटिस द्वारा किसी भूमि या इमारत के मालिक या उस भूमि या इमारत पर जब्ज रखने वाले व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उसे यथोचित समय देकर निम्नलिखित बातों को करने के लिये आदेश दे :—

( क ) किसी पाखाने, पेशाबखाने, नावदान, नाली, चहबूत्ता या दूसरी गंदगी का बर्तन, मोरी का गन्दा पानी कूड़ा—करकट या मैला जमा करने की जगह, जो ऐसी भूमि या इमारत से सम्बन्धित हो, बन्द करना, हटाना, उसमें परिवर्तन करना उसकी मरम्मत

करना, उसकी सफाई करना, कीटाणुनाशक दवाइयों द्वारा उसे शुद्ध करना या अच्छी दशा में रखना, या किसी एक ऐसे पाखाने, पेशाब-खाने या नाबदान को जो किसी सड़क या नाली पर खुलता हो, हटाना या उसके किसी दरवाजे या कठद्वार को बदलना या उसके लिये नाली बनाना, या ऐसे पाखाने, पेशाबखाने या नाबदान को एक उपयुक्त छत और दीवार या आढ़ द्वारा राहगीरों या पड़ोस में रहने वालों की दृष्टि से छिपाये रखना;

( ख ) किसी निजी कुएँ, तालाब; हौज जूहड़ ( पोखर ) गड्ढा, या खुदी हुई गहरी जगह को जो उस भूमि या इमारत में हो जो गाँव-पञ्चायत की राय में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो या पड़ोस में रहने वालों के लिये नागवार हो, साफ करना, उसकी मरम्मत करना, उसे ढँक देना, भरना, गहरा करना या उनमें से पानी निकलवाना;

( ग ) वहाँ से वनस्पति, पेड़ों के नीचे उगने वाली छोटी झाड़ियाँ, नागफनी या स्कव जंगल को साफ करा देना;

( घ ) वहाँ से धूल, गोबर, गलोज, खाद या किसी बदबूदार चीज को हटाना और भूमि या इमारत की सफाई करना ।

पर शर्त यह है कि कोई व्यक्ति जिसे वाक्य-खण्ड ( ख ) के अधीन नोटिस दिया गया हो, नोटिस मिलने के ३० दिन के भीतर उसे नोटिस के विरुद्ध "डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ" के पास अपील कर सकता है जो उस नोटिस को बदल सकता है, रद्द कर सकता है या बहाल कर सकता है ।

स्कूल और अस्थितियों को चलायाना और उनमें सुधार करना

१६—( १ ) किसी गाँव-पञ्चायत को उचित होगा—

( क ) कि वह उन नियमों के अनुसार जो पाठ्य-पुस्तकों की सूची, ट्रे एंड अध्यापकों की नियुक्ति और योग्यता और स्कूल की

देख-रेख के बारे में बनाये जायँ, किसी वर्तमान प्राइमरी स्कूल का और उसकी इमारतों और फर्नीचर का खर्च उठाये और उस स्कूल को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी ले और उसका अधिकार होगा कि वह इसी तरह का कोई नया स्कूल स्थापित करे और उसका खर्च उठावे या किसी मौजूदा स्कूल की हालत सुधारें।

(ख) कि वह उन नियमों की पाबन्दी के साथ, जो अस्पताल या शकाखाना खोलने, उन्हें कायम रखने और उसकी देख भाल के बारे में बनाये जायँ किसी वर्तमान आयुर्वेदिक या यूनानी अस्पताल या शकाखाने का और इसकी इमारत और सामान का खर्च उठाये और उसको अधिकार होगा कि वह चिकित्सा के ऊपर बताये गये तरीकों में से एक या एक से अधिक तरीकों के लिये कोई नया अस्पताल या शकाखाना खोले और ठीक ढंग से चलाये।

(२) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रान्तीय सरकार ऐसे स्कूलों अस्पतालों और शकाखानों के लिये उतनी आर्थिक सहायता देगी जितनी कि नियत की जाय।

**कुछ गाँव-सभाओं के समूह में प्राइमरी स्कूल  
और अस्पताल या शकाखाना खोलना**

२०—जब पड़ोसी की कुछ गाँव सभाओं के क्षेत्र में कोई प्राइमरी स्कूल या आयुर्वेदिक या यूनानी अस्पताल या शकाखाना न हो, यदि नियत अधिकारी ऐसी आज्ञा दे, तो वहाँ की गाँव-पञ्चायत मिल कर कोई ऐसा स्कूल, अस्पताल या शकाखाना खोल लेंगे और उसका खर्च उठावेंगे और उसे ढङ्ग के अनुसार उसका प्रबन्ध किया जायगा और उन्हें आर्थिक सहायता दी जायगी जो इस स

नियत किया गया हो प्रांतीय सरकार और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसे स्कूल, अस्पताल या शस्त्राखाना के लिये ऐसी आर्थिक सहायता देगी जो उनके लिये नियत की जाय ।

## सरकारी कर्मचारियों को सहायता

२१—किसी गाँव-पञ्चायत को मान्य होगा कि वह, यदि प्रांतीय सरकार कोई ऐसी आज्ञा दे और जहाँ तक सम्भव हो, अपनी सीमा के अन्दर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके काम में सहायत दे ।

### गाँव पञ्चायतों की ओर से प्रार्थना पत्र और सिफारिशें

२२—किसी गाँव-पञ्चायत को अधिकार होगा कि वह उपयुक्त अधिकारी के पास—

( क ) अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वालों की भलाई के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र दे; और

( ख ) ऐसी गाँव-पञ्चायत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर काम करने वाले सिंचाई-विभाग में पटरौल, पटवारी या मुखिया की नियुक्त, बदली या चरखास्तगी के लिये सिफारिश करे ।

### बुद्ध अफसरों के दुराचरण के बारे में जांच करने

### और रिपोर्ट देने का अधिकार

२३—किसी गाँव-पञ्चायत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी व्यक्ति से अमीन, मजकूरी, टीका लगाने वाला, सिपाही (कान्स्टेबुल) पटवारी, सिंचाई-विभाग के पटरौल या किसी सरकारी विभाग के चपरासी के विरुद्ध सरकारी कर्तव्यों के पालन करने में, दुराचरण के बारे में शिकायत मिलने पर, ऐसी पञ्चायत को, यदि प्रकट रूप से प्रमाण हो, अधिकार होगा कि वह उस शिकायत को अपनी रिपोर्ट के साथ उपयुक्त अधिकारी के पास भेज दें । उस



अधिकारी के लिये मान्य होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने पर, जो करना आवश्यक हो, उपयुक्त कार्यवाही करे और उसके नतीजे की सूचना गाँव-पञ्चायत को भेज दे।

नोट—सरकारी कर्मचारियों में जो ( misconduct ) घूस-खोरी, रुपया ऍटने की कोशिश और तङ्ग करते और उसके न मिलने पर काम में लापरवाही करते इत्यादि बातों की गाँव पञ्चायत रिपोर्ट उपयुक्त अफसर को कर सकती है।

## मालिकों के लिये टैक्स और दूसरे महसूल करने

### के बारे में मुआहिदा करने का अधिकार

२४—किसी गाँव-पञ्चायत को अधिकार होगा कि वह नियत तरीके पर और किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर हो—

(क) प्रान्तीय सरकार की ओर से तहसील-वसूल के खर्च के रूप में ऐसी रकम दिये जाने पर, जो नियत की जाय, ऐसे कोई टैक्स या महसूल को, जो श्रीमान् सम्राट को वाजिबुल अदा हो वसूल करने के लिये प्रान्तीय सरकार से मुआहिदा करे, या

(ख) किसी मालिक या सभी मालिकों की ओर से तहसील वसूल के खर्च के रूप में ऐसी रकम दिये जाने पर, जो नियत की जाय, उसको या उनकी ओर से लगान वसूल करने के लिये सभी मालिकों या उनमें से किसी एक मालिक से मुआहिदा करे।

### कर्मचारी

२५—(१) किसी गाँव-पञ्चायत के लिये मान्य होगा कि यह नियत नियमों के अनुसार एक सेक्रेटरी नियुक्त करे और नियत अधिकारी के पास उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो वह पूरे समय

के लिये या कुछ समय के लिये रखना चाहती हो. वेतन और भत्ते. यदि कोई हो. जो उनको दिये जायेंगे और उनमें से हर एक कामों के बारे में अपने प्रस्ताव भेजें। नियत अधिकारी को अधिकार होगा कि वह नियत तरीके पर प्रस्तावों को स्वीकार करे. उनमें संशोधन करे या उन्हें अस्वीकार करे। गाँव-पञ्चायत को अधिकार होगा कि तब वह नियत अधिकारी द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्त करे।

(२) नियत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की पावन्दी के साथ, गाँव-पञ्चायत उपरोक्त योजना के कोई परिवर्तन कर सकती है।

(३) उपधार (१) में भले हो कोई बात हो, गाँव-पञ्चायत आकस्मिक आवश्यकता के समय नियत अधिकारी की स्वीकृति लिये बिना भी किसी कर्मचारी को ऐसी अवधि के लिये नियुक्त कर सकती है जो तीन महीने से अधिक न हो।

(४) गाँव-पञ्चायत के किसी कर्मचारी को नियुक्त करने, अलग करने या बर्खास्त करने के अधिकार को पञ्चायत प्रयोग में लायेंगी, लेकिन दंड देने, अनुशासन सम्बन्धी कारवाई करने या तरक्की देने के अधिकार पञ्चायत के किसी ऐसे अधिकारी को दिये जा सकते हैं, जो निर्मात किया जाय पर शर्त यह है कि ऐसे अफसर के हुक्म के विरुद्ध अपील नियत तरीके के अनुसार गाँव-पञ्चायत के सामने हो सकेगी।

### व्यक्तिगत मेम्बरों का अधिकार

२६—किसी गाँव-पञ्चायत के मेम्बर को अधिकार होगा कि वह नियत तरीके के अनुसार, गाँव-पञ्चायत की शासन प्रबन्ध-सम्बन्धी बातों के बारे में कोई प्रस्ताव पेश करे और सभापति या उपसभापति से उनके बारे में सवाल करे।

**गांव-पञ्चायत के धन या सम्पत्ति की हानि, उसके**

**अपव्यय या वेजा इस्तेमाल के लिये सज़ा**

२७—( १ ) इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई गांव-पञ्चायती या संयुक्त-कमेटी या किसी ऐसी दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर गांव-पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, उसके अपव्यय या वेजा इस्तेमाल के लिये उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, या वेजा इस्तेमाल उसकी लापरवाही या दुराचरण का प्रत्यक्ष फल हो, जब कि वह गांव-पञ्चायत की संयुक्त कमेटी का मेम्बर था और गांव-पञ्चायत, नियत अधिकारी की पहिले से स्वीकृति लेकर, उसके विरुद्ध मुआवजे के लिये नालिश दायर करे।

( २ ) यदि नियत अधिकारी उपधारा ( १ ) के अधीन नालिश दायर करने की स्वीकृति दे दे या स्वीकृति देने से मना कर दे, तो सम्बन्धित मेम्बर या गांव-पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी स्वीकृति या अस्वीकृति की तारीख से ३० दिन के भीतर प्रान्तीय सरकार या ऐसे अधिकारी को जिसके यहाँ अपील की जा सकती हो उपरोक्त स्वीकृति या अस्वीकृति के विरुद्ध अपील कर सकती है।

( ३ ) प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार होगा कि उपधारा ( १ ) में बताई गई किसी नालिश को स्वयं दायर करे।

**मेम्बर और कर्मचारी जन-सेवक समझे जायेंगे**

२८—किसी पंचायती अदालत या गांव-पंचायत या संयुक्त-कमेटी या इस ऐक्ट के अधीन बनाई गई किसी दूसरी कमेटी का प्रत्येक मेम्बर या कर्मचारी भारतीय दण्ड-संग्रह की धारा २१ के अन्तर्गत जन-सेवक (Public Servant) समझा जायगा।

**सन् १८६० ई० का ऐक्ट नं० ४५ कमेटी**

२९—नियत शर्तों की पाबन्दी के साथ कोई गांव-पंचायत अपने नियत कर्त्तव्य का किसी प्रकार के कर्त्तव्यों को पूरा करने में सहायता

करने के लिये, एक कमेटी बना सकती है और ऐसी कमेटी को अपने ऐसे अधिकार दे सकती है जो ऐसी सहायता देने के लिये आवश्यक हों।

### संयुक्त कमेटी

३०—( १ ) ऐसे नियमों की पाबन्दी के साथ जो नियत किये जायें, दो या उससे अधिक गांव-सभाएं कोई ऐसे कार वार करने के लिये जिसमें उनका संयुक्त रूप से हित हो, एक लिखित दस्तावेज के द्वारा अपने प्रति-निधियों की एक संयुक्त कमेटी नियुक्त करने के लिये आपस में सम्मिलित हो सकती है और वे—

( क ) ऐसी कमेटी को, ऐसी शर्तों के साथ जो वे ठीक समझें, अधिकार दे सकती है कि वह किसी संयुक्त इमारती काम के निर्माण और उसे बनाये रखने के सम्बन्ध में और ऐसे अधिकार नियत करने के लिये जो ऐसी योजना के सम्बन्ध में कोई ऐसी सभा प्रयोग में ला सकती है, एक ऐसी योजना तैयार करे जो ऐसी हर गांव सभा को मान्य होगा।

( ख ) ऐसी कमेटी के जारी रहने, उसके मेम्बरों के पद पर रहने की अवधि और उसकी कारवाइयां करने के ढंग और पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है।

( २ ) इस धारा के अधीन काम करने वाली गांव-सभाओं के बीच यदि कोई मतभेद पैदा हो जाय, तो यह मतभेद नियत अधिकारी के हवाले किया जायगा और इस पर उसका निष्पक्ष अन्तिम समझा जाय।

### अधिकारों का सौंपना

३१—गांव-सभा के कुल कर्तव्यों, अधिकारों और दूसरे कामों को सिवाय उनके, जिनका उल्लेख अध्याय ३ और धारा ३० और

११४ में किया गया है गाँव-पंचायत स्वयं प्रयोग में लायेंगी, इस्तेमाल करेगी या पालन करेगी और दूसरी प्रकार न प्रयोग में लायेगी न इस्तेमाल करेगी, न पालन करेगी।

### गाँव-कोष (फंड)

३२—(१) हर गाँव-सभा के अधिकार में एक गाँव-कोष ( फंड ) होगा जिसे गाँव-पंचायत धारा १३ के अधीन पास किये गये वजट में दी हुई रकमों की पावन्दी के साथ, इस ऐक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में होने वाले खर्चों को उठाने के लिये इस्तेमाल करेगी।

( २ ) गाँव-कोष (फंड) में निम्नलिखित रकमों जमा होंगी :—

( क ) इस ऐक्ट के अधीन लगाये गये किसी टैक्स से वसूल की हुई रकमें;

( ख ) ऐसी कुल रकमें जो प्रान्तीय सरकार ने गाँव-सभा के सुपुर्द कर दी हों;

( ग ) वकाया यदि कोई हो, जो ऐसी गाँव-पञ्चायत के खाते में जमा हो जो “गाँव-पञ्चायत ऐक्ट” के अधीन पहले से घनी हो;

( घ ) ऐसी सब रकमें जो किसी अदालत के हुक्म से गाँव-कोष (फंड) में जमा की जायें;

( ङ ) ऐसी कुल रकमें जो धारा १०४ के अधीन प्राप्त हों;

( च ) गाँव-पञ्चायत के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ कूड़ा-करकट, घूर, गोबर या पांस तथा मरे हुये जानवरों की लाशें इत्यादि के बेचने से जो आमदनी हो;

( छ ) नजूल की भूमि के लगान का या उससे होने वाला दूसरी आमदनियों का वह भाग जिसके वारं में प्रान्तीय सरकार ने गाँव-कोष (फंड) में जमा करने के आदेश किये हों;

( ज ) ऐसी रकमें जो गाँव-कोष ( फंड ) के लिये कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या दूसरा स्थानीय अधिकारी ( लोकल अथॉरिटी ) दे ।

( भ ) वे सब रकमें जो ऋण या दान के रूप में प्राप्त हों;

( न ) ऐसी दूसरी रकम जो प्रान्तीय सरकार के किसी साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा गाँव-कोष ( फंड ) के लिये दे दी जायें;

( त ) वे सब रकमें जो धारा २४ के अधीन या किसी दूसरे कानून के अधीन गाँव-पञ्चायत का किसी व्यक्ति या कारपोरेशन या प्रान्तीय सरकार से मिली हों ।

( ३ ) इस धारा के किसी आदेश से किसी गाँव-सभा के किसी ऐसे दावित्य पर प्रभाव न पड़ेगा जो किसी ऐसे ट्रस्ट के कारण उस पर आया हो जो कानून द्वारा उसके सुपुर्द किया गया हो या जिसे उसने स्वयं स्वीकार किया हो ।

गाँव-पञ्चायत जो वसूली प्रान्तीय सरकार अथवा मालिकों की ओर से करे उसको गाँव-कोष जमा करेगा ।

## अध्याय ५

### भूमि, गाँव-कोष (फण्ड) और सम्पत्ति प्राप्त करना

१३—जब किसी गाँव-सभा को या ऐसी बहुत सी गाँव-सभाओं को जो धारा २० या ३० के आदेशों के अधीन सम्मिलित हो गई हों, इस ऐक्ट के किसी उद्देश्य के लिये, किसी भूमि की आवश्यकता हो तो वह सभा या वे सभायें पहिले उस भूमि को आपसी बातचीत के द्वारा प्राप्त करने की दोशिश करेगी या करेंगी और यदि सम्बन्धित दोनों पक्ष आपस में कोई समझौता न कर सकें तो ऐसी गाँव-सभा या गाँव सभायें कलक्टर को नियत फार्म में उस भूमि को प्राप्त करने के लिये दरखास्त दे सकती हैं या दे सकती हैं और कलक्टर

ऐसी भूमि को ऐसी गाँव-सभा या गाँवसभाओं के लिये प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में शब्द 'भूमि' में ऐसे लाभ जो भूमि से प्राप्त हों और ऐसी चीजें सम्मिलित हैं जो 'भूमि' से लगी हुई हों या किसी ऐसी चीज से स्थायी रूप से बन्धी हुई हों जो भूमि से लगी हुई हों।

**सम्पत्ति, जिस पर गाँव-सभा का अधिकार होगा**

३४—( १ ) ऐसी विशेष शर्तों की पाबन्दी करते हुये जिन्हें प्रान्तीय सरकार नियत करे, गाँव-सभा के अधिकार क्षेत्र के अन्दर स्थित सारी सरकारी सम्पत्ति गाँव-सभा की सम्पत्ति होगी या उसके अधिकार में होगी और यह सम्पत्ति, ऐसी दूसरी सारी सम्पत्तियों के सहित जो गाँव-सभा के अधिकार में आ जाय, उसके देखरेख में या प्रबन्ध में या उसके नियन्त्रण में रहेगी।

( २ ) सारे बाजारों और मेलों या उनके सेपे भाग का, जो सरकारी भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और नियन्त्रण गाँव-पंचायत करेगी और गाँव-सभा गाँव कोष ( फंड ) के नाम में इन बाजारों और मेलों के सम्बन्ध में नियत या लगाये हुये कुल महसूल वसूल करेगी।

**दावों का निवटाया जाना**

३५—जब धारा ३४ में बताई हुई कसी सम्पत्ति की मिल्कियत ( स्वामित्व ) के बारे में गाँव-सभा और किसी व्यक्ति के बीच झगड़ा हो, तो गाँव-पंचायत उक्त व्यक्ति को अपना वयान देने के लिये उचित अवसर देगी और उसके बाद यह निर्णय करेगी कि उस सम्पत्ति को गाँव-सभा की मिल्कियत ( स्वामित्व ) समझी जाय या नहीं।

## ऋण लेने का अधिकार

३६—नियत अधिकारी की आज्ञा लेकर और ऐसी सब शर्तों की पाबन्दी करते हुये जो नियत की गई हों, गाँव-सभा इस ऐक्ट के किसी भी उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रान्तीय सरकार से ऋण ले सकती है।

## टैक्स जो लगाये जा सकते हैं

३७ नियत नियमों और ऐसे आदेशों की पाबन्दी के साथ जो प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में बनाये हों, कोई गाँव सभा निम्नलिखित टैक्स लगा सकती है :—

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १७, सन् १९३९ ई०

(क) एक टैक्स ऐक्ट कब्जा आराजी संयुक्त प्रान्त, ऐक्ट नं० १७ सन् १९३९ ई० के आदेशों के अधीन अदा किये जाने वाले लगान पर, जो ऐसे लगान के एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा, और उक्त टैक्स उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से वसूल किया जा सकेगा, जो उस पर अलग-अलग या सम्मिलित रूप से काश्तकाराना (कृषि-सम्बन्धी) कब्जा रखता हो या रखते हों या जिसको या जिनको उससे सायर की आमदनी मिलती हों।

पर शर्त यह है कि यदि कोई सीर या किसी दूसरी आराजी (भूमि) का शिकमी असामी किसी आराजी पर काश्त करता हो तो इस धारा के अधीन जो टैक्स की रकम लगाई जायगी वह ऐसे शिकमी असामी और सीर के मालिक या असल असामी से, जैसी भी स्थिति हो. ३१४ और ३१४ के अनुपात से क्रमशः वसूल की जायगी।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १७, सन् १९३९ ई०

(ख) एक टैक्स उस लगान पर जो कोई मालिक या



मातहतदार ऐसी आराजी के सम्बन्ध में वसूल करता हो जिसकी व्याख्या ऐक्ट कब्जो संयुक्त प्रान्त, सन् १८३६ ई० की धारा ३ में की गई है, और जो ऐसे लगान के ३ पाई प्रति रुपया से अधिक न होगा। उपरोक्त टैक्स उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से क़ाबिल अदा होगा जो ऐक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रांत, ऐक्ट न० ३ सन् १८०१ ई० की धारा २२ के आदेशों के अनुसार ऐसी आराजी के अलग-अलग या संयुक्त रूप से मालिक या मातहतदार की हैसियत से क़ब्जा रखने वाले दर्ज हों।

### संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० ३, सन् १९०१ ई०

( ग ) एक टैक्स ऐसी आराजी सीर या खुदकाशत को मानती हुई जमावन्दी की मालियत पर जिसका हिसाब ऐक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रान्त सन् १८०१ ई० की धारा ६३ ( व ) के शर्तिया वाक्य-खंड के अनुसार लगाया जायगा। उपरोक्त टैक्स हर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से क़ाबिल अदा होगा जो ऐक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रांत, सन् १८०१ ई० की धारा ३२ के आदेशों के अनुसार ऐसी सीर के अलग-अलग या संयुक्त रूप से मालिक या मातहतदार की हैसियत से क़ब्जा रखने वाले दर्ज हों, और यह टैक्स एक आना प्रति रुपया से अधिक न होगा।

( घ ) एक टैक्स व्यापार, कारवार और पेशों पर जो ऐसी दर से अधिक न होगा जो नियत की जाय।

( ङ ) एक टैक्स उन इमारतों पर जो ऐसे व्यक्तियों की मिल्कियत ( स्वामित्व ) में हों जो ऊपर दिये हुये कोई टैक्स अदा न करते हों, और जो ऐसी दर से अधिक न होगा जो नियत की जाय।

( २ ) उपधारा ( १ ) के वाक्य खण्डों (क), (ख) या (ग) के अधीन कोई टैक्स अकेला न लगाया जायगा, और यदि कोई टैक्स ऊपर दिये हुए तीनों वाक्यखण्डों में से किसी के अधीन लगाया जायगा तो दूसरे दोनों वाक्यखण्डों के अधीन भी टैक्स लगा दिये जायेंगे और तीनों वाक्यखण्डों के अधीन लगाये हुये टैक्सों की दरों में वही पारस्परिक अनुपात होगा जो अधिक से अधिक नियत की गई दरों में हो ।

स्पष्टीकरण यदि कोई गाँव-सभा उपधारा ( १ ) के वाक्य-खण्ड ( क ) और ( ग ) के अधीन आध आना प्रति रुपया के हिसाब से एक टैक्स लगाती है तो उक्त उपधारा के वाक्य-खण्ड ( ख ) के अधीन एक टैक्स उस लगान पर भी जो आराजी के मालिकों को क़ाबिल अदा होगा १।४ आने प्रति रुपया के हिसाब से लगाया जायगा ।

( ३ ) उपधारा ( १ ) के अधीन टैक्स ऐसे तरीके पर लगाये, तशखीस और वसूल किये जायेंगे और ऐसे समय पर अदा या वसूल होंगे जो नियत किये जायें ।

### मतालवों की वसूली कोष (फंड) की रक्षा और हिसाब

३८—नियत किये हुए नियमों की पाबन्दी के साथ गाँव-पञ्चायत, पञ्चायत के टैक्सों और मतालवों को वसूली, कोष ( फंड ) की रक्षा और हिसाब-किताब रखने का प्रबन्ध करेगी ।

३९—( १ ) पञ्चायती अदालत के खर्च उस क्षेत्र के हर यूनिट के गाँवकोष ( फंड ) से बराबर अनुपात से वसूल किये जायेंगे ।

( २ ) ऐसी सारी रकमें जो किसी मुकद्दमे, नालिश या क़ानूनी कार्रवाई के सिलसिले में कोर्ट फ़ीस के तौर पर वसूल की गई हों या जो जुर्माने के तौर पर उन मुकद्दमों में वसूल की गई हों ।

जिनकी पञ्चायती अदालत ने सुनवाई की हो और जिनका उसने फैसला किया हो, प्रान्तीय सरकार बराबर अनुपात से उन गाँव-सभाओं को दे देगी जो उस पञ्चायती अदालत के अधिकार-क्षेत्र में हों।

## हिसाब की जाँच

४०—नियत नियमों के अनुसार हर गाँव सभा के हिसाबों की हर वर्ष जाँच की जायगी।

४१—( १ ) [ क ] प्रत्येक गाँव-पञ्चायत प्रति वर्ष आगामी वर्ष के लिए जो हर पहली अप्रैल से प्रारम्भ होगा अपने आय-व्यय का अनुमानित बजट तैयार करके गाँव-सभा की 'खरीफ' फसल की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

[ ख ] प्रत्येक गाँव-पञ्चायत अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे गाँव-सभा की 'रबी' की बैठक में प्रस्तुत करेगी जिस में वास्तविक और अनुमानित आय-व्यय का हिसाब उस वर्ष के लिये दिया होगा जो बैठक से पहिले गत मार्च की ३१ तारीख को समाप्त हुआ।

( २ ) गाँव-सभा नियत ढङ्ग के अनुसार उस बजट को जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाय स्वीकार कर सकती है या उस पर फिर से विचार करने के लिये उसे ऐसे आदेशों के साथ जिम्मा देना वह उचित समझे, गाँव-पञ्चायत के पास वापस भेज सकता है और इसी प्रकार का रिपोर्ट या किसी दूसरे मामले के बारे में सकारिशी प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकती है।

( ३ ) यदि बजट फिर से विचार करने के लिये गाँव-पञ्चायत के पास भेज दिया जाय, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो नभापति गाँव-सभा की एक असाधारण बैठक करेगा जो उक्त वार्षिक बैठक की तारीख से दो सप्ताह के अन्दर होगी और

गाँव-पञ्चायत उक्त बैठक में उस वजट को ऐसे संशोधनों के साथ जो सभा के आदेशों के अनुसार आवश्यक हों फिर से प्रस्तुत करेगी और तब गाँव-सभा नियत ढंग के अनुसार वजट को स्वीकृत करेगी ।

इस सम्बन्ध में बनाये हुये नियमों के अधीन वजट नियत अधिकारी की स्वीकृति के बाद कार्यान्वित होगा और कोई गाँव पञ्चायत नियत अधिकारी की स्वीकृति से वजट में परिवर्तन या संशोधन किये बिना वजट की किसी मद में उस रकम से अधिक खर्च कर सकती है जो उसी मद में स्वीकृत की गई हो ।

## अध्याय ६

### पञ्चायती अदालत

४२ - प्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी जिले को ऐसे क्षेत्रों में बाँटेगा जिनमें गाँव सभाओं की अधिकार-सीमा के अधीन उतने स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित हों जितने उसके राय में आवश्यक हों और प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के लिये एक पञ्चायती अदालत स्थापित करेगी या करेगा ।

पर शर्त यह है कि हर इलाके में गाँव-सभाओं के क्षेत्र जहाँ तक सम्भव हो, एक दूसरे से मिले हुये हों ।

### पञ्चायती-अदालत का विधान

४३ - किसी क्षेत्र की प्रत्येक गाँव-सभा उक्त क्षेत्र की पञ्चायती अदालत में पञ्चों की हैसियत से काम करने के लिये नियत योग्यता रखने वाले पाँच ऐसे प्रौढ़ चुनेगी जो स्थायी रूप से उसके अधिकार-क्षेत्र के भीतर रहने वाले हों । किसी क्षेत्र के

सारे गाँव-सभाओं के इस प्रकार चुने हुये पञ्चों का पञ्चमण्डल होगा ।

### सरपञ्च का चुनाव

४४—धारा ४३ के अधीन चुने हुए सब पञ्च पञ्चायती अदालत के सरपञ्च का काम करने के लिये अपने में से एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो कार्यवाहियां लिखने की योग्यता रखता हो ।

पर शर्त यह है कि ऐसे चुनाव से पैदा होने वाला कोई मगड़ा ( निर्णय के लिये ) उस नियत अधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा और जिस पर किसी कानूनी अदालत में आपत्ति न की जा सकेगी ।

### पञ्चायती अदालतों की अवधि

४५—प्रत्येक पञ्च अपने चुनाव की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा ।

### पदग्रहण की शपथ

४६—धारा ४३ के अधीन चुने हुये प्रत्येक पञ्च को चुने जाने के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो, नियत ढङ्ग के अनुसार पद-ग्रहण की शपथ लेनी पड़ेगी ।

### इस्तीफ़े

४७—कोई पंच अपने ओहदे का इस्तीफ़ा नियत अधिकारी को दे सकता है ।

### अलग किया जाना

४८—( १ ) नियत अधिकारी नियत ढङ्ग के अनुसार नियत किये हुये कारणों के आधार पर किसी पंच को किसी भी समय अलग कर सकता है ।

( २ ) किसी पञ्च को जिसे उपधारा ( १ ) के अधीन अलग किया गया हो. ३ साल तक दुबारा पंच चुने जाने का अधिकार न होगा ।

४६—( १ ) सरपंच प्रत्येक मुकदमे, नालिश या कार्रवाई के लिये पञ्च-मंडल ( पैनल ) में से पांच पंचों का एक बेंच नियुक्त करेगा, पर शर्त यह है कि बेंच में कम से कम एक पंच ऐसा व्यक्ति होगा जो शहादतों और कार्रवाइयों को लिखने की योग्यता रखता हो ।

( २ ) प्रत्येक ऐसी बेंच में एक पंच ऐसा होगा जो गाँव-सभा के उस इलाक़े का रहने वाला हो जिसमें वह व्यक्ति रहता हो जो किसी नालिश या कानूनी कार्रवाई में मुद्दई हो या किसी मुकदमे में मुस्तगीस हो और इसी तरह एक पंच ऐसा होगा जो गाँव-सभा के उस क्षेत्र में रहता हो जिसमें मुद्दाअलह या अभियुक्त रहता हो और तीन पंच ऐसे होंगे जो गाँव-सभा के उन क्षेत्रों के रहने वाले हों जिनमें दोनों फरीकों में से कोई न रहता हो, पर शर्त यह है कि पुलिस के मुकदमों में एक पंच ऐसा होगा जो गाँव-सभा के उस क्षेत्र में रहता हो जहाँ अपराध किया गया हो और एक पंच गाँव-सभा के उस क्षेत्र का रहने वाला होगा जिसमें अभियुक्त रहता हो और तीन पंच उन क्षेत्रों के रहने वाले होंगे जो ऊपर बताये गये क्षेत्रों के अलावा दूसरी जगह रहते हों ।

( ३ ) कोई पंच या सरपंच किसी ऐसी नालिश, मुकदमे या कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, जिसमें वह या उसका निकट सम्बन्धी या मालिक या नौकर या रोज़गार में उसका सामी एक पक्ष में हो या जिसमें उनके से किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो ।

( ४ ) इस धारा की शर्तों के होते हुए प्रान्तीय सरकार किसी भगड़े का निर्णय करने के लिये जो विभिन्न पक्षों या भिन्न-

भिन्न क्षेत्रों की गाँव-सभाओं के बीच में पैदा हो या किसी अन्य प्रयोजन के लिये नियमों के अनुसार खास बेंचों का विधान नियत कर सकती है।

**इतिफाकिया खाली होने वाली जगहों का भरा जाना**

५७—यदि किसी पंच की जगह उसकी मृत्यु हो जाने, उसके अलग किये जाने या इस्तीफा दे देने के कारण खाली हो तो वह जगह धारा ४६ में दिये हुये ढङ्ग के अनुसार भरी जायगी और यदि जगह खाली करने वाला पंच सरपंच हो तो धारा ४७ के अनुसार एक सरपञ्च चुना जायगा।

**अधिकार-सीमा का क्षेत्र**

५१—(१) दण्ड-विधि संग्रह एक्ट न० ५ सन् १८६८ ई० में किसी बात के होते हुए भी इस ऐक्ट के अधीन दायर किया हुआ प्रत्येक मुकद्मा उस क्षेत्र की पञ्चायती अदालत के सामने दायर किया जायगा जिसमें अपराध किया गया हो।

नोट—देखिये धारा ४३ और ४४ जिसके अनुसार ५३ और सरपञ्च चुने जायेंगे।

**सन् १९०८ ई० का ऐक्ट न० ५**

(२) दीवानी नियम संग्रह सन् १९०८ ई० में भले ही कोई वान ही. इस ऐक्ट के अधीन दायर किया हुआ प्रत्येक मुकद्मा उस क्षेत्र की पञ्चायती अदालत के सामने दायर किया जायगा जिसमें मुद्दाअलेह या यदि एक से अधिक मुद्दाअलेह हों तो उनमें से कोई एक मुद्दाअलेह साधारणतया रहता हो या मुकद्मा दायर करने के समय वहां कार-बार करता हो, भले ही उसके कार्य का कारण कहीं पैदा हुआ हो!

**संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट न० ३ सन् १९०१ ई०**

(३) ऐक्ट मालगुजारी संयुक्त प्रांत एक्ट न० ३ सन् १९०१ ई०

में भले ही कोई बात हो तहसीलदार धारा ७० के अधीन प्रत्येक कार्रवाई को उस स्थानीय क्षेत्र की पञ्चायती अदालत के सुपुर्द करेगा जिसमें सम्बन्धित आराजी स्थित हो और पञ्चायती अदालत ऐसी कार्रवाइयों का नियत ढङ्ग से फ़ैसला करेगी।

पर शर्त यह है कि जहां एक से अधिक पञ्चायती अदालतों के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित आराजी से सम्बन्ध हो वह उस पञ्चायती अदालत की अधिकार-सीमा में होगी जिसमें दर्ज किया हुआ असामी या मालिक साधारणतया रहता हो, या यदि वह उनमें से किसी में न रहता हो तो तहसीलदार उन कार्रवाइयों की उन क्षेत्र की पञ्चायती अदालत को सुपुर्द करेगा जिसमें आराजी का अधिक भाग स्थित हो।

५८—( १ ) नीचे दी हुई धाराओं के अधीन यदि अपराध किसी पञ्चायती अदालत की अधिकार-सीमा में किये जायें, तो उनकी और साथ-साथ ऐसे अपराधों के करने के लिये जो प्रोत्साहन दिये जायें या उनके करने के लिये जो प्रयत्न किये जायें तो उनकी सुनवाई का अधिकार ऐसी पञ्चायती अदालत का होगा।

सन् १८६० ई० का ऐक्ट नं० ४५

( क ) भारतीय दंड विधान. सन् १८६० ई० की धारायें १४०, १६०, १७२, १७४, १७६, २७७, २७८, २८३, २८५, २८६, २८८, २९०, २९४, ३२३, ३३४, ३३६, ३४१, ३४२, ३४६, ३४७, ३४८, ३७४, ३७६, ४०३, ४११, ( जब कि चोरी या रावन किये हुये माल का, जहाँ तक कि धारा ३७६, ४०३ और ४११ का सम्बन्ध है, मूल्य ५० रुपया से अधिक न हो ) ४०६, ४२८, ४३०, ४४७, ४४८, ५०४, ५०६, ५०८ और ५१०।

नोट—भूमिदा में इन धाराओं के अर्थ देखिये,

नोट—सार्वजनिक मार्ग पर लड़ाई, सम्मन तामील न करना या



उल्लंघन करना, अश्लील क्रिया तथा गीत, मार-पीट, हमला, किसी को वन्द करने के लिये हमला, जबरदस्ती बेगार ५० रुपये से कम मूल्य की चोरी, भूमि व मकान में अनाधिकार प्रवेश वा अधिकार कर लेना, धमकी, स्त्री की लज्जा अपहरण की चेष्टा आदि पंचायत तै करगी।

सन् १८७१ ई० का ऐक्ट नं० १,

(ख) जानवरों के अनाधिकार प्रवेश ऐक्ट, सन् १८७१ ई० की धारा २० से २४ तक,

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० १, सन् १९२६ ई०

(ग) संयुक्त प्रान्त की डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की प्रारम्भिक शिक्षा के ऐक्ट, नं० १ सन् १९२६ ई० की धारा १० की उपधारा (१);

(घ) इस ऐक्ट या इस ऐक्ट के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन कोई अपराध,

सन् १८६० ई० का ऐक्ट नं० ३

(ङ) आम मजमे में किमारवाजी (सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने) के ऐक्ट, सन् १८६७ ई० की धारा ३, ४ और ७ के अधीन कोई अपराध;

(च) प्रान्तीय सरकार द्वारा घोषित किये गये किसी दूसरे कानून के अधीन कोई दूसरा अपराध जिसकी सुनवाई का अधिकार किसी पञ्चायती अदालत को हो।

सन् १८६६ का ऐक्ट नं० ४५

(२) कोई मुक्रद्मा जिसका सम्बन्ध भारतीय दंड-विधान, सन् १८६० ई० की धारा १४३, १४५, १५१, या १५३ के अधीन किसी अपराध से हो और जो किसी अदालत में विचाराधीन हो। सुनवाई के लिये पंचायती अदालत को भेजा जा सकता है, यदि ऐसी अदालत की राय में अपराध गंभीर न हो।

## शान्ति बनाये रखने के लिये ज़मानत

५३—( १ ) जब किसी पंचायती अदालत के सरपंच के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति की ओर से शान्ति भङ्ग किये जाने या सार्वजनिक शान्ति में बाधा डालने की आशंका हो तो वह ऐसे व्यक्ति से ज़वाब तलब कर सकता है कि वह कारण बताये कि क्यों न उससे ऐसी अवधि तक के वास्ते शान्ति रखने के लिये जो १५ दिन से अधिक का न हो, ऐसा मुचलका-ले लिये जाय जो १०० रुपये से अधिक का न हो, और जो जामिनों सहित या जामिनों के बिना हो सकता है।

( २ ) सरपंच को मान्य होगा कि ऐसी नोटिस जारी करने के बाद तीन दिन के भीतर एक बेंच क़ायम करे कि वह मामले की कार्रवाई करे। पर शर्त यह है कि बेंच का कम से कम एक पंच उस गाँव-सभा का हो जिसमें ऐसा व्यक्ति रहता हो।

बेंच को अधिकार है कि वह उस आज्ञा को बहाल रखे या ऐसे व्यक्ति या ऐसे गवाहों का बयान सुनने के बाद जिन्हें वह पेश करना चाहें नोटिस को मंसूख कर दे।

## दंड

५४—( १ ) कोई पंचायती अदालत कारावास का दण्ड नहीं दे सकती।

( २ ) कोई पंचायती अदालत जुर्माना कर सकती है जो १०० रुपये से अधिक न होगा, लेकिन वह जुर्माना न अदा किये जाने की दशा में कारावास का दण्ड नहीं दे सकती।

## नालिशों की सुनवाई इत्यादि

५५. कोई अदालत किसी ऐसे दावे या नालिश की सुनवाई न करेगी जो इस ऐक्ट के अधीन पंचायती अदालत

के सुनने के काविल हो जब तक कि धारा ८५ के अधीन सब-  
डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मुन्सिफ ने कोई आज्ञा न दी हो।

नोट—धारा ८५ में पंचायती अदालतों के सम्बन्ध में हाकिम  
परगना व मुन्सिफों के अधिकार दिये गये हैं।

## कुछ सूक्तों में फौजदारी की कार्यवाइयों को पञ्चायती अदालत में भेजना

५३— यदि फौजदारी के किसी मुकदमे के बीच में जो किसी  
मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो किसी समय भी यह मालूम हो कि  
इस मुकदमे की सुनवाई किसी पंचायती अदालत को करना  
चाहिये तो वह उस मुकदमे को तुरन्त ही उस पंचायती  
अदालत के पास भेज देगा जो मुकदमे की सुनवाई आरम्भ से  
करेगी।

## इस्तग़ासों को सरसरी तौर पर खारिज करना

५७— पंचायती अदालत किसी भी इस्तग़ासे को खारिज  
कर सकती है यदि सुस्तगीस का बयान और ऐसी गवाही जिसे  
वह पेश करे, लेने के बाद उसकी इस बात का विश्वास हो जाय  
कि वह इस्तग़ासा पंशान करने के लिये दायर किया गया है  
या निरर्थक और झूठा है।

## इस्तग़ासे को वापस करना

५८— यदि पञ्चायती अदालत को किसी समय भी यह मालूम  
हो :—

( क ) कि उसको उस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार नहीं  
है जो उसके सामने पेश है या;

( ख ) कि वह अपराध ऐसा है जिसके सम्बन्ध में वह उचित  
दण्ड नहीं दे सकती, या

( ग ) कि वह मुकदमा इस तरह का है या इतना पेचीदा है के उसकी सुनवाई किसी वाजान्त अदालत को करनी चाहिये तो वह उस मुस्तगीस को वह इस्तगासा वापस कर देगी और इस बात का आदेश करेगी कि वह उसको ऐसे मज-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जिसे ऐसे मुकदमे की सुनवाई का अधिकार हो ।

नोट—दण्ड-विधि-संग्रह के धारा २५३ में भी ऐसी व्यवस्था दी है ।

कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई पञ्चायत नहीं कर सकती

५६ - कोई पञ्चायती अदालत किसी ऐसे अपराध की सुनवाई नहीं करेगी जिसमें कि मुलजिम ( अभियुक्त ) को:

( क ) पहिले कभी किसी अपराध के लिये तीन वर्ष या उससे अधिक का दोनो में किसी भी प्रकार के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

( ख ) पहिले कभी किसी पञ्चायती अदालत से चोरी के अपराध में जुर्माना का दण्ड दिया हो, या

सन १९११ ई० का ऐक्ट न ३

( ग ) मुलजिम जरायम पेशा जातियो के ऐक्ट; सन १८९१ ई० की धारा ४ के अधीन जरायम पेशा जाति का रजिस्टर्ड मेम्बर हो, या

सन १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

( घ ) दण्ड-विधि-संग्रह ) जाज्ता कौजदारी सन १८६८ ई० की धारा १८६ या ११० के अधीन अच्छा चाल चलन रखने के लिये उसका मुचलका हो चुका हो, या

( ड ) जुआ खेलने के अपराध में सजा मिली हो ।

### मुस्तगीसों को मुआविजा

६०—जुर्माने का दण्ड देने की दशा में पंचायती अदालत यह आज्ञा दे सकती है कि जुर्माने से वसूल की हुई रकम का कोई भाग या पूरी रकम;

( क ) उन खर्चों को पूरा करने के लिये काम में लाई जाये जो मुस्तगीस ने उचित रूप से मुकद्दमे में खर्च किया हो, और

( ख ) किसी ऐसी माली नुकसान या क्षति की पूर्ति ( मुआविजे ) में दी जाय जो अपराध किये जाने के कारण हुई हो ।

### मुलजिम ( अभियुक्त ) को मुआविजा

६१—यदि तहकीकात के बाद किसी पञ्चायती अदालत को इस बात का विश्वास हो जाय कि उसके सामने केवल परेशान करने के लिये निरर्थक और झूठा मुकद्दमा पेश किया गया था तो वह उस मुस्तगीस को यह आज्ञा दे सकती है कि वह मुलजिम ( अभियुक्त ) को ऐसा मुआविजा अदा करे जो पांच रुपये से अधिक न हों, जैसा कि वह उचित समझे ।

मुजरिमों (अपराधियों) को आजमाइश पर रिहा करना

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ६ सन् १९३८ ई०

६२—पंचायती अदालत संयुक्त प्रान्त के 'फर्स्ट' आफ्फिन्डर्स प्रोवेशन ऐक्ट सन् १९३८ ई० की धारा ४ के अधीन अधिकारों को काम में ला सकती है ।

नोट—यानी प्रथम बार मामूली अपराधी को कड़ा दण्ड न देकर सिर्फ नेकचलनी का मुचलका लेकर उपरोक्त ऐक्ट के अनुसार पंचायती अदालत अभियुक्त को छोड़ सकती है ।

मैजिस्ट्रेटों के भेजे हुये मुकदमों की तहकीकात

सन् १८९८ ई० का ऐक्ट नं० ५

६३—जान्ता फौजदारी ( दण्ड-विधि-संग्रह ) सन् १८६८ ई० की धारा २०२ के अधीन कोई मैजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि पंचायती अदालत किसी ऐसे मुकद्दमे में जिसमें कि अपराध उस पंचायती अदालत के अधिकार क्षेत्र में हुआ हो तहकीकात करे और पञ्चायती अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह उस मुकद्दमे की तहकीकात करे और अपनी रिपोर्ट उक्त मैजिस्ट्रेट के पास भेज दे ।

नोट—पंचायती न्यायालय बड़े अमराविय की नहीं सुनेगी—ऐसे मामले मैजिस्ट्रेट के यहाँ भेजे जायेंगे ।

### अधिकार-सीमा

६४—यदि किसी नालिश की मालियत १ ० रु० से अधिक न हो तो पञ्चायती अदालत नीचे दी हुई किसी भी नालिश की सुनवाई कर सकती है ;

( क ) उस मुआहिदा के अतिरिक्त जो अचल सम्पत्ति ( गैर-मनकूला जायदाद ) के बारे में हो उस रकम की हर एक नालिश जो किसी मुआहिदा के आधार पर वाजिबुल अदा हो;

( ख ) किसी चल सम्पत्ति ( मनकूला जायदाद ) या उसके कीमत की वापसी के लिये नालिश;

( ग ) किसी चल सम्पत्ति के नाजायज तौर पर ले लेने या उसको नुकसान पहुँचाने के मुआवजे के लिये नालिश; और

( १ ) उस क्षति के लिए नालिश जो जानवरों के अनाधिकार प्रवेश के कारण हुई हो ।

( २ ) ग्रान्तीय सरकार या नियत अधिकारी सरकारी गजट में सूचना देकर यह आदेश दे सकती है या दे सकता है कि किसी

भी पञ्चायती अदालत को ऐसी कुल नालिशों की सुनवाई का अधिकार होगा जिनकी व्याख्या सूचना में कर दी गई हो और जो ५०० रु० से अधिक मालियत की न हो।

### फरीकों ( पक्षों ) की रज़ामन्दी से अधिकार सीमा का विस्तार

६५ किसी नालिश के फरीक एक लिखित राजीनामा द्वारा धारा ८२ में दी हुई व्याख्या की हुई किसी भी नालिश का विचार किये बिना कि उसकी मालियत क्या है, निर्णय के लिये पञ्चायती अदालत के सामने पेश कर सकते हैं और निर्धारित नियमों की पाबन्दी के साथ पञ्चायती अदालत को इस ऐक्ट के अधीन उक्त नालिश में कार्यवाही करने और उसका फैसला करने का अधिकार होगा।

### नालिशें जो पञ्चायती अदालत के अधिकार सीमा से बाहर होंगी

६६—पञ्चायती अदालत को नीचे दी हुई किसी भी नालिश की सुनवाई करने का अधिकार न होगा :—

( १ ) कोई नालिश शरीकदारी के हिसाब के वकाया के सम्बन्ध में जब तक कि उस वकाया को फरीकों या उनके एजेन्टों ने खारिज न कर दिया हो;

( २ ) किसी गैर-वसीयती जायदाद में किसी हिस्से या हिस्से के किसी भाग के लिये नालिश या किसी वसीयतनामे के अधीन किसी हिस्से विल वसीयत या उसके किसी भाग के बारे में नालिश ;

( ३ ) कोई नालिश जो श्रीमान सम्राट या किसी जन-सेवक के वन्द्य या उनकी ओर से उन कामों के बारे में की जाय जो उन्होंने सरकारी कर्तव्यों को करने में किये हों;

(४) कोई नालिश जो कोई नावालिग (अल्पवयस्क). या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग खराब हो. दायर कर या उरकी ओर से दायर की जाय;

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० २० सन् १९३९

(५) कोई नालिश जिसकी सुनवाई संयुक्त प्रांत के एक्ट कब्जा आराजी. सन् १९३६ ई० के अधीन कोई अदालत माल कर सके।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ६, सन् १९२० ई०

६) कोई नालिश जिसकी सुनवाई संयुक्त प्रान्त के गाँव-पंचायत ऐक्ट. सन् १९२० ई० के अधीन स्थापित किसी पंचायत को; संयुक्त प्रान्त के किसानों और मजदूरों को कर्जे से छुड़ाने के एक्ट, नं० १३ सन् १९३६ ई० की धारा २८ के अधीन करने का अधिकार नहीं है।

नालिशों में पूरा मुतालवा शामिल होना चाहिये

६७ (१) ऐसी हर एक नालिश में जो पंचायती अदालत के सामने दायर की जाय वह पूरा मुतालवा शामिल होगा जिसका विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में मुद्दे को अधिकार प्राप्त है. लेकिन वह इस उद्देश्य से कि उस नालिश की सुनवाई पंचायती अदालत कर सके. अपने मुतालवे का कोई भी भाग जोड़ सकता है।

(२) यदि कोई मुद्दे उसके किसी भाग के बारे में दावा न करे या उसको छोड़ दे तो उसको उन दावा न दिये हुए या छोड़े हुए भागों के बारे में दावा दायर करने का अधिकार न होगा।

मियादें

६८—हर ऐसी नालिश जो परिशिष्ट में इस सम्बन्ध में दी



मियाद की नियत अवधि के बाद पञ्चायती अदालत के सामने दायर की जाय. खारिज कर दी जायगी. भले ही मियाद के सम्बन्ध में मुद्दाअलेह ने कोई भी आपत्ति न की हो।

### पञ्चायती अदालत के निर्णय का प्रभाव

६६—इस्तहक्राक, कानूनी हैसियत, मुआहिदा या दायित्व के प्रश्न पर पंचायती अदालत का निर्णय प्ररीकों पर, उस नालिश के अतिरिक्त जिसमें ऐसे मामले का निर्णय किया गया हो, बाध्य न होगा।

नोट—Title, legal character, contract या obligation के रुवाल स्वतन्त्र रूप से आम, अदालत में मुकदमे दायर किये जा सकेंगे।

एक्ट मालगुजारी नं० ३, सन् १९०१ के अधीन

### कार्यवाहियाँ

७०—ऐसे सब विवादास्पद मुकद्दमों की जो एक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रान्त सन् १९०१ ई० की धारा ३३, ३४, ३५, ३६, ४० और ४१ के अधीन कार्यवाहियों से पैदा हों, तहसीलदार उस पंचायती अदालत का यदि कोई हों, भेज देगा जिसे सुनवाई करने का अधिकार हो।

पर शर्त यह है कि कुल विवादास्पद जायदाद पंचायती अदालत के अधिकार-क्षेत्र में हो।

संयुक्त प्रान्त का एक्ट नम्बर ३, सन् १९०१ ईसवी

और शर्त यह भी है कि एक्ट मालगुजारी आराजी संयुक्त प्रान्त; सन् १९०१ ई० की धारा ३४ और ३५ के अधीन ऐसी कार्यवाहियाँ, जो किसी ऐसी आराजी के सम्बन्ध में हों जिसकी मालगुजारी २०० रु० से अधिक हो, किसी पंचायती अदालत को न भेजी जायगी।

और यह भी शर्त है कि तहसील कागजात या नामों के दायित्व-  
खारिज की कोई दरखास्त पंचायती अदालत न लेगी।

### नज़रसानी

७१—उन सारी कार्यवाहियों में, जिसका उल्लेख धारा ७० में किया जा चुका है, सब-डिविजनल आफिसर को, अपने प्रस्ताव पर या उस दशा में जब उनके पास फैसले के लिये भेजा जाय, नज़र-सानी करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी पंचायती अदालत की किसी आशा के विरुद्ध अपील न हो सकेगी, भले ही इसके विपरीत ऐक्ट मालगुजारी आराज़ी संयुक्त प्रान्त, ऐक्ट नं० ३ सन १९०१ ई० में कोई आदेश हो।

७२—ऐक्ट मालगुजारी आराज़ी सन १९०१ ई० के अधिन कार्यवाहियों में पंचायती अदालत नियत कार्य-विधि के अनुसार कार्य करेगी।

निबटाये हुये भगड़े और ऐसी नालिशें जिनका फैसला न हुआ हो ( निर्णाय और विचाराधीन नालिशें )

७३—( १ ) कोई पंचायती अदालत किसी ऐसे मामले के बारे में किसी नालिश की कार्रवाई या तनकीह की सुनवाई न करेगी जो किसी अधिकृत अदालत के विचाराधीन हो या जिसकी सुनवाई या जिसका निर्णय कोई अधिकृत अदालत किसी ऐसी पहली नालिश में कर चुकी हो जिसके फरीक वही लोग हों या ऐसे फरीक हों जो उन्हीं फरीक या उनमें से किसी फरीक के तापेदार हों।

( २ ) जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में अदालत में मुकदमा चल रहा हो या जब किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध के बारे में मुकदमे की सुनवाई हो चुकी हो तो कोई पंचायती अदालत उसे अपराध की या उन्हीं तथ्यों

के आधार पर ऐसे अपराध की सुनवाई न करेगी, जिसके बारे में अभियुक्त पर दोष लगाया जा सकता था या उसको दण्ड दिया जा सकता था।

नोट—धारा ११ जान्ता हीवानी *Res Judicata* के आधार पर यह है।

### अदालतों का बराबर अधिकार

७४—जब किसी मुकदमे, नालिश या कार्रवाई की सुनवाई एक से अधिक पंचायती अदालतों में की जा सकती हो तो मुद्दा या दरखास्त देने वाले या मुस्तगीस, जैसी भी दशा हो, नालिश या मुकदमा या कार्रवाई ऐसी किसी भी एक पञ्चायती अदालत में दायर कर सकता है। सुनवाई के अधिकार के सम्बन्ध में किसी भगड़े का फैसला ऐसा सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मंसिफ या सब डिविजनल आफिसर, जैसी भी स्थिति हो, जिसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त हो करेगा।

### नालिशों और मुकदमों का दायर किया जाना

७५—ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस ऐक्ट के अधीन कोई नालिश या मुकदमा या कार्रवाई किसी पंचायती अदालत में दायर करना चाहता हो, वह अदालती पंचायत के सरपंच से या जब वह क्षेत्र में न हो तो किसी ऐसे पञ्च से जिसको उसने इस काम के लिये नियुक्त किया हो, जयानी या लिख कर दरखास्त करेगा और उसी के साथ वह नियत फीस अदा करेगा। पञ्चायती अदालतों पर कोर्ट फीस ऐक्ट, सब १८७० ई० लागू न होगा, उस दशा के अतिरिक्त जो नियत की गई हो, हर एक नालिश में मुद्दा उसकी मालियत लिख देगा।

दरखास्त का सारांश जो रजिस्टर में लिख लिया जायगा

७६—( १ ) जब कोई नालिश या कोई मुकदमा या कोई कार्र-

बाई जमानती दायर की जाय तो वह सरपञ्च या पञ्च जो दरखास्त ले, बिना देर किये नियत विवरण को रजिस्टर में लिख लेगा और रजिस्टर में दरखास्त देने वाले के हस्ताक्षर करा लिये जायंगे या उसके अँगूठा का निशान लगवा लिया जायगा।

( २ ) इसके बाद सरपञ्च या उसकी अनुपस्थिति में पञ्च, जिसका उल्लेख धारा ७५ में किया गया है धारा ४६ के अर्धान पञ्चायती अदालत की एक बेंच स्थापित करेगा और उस दरखास्त की आवश्यक कार्रवाई के लिए उस बेंच के सिपुर्द कर देगा और उस बेंच के सामने उस दरखास्त की सुनवाई के लिए पहली पेशी की तारीख भी नियत कर देगा और दरखास्त देने वाले को और ऊपर बताई पञ्चायती अदालत की बेंच के सदस्यों को उस तारीख की सूचना दे देगा।

### कारवाई का तरीका

७७—हर नालिश, मुकद्दमा या कारवाई जो धारा ७७ के आदेशों के अनुसार दायर की गई हो नियत तारीख को पञ्चायती अदालत की बेंच के सामने पेश की जायगी और बेंच, जब तक कि सरपञ्च उस बेंच का सदस्य न हो अपने सदस्यों में से एक को उस बेंच के चेयरमैन के स्थान के लिए चुन लेगा जो कारवाइयों का संचालन करेगा।

सम्यन्धित प्रतीक के उपस्थित न होने की दशा में नालिशों और मुकद्दमों का खारिज किया जाना

७८—( १ ) यदि मुद्दे या मुस्तगास या दरखास्त देने वाला मुकद्दमे की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना पत्र पर ही उपस्थित न हो तो पञ्चायती अदालत उस नालिश, मुकद्दमे या कारवाई को खारिज कर सकती है या ऐसी आज्ञा जारी कर सकती है जो वह उचित समझे।

( २ ) पञ्चायती अदालत किसी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई को मुदाअलेह, मुलजिम ( अभियुक्त ) या फरीक मुखालिफ की अनुपस्थिति में सुन सकती है और उसका निर्णय कर सकती है यदि मुदाअलेह, मुलजिम ( अभियुक्त ) या मुखालिफ फरीक पर सम्मन की तामील कर दी गई या यदि उसको मुकद्दमें की सुनवाई के लिए नियत समय और स्थान की सूचना दे दी गई हो ।

पञ्चायती अदालत अपने फैसले ( निर्णय ) की नज़र-

सानी न करेगी या उसको न बदलेगी

७६—( १ ) उस दशा के अतिरिक्त जिसके सम्बन्ध में उप-धारा ( २ ) में आदेश हैं या जब लिखने वाले की कोई गलती सुधारनी हो, पंचायती अदालत को किसी ऐसी डिग्री या आह्वा को जो उसने दी हो मंसूख करने या उस पर नज़रसानी करने या उसको बदलने का अधिकार न होगा ।

( २ ) आह्वा या डिग्री होने या अगर व्यक्तिगत तौर पर सम्मन की तामील न हुई हो तो, उसके मालूम होने की तारीख से एक महीने के अन्दर दरखास्त देने पर पंचायती अदालत पर्चाप्त कारणों के आधार पर जो लिख दिये जायेंगे किसी भी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई को फिर से कायम कर सकती है, जो कि उपस्थित न होने का कारण खारिज कर दी गई हो या जिसमें एक तरफा डिग्री या आह्वा दे दी गई हो ।

कानून का पेशा करने वाला कोई व्यक्ति पैरवी न करेगा

८०—पंचायती अदालत के सामने किसी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई में किसी फरीक की ओर से किसी कानून पेशा व्यक्ति को पैरवी करने की इजाजत न होगी ।

अदालत में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना

८१—धारा ८० के आदेशों की पाबन्दी के साथ, किसी

नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई का कोई प्ररीक, पञ्चायती अदालत के सामने स्वयं या ऐसे नौकर ( जो दलाल-मुकद्दमा न होगा ), हिस्सेदार, सम्बन्धी या मित्र द्वारा जिसको उसने इसके लिए अधिकार दिया हो और जिसके बारे में पञ्चायती अदालत यह मान ले कि वह उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है, उपस्थित होकरना है ।

ऐसे मामलों के बारे में, जिसमें राजीनामा इत्यादि हो

गया हो विशेष अधिकार—सीमा

८२— इस ऐक्ट में या किसी और कानून में जो उस समय जारी हो, भले ही कोई बात हो, पञ्चायती अदालत को मान्य होगा कि वह किसी ऐसे दीवानी या माल के भागड़े का जो उसके स्थानीय अधिकार-क्षेत्र की सीमा के अन्दर हो और जो किसी ऐसे समझौते या राजीनामे या हलफनामे के अनुसार जिन पर प्ररीक राजी हो, किसी अदालत के विचाराधीन न हो, निर्णय कर दे और उसी तरह किसी मुकद्दमे का फैसला कर दे अगर उसमें राजीनामा हो सकता हो ।

सचवाई का पता चलाने का अधिकार और तरीका

८३— पञ्चायती अदालत किसी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई में ऐसी शहादत सुनेगी जो प्ररीक पेश कर और वह ऐसी और शहादत तलब कर सकती है जो उसकी राय में विवादास्पद विषयों का फैसला करने के लिए आवश्यक हो । पञ्चायती अदालत का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हर नालिश मुकद्दमे या कार्रवाई के, जो उसके सामने पेश हों, तथ्यों को हर ऐसे उचित साधन से जो उसके अधिकार में हो, मालूम करे और उसके बाद ऐसी डिग्री या आज्ञा, खर्चा सहित या बिना खर्चा के दे, जो उसको उचित और कानूनी जान पड़े । वह उस गाँव में जिससे कि भागड़े का संबंध हो, स्थानीय जाँच-पड़ताल

हैं। वह इस ऐक्ट के अधीन या उसके द्वारा नियत कार्य—विधि के अनुसार काम करेगा। दीवानी—नियम संग्रह (मजमुआ दीवानी, ५ सन् १६०८ ई० कादण्ड—विधि—संग्रह (मजमुआ ज़ाव्ता फौजदारी) ५ सन् १८६८ ई०, भारतीय-गवाही ऐक्ट सन् १८७२ ई० और भारतीय काल-अवधि ऐक्ट (ऐक्ट मियाद समाप्त हिन्द); सन् १६०८ ई० पञ्चायती अदालत की किसी भी नालिश, मुकदमे या कारवाई पर लागू न होंगे उस दशा के अतिरिक्त जहाँ उसका उपयोग निश्चित कर दिया गया हो या जब इस ऐक्ट में इनके बारे में कोई आदेश दिए गए हों।

### बहुमत का निर्णय मान्य होगा

८४—यदि सब पञ्चों की राय एक न हो तो बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

पञ्चायती अदालतों के सम्बन्ध में हाकिम परगना (सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट) और मुन्सिफों के अधिकार

८५—(१) यदि किसी मुकदमे, नालिश या कारवाई में अन्याय हुआ हो या अन्याय होने की आशङ्का हो तो हाकिम परगना किसी मुकदमे में और मुन्सिफ किसी नालिश और सब-डिवीजनल अफसर संयुक्त प्रांत के ऐक्ट मालगुजारी आराजी, संयुक्त प्रान्त सन् १६०९ ई० के अधीन किसी कारवाई के बारे में, किसी फरीक की दरखास्त पर या स्वयं अपने ही प्रस्ताव पर मुकदमे, नालिश या कारवाई जैसी भी स्थिति हो, विचाराधीन होने के बीच किसी समय और डिप्री या आज़ा की तारीख से ६० दिन के अन्दर मुकदमा, नालिश या कारवाई के कागजात को, जैसी भी दशा हो, पञ्चायती अदालत से मांग सकता है और उन कारणों के आधार पर जिन्हें वह लिखेगा :—

[ क ] किसी मुकदमा, नालिश या कारवाई के बारे में पञ्चायती अदालत के अधिकार-सीमा को रद्द कर सकता है; या

[ ख ] पञ्चायती अदालत का दी हुई किमी हिमी या आजा की किसी भी अवस्था में रद्द कर सकता है; या

( २ ) जब हाकिम परगना ने उप-धारा ( १ ) के अर्धान किमी मुकद्दमे में, या तहकीकात या इन्तगामे पर हुकम दिया हो तो उसी जुर्म के बारे में इन्तगामे दायर किये जाने पर या किमी दूसरे तरीके से मुकद्दमे की मुनवाई जम मैजिस्ट्रेट की अदालत में शुरू हो सकती है जिसे ऐसे मुकद्दमे का फैसला करने का अधिकार प्राप्त हो ।

( ३ ) जब किसी मुन्सिफ ने उप-धारा ( १ ) के अर्धान किसी नालिश के बारे में आजा दे दी हो तो मुद्दा मुन्सिफ की अदालत में उसी दावे के आधार पर और उसी दादरसी ( सहायता ) के लिए नालिश कर सकता है और पञ्चायती अदालत में नालिश करने और ऐसी आजा के दिए जाने तक की अपाधि कोई नई नालिश के दायर करने की मियाद समाप्त ( काल-अवधि ) में सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

नोट—पञ्चायती अदालतों में भाई चारा या पारीबन्दी की बांझी या कानून ने अनभिष्ट देहाती पंच के लिये दर फिरका बहुत जरूरत रोक है और इबादात मुकद्दमे टिप्पी, और मुन्सिफ के दर निगानी के लिये पहुँचेंगे ।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३, सन् १९०१ ई०

( ४ ) जब सच-खिजनल अक्सर ने संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट मालगुजारी आराजी; सन् १९०१ ई० के अर्धान किसी कार-बाई के बारे में आजा दे दी हो तो उसी दादरसी के लिए और उन्हीं तथ्यों के आधार पर कार-बाईयां किसी ऐसी अदालत आद के सामने शुरू की जा सकती हैं, जिसे इन मामलों में



सुनवाई करने का अधिकार हो, और पंचायती अदालत के मामले ऐसी कार्रवाई के पेश होने की तारीख से ऐसी आज्ञा दिग जाने की तारीख तक की अवधि को नई कार्रवाई दायर करने की मियाद-समाप्त (काल-अवधि) में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

( ५ : उपर्युक्त दशाओं के अतिरिक्त, इस ऐक्ट के अधीन किसी मुकद्दमे, नालिश या कार्रवाई के सम्बन्ध में पंचायती अदालत की दी हुई डिग्री या उसकी आज्ञा अन्तिम होगी और उसकी किसी अदालत में अपील या नज़रसानी नहीं हो सकेगी।

अगर उप-धारा ( १ ) के अधीन कोई दरखास्त निरर्थक हो तो दरखास्त देने वाले को हाकिम परगना या मुन्सिफ या सब-डिवीजनल अकमर, जैसी भी स्थिति हो, ५० रु० तक जुर्माना कर सकता है।

### गवाहों के नाम सम्मन जारी करना

८३—पंचायती अदालत, यदि वह किसी नालिश, मुकद्दमे या कार्रवाई में किसी व्यक्ति की शहादत का गुजारा जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना आवश्यक समझे तो वह नियत ढङ्ग पर ऐसे व्यक्ति के नाम सम्मन जारी कर सकती है और उसको उस पर तामील करा सकती है, जिसमें उसे यह आदेश दिया गया होगा कि उसे उपस्थित होना पड़ेगा या उसे ऐसा दस्तावेज पेश करना या पेश कराना होगा और वह व्यक्ति उस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा जो सम्मन में दज हो।

पञ्चायती अदालत के सामने उपस्थित न हो सकने के लिये दंड

८७—यदि कोई व्यक्ति, जिसे पञ्चायती अदालत ने लिखित आज्ञा द्वारा गवाही देने या कोई काराजात पेश करने के लिए नलब किया हो, सम्मनों या नोटिसों या आज्ञाओं को जानबूझ कर तामील न करे तो पञ्चायती अदालत ऐसे मैजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकती है जिसको स्थानीय मुकद्दमे सुनने का अधिकार प्राप्त हो और ऐसे व्यक्ति को जुर्माने का दंड दिया जायगा जो २५ रुपये तक हो सकता है।

पर शर्त यह है कि किसी औरत को खुद-पंचायती अदालत के सामने उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जायगा। इसका नियत तरीके से कमीशन द्वारा बयान लिया जा सकता है।

नोट—धारा १३२ दीवानी नियम-संग्रह में औरतों की अधिकार वही प्रकार हैं।

पर यह भी शर्त है कि अगर इस धारा के अधीन जारी कर हुए सम्मन की तामील में कोई दस्तावेज पेश किया जाय तो पंचायती अदालत उस दस्तावेज की नकल लेगी और असल ने मुकद्दला करने के बाद उस नकल पर लिखेगा कि वह सही नकल है और असल दस्तावेज उस व्यक्ति को वापस कर देगी जिन्हने उसे पेश किया था।

**नालिशों वगैरह का खारिज किया जाना**

८८—पंचायती अदालत किमी नालिश या कार्रवाई को खारिज कर सकती है अगर मुद्दई या दरख्वात देने वाले का बयान लेने के बाद उसको इस बात का विश्वास हो जाय कि वह नालिश या कार्रवाई निरर्थक, दुःखदायी या भूठी है।

## नजरसानी

८६—पंचायती अदालत की दी हुई किसी डिग्री या आज्ञा की नजरसानी मुकद्दमे की सूरत में, हाकिम परगना ( सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ) के सामने, नालिश की सूरत में मुन्सिफ के सामने, और संयुक्त प्रांत के ऐक्ट मालगुजारी आराजी, सन् १९०१ ई० के अधीन की हुई किसी कारवाई की सूरत में ऐसे सब-डिवीजनल अफसर के सामने की जायगी जिसे इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार हो ।

नोट—६० दिन के अंदर नजरसानी होती है ।

## मुद्दाअलेह या अभियुक्त (मुलजिम) के नाम सम्मन का जारी होना

८७—कोई पंचायती अदालत, धारा ७५ के अधीन दरख्वास्त दिए जाने के बाद जब तक कि वह इस ऐक्ट के आदेशों के अधीन श्वारिजन कर दी गई हो या उस पर कोई और कारवाई न कर दी गई हो, नियत फार्म में और नियत डक के अनुसार, मुद्दाअलेह या मुलजिम ( अभियुक्त ) या करीब-मुखालिफ पर सम्मन की तामील कर देगी जिसमें उसको यह आदेश दिया हुआ होगा कि वह ऐसे समय और स्थान पर जो सम्मन में दर्ज हों उपस्थित होकर अपनी शहादत दे और पंचायती अदालत साथ-ही-साथ मुद्दे या मुस्तगीस या दरख्वास्त देने वाले को यह आदेश करेगी कि वह उस समय और उस स्थान पर उपस्थित होकर अपनी शहादत दे ।

## वारंट

८८—अगर पंचायती अदालत को यह विश्वास हो जाय कि कोई व्यक्ति सम्मन की तामीली से भाग रहा है तो वह उसके

विरुद्ध अधिक से अधिक २५ स० तक का जमानती वारंट जारी कर सकता है।

## डिगरी के अदा किये जाने के बारे में इन्दराज किया जायगा

६२- यदि डिग्रीदार या मदयून डिग्री की दरम्यान्त पर उस पंचायती अदालत को जिसने डिग्री दी हो तत्प्राप्तगत के बाद यह मालूम हो कि डिग्री का कुल या उसका कुछ भाग अदा कर दिया जा चुका है तो वह नियत रजिस्टर में इस बात को दर्ज कर लेगी।

## डिगरी का इजरा होना

६३-(१) किसी पंचायती अदालत द्वारा दी हुई डिगरी या आज्ञा का इजरा ऐसे ढङ्ग पर किया जायगा जो नियत किया जाय। यदि मुद्दाअलेह की सम्पत्ति उस पंचायती अदालत के अधिकार-सीमा के बाहर स्थित हो जिसने ऐसी डिगरी या आज्ञा दी है, तो वह उस डिगरी या आज्ञा को नियत ढङ्ग पर इजरा किये जाने के लिए उस पंचायती अदालत के पास भेज सकती है जिसके अधिकार-सीमा में वह सम्पत्ति स्थित हो और यदि ऐसी कोई पंचायती अदालत न हो तो वह डिगरी या आज्ञा को उस मुन्सिफ की अदालत में भेज सकती है जिसके अधिकार-सीमा में वह सम्पत्ति स्थित हो।

(२) यदि कोई पंचायती अदालत किसी डिगरी के इजरा में कठिनाई अनुभव करे तो वह डिगरी को मुन्सिफ के पास भेज सकती है और मुन्सिफ उस डिगरी का इजरा उसी तरह करायेंगा मानो वह डिगरी स्वयं उसी ने दी है।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३, सन् १९०१ ई०

( ३ ) संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट मालगुजारी आराजी, सन् १८०१ ई० के अधीन किसी कार्रवाई के सिलसिले में खर्चों के लिए किसी आज्ञा का इजरा, जहां तक सम्भव होगा, उप-धारा ( १ ) और ( २ ) में दिए हुए आदेशों के अनुसार किया जायगा। उप-धारा ( १ ) इस तरह पढ़ी जायगी और समझी जायगी मानों शब्द "मुनिसिफ" की जगह शब्द "सब-डिवीजनल अकसर" रख दिए गए हैं।

### जुमाने का वसूल किया जाना

८४— किसी मुकद्दमे में पंचायती अदालत के लगाए हुए जुमाने की रकम दण्ड-विधि संग्रह ( मजमुआ जव्ता फौजदारी ) ५ सन् १८६८ ई० की धारा ३८६ के अधीन दिये हुए तरीके पर वसूल की जायगी। लेकिन यदि पंचायती अदालत उसकी वसूलग्राही में कोई कठिनाई अनुभव करे तो वह उस हाकिम परगना से पंचायती अदालत जिसके अधिकार-सीमा में वह जुमाना वसूल कराने की दरखास्त कर सकती है और हाकिम परगना उसे उसी प्रकार वसूल करेगा मानो उसने स्वयं जुमाने का दण्ड दिया हो।

### अध्याय ७

#### वाह्य निमंत्रण

८५— प्रांतीय सरकार—

( क ) ऐसी अचल सम्पत्ति ( गैर-मनकूला जायदाद ) का मुआइना करा सकती है जो गांव-सभा के स्वामित्व में हो, या जो किसी गांव-पंचायत या संयुक्त कमेटी के इस्तेमाल में हो या कच्चे

में हो या किसी ऐसी इमारत का मुआइना करा सकती हैं जो गांव-पंचायत या संयुक्त कमेटी की निगरानी में बन रही है;

( ख ) एक लिखित आज्ञा द्वारा कोई ऐसी किताब या दस्तावेज तलब करा कर उसका मुआइना कर सकती हैं जो गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी के कब्जे या निगरानी में हो;

( ग ) एक लिखित आज्ञा द्वारा किसी गांव-पंचायत या संयुक्त कमेटी को आदेश कर सकती हैं कि वह गांव-पञ्चायत या ऐसी ही किसी कमेटी के कर्त्तव्यों और कार्रवाइयों के सम्बन्ध में ऐसे नकलें, रिपोर्टें या दस्तावेजों की नकलें जिन्हें वह उचित समझे, पेश करे;

( घ ) किसी गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी का ध्यान दिलाने के लिए ऐसी राय लिखकर भेज सकती हैं जिसे वह ऐसी गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी के कर्त्तव्यों और कार्रवाइयों के सम्बन्ध में उचित समझे;

( ङ ) किसी गांव-सभा, गाँव—पञ्चायत या पञ्चायती अदालत से सम्बन्धित किसी मामले को जांच करा सकती हैं; और

( च ) किसी गांव-पञ्चायत, संयुक्त कमेटी या पंचायती अदालत को तोड़ सकती हैं या उसके किसी मेम्बर को हटा सकती हैं या मुअ्तल कर सकती हैं अगर प्रान्तीय सरकार की राय में ऐसी गांव-पंचायत, संयुक्त कमेटी या पंचायती अदालत ने या उसके किसी मेम्बर ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है या लगातार उन कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है जो उक्त ऐक्ट या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के द्वारा उनके लिये बना आवश्यक हो ।

## कुछ कार्यवाहियों की मनाही

६६—( १ ) निम्न अधिकारी या कोई और व्यक्ति जिसे-

प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकार दे दिये हों, सूचना मिलने पर या स्वयं अपनी ओर से, एक लिखित आज्ञा द्वारा किसी ऐसे प्रस्ताव या आज्ञा को पालन करने से या उसके आदेशानुसार और अधिक काम करने से मना कर सकता है जिसे किसी गांव-सभा, गांव-पञ्चायत या संयुक्त कमेटी ने या उसके किसी अफसर कर्मचारी ने इस ऐक्ट या और किसी ऐक्ट के अधीन पास किया हो या दिया हो, यदि उसकी राय में यह प्रस्ताव या आज्ञा ऐसी है कि उससे जनता का यह जायज तौर पर काम में लगे हुये किसी वर्ग या समूह के काम में बाधा पहुँचती हो या तकलूफ या चोट पहुँचती हो या ऐसी बाधा तकलीफ या चोट पहुँचने की सम्भावना हो या उसके कारण मानव-जीवन, स्वास्थ्य या सूरक्षा खतरे में पड़ जाय या ऐसे खतरे का भय हो, या उससे कोई भगड़ा या दगा हो जाय या होने का भय हो। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे प्रस्ताव या आज्ञा के अनुसार या उसकी आज्ञा में किसी काम को करने या उसे जारी रखने के बारे में मनाही की जा सकती है।

( २ ) जब कोई आज्ञा उपधारा ( १ ) के अधीन दी गई हो तो नियत अधिकारी या उपरोक्त अफसर इस आज्ञा की नकल एक वयान के साथ जिसमें उस आज्ञा के देने के कारण दिये गये हों, प्रान्तीय सरकार के पास भेज देगा जो गाँव-सभा, गाँव पञ्चायत, संयुक्त कमेटी या उसके किसी अफसर या कर्मचारी से जवाब तलब करेगी और यदि जवाब आया हो तो उस पर विचार करने के बाद उस आज्ञा को रद्द कर सकती है या उसे संशोधित या बहाल कर सकती है।

( ३ ) जब किसी ऐसी आज्ञा द्वारा जो उपधारा ( १ ) के अधीन दी गई हो और जो लागू हो किसी प्रस्ताव या आज्ञा को

कार्यान्वित या उसे अधिक कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में मनाही कर दी गई हो तो गाँव-पंचायत या गाँव-सभा, संयुक्त कमेटी या उसके किसी अफसर या उसके कर्मचारी का यह कतव्य होगा कि वह, यदि आज्ञा देने वाला हाकिम यह आदेश दे, ऐसी कार्यवाही करे जो उसको उस दशा में करने का अधिकार होता जब कि प्रस्ताव पेश ही न किया गया होता या आज्ञा दी ही न गई होती और जो ऐसे प्रस्ताव या आज्ञा के अधीन किसी-व्यक्ति का ऐसी कार्यवाही करने या जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो जिसे और अधिक कार्यान्वित करने की मनाही कर दी जाय।

## अध्याय ८

### दंड और कार्यविधि

इस ऐक्ट के दिशों अको उल्लंघन करने के सम्बन्ध में दंड

६७—जो व्यक्ति इस ऐक्ट के किसी आदेश का उल्लंघन करेगा उसे जुर्माने का दण्ड दिया जब तक कि इसके विरुद्ध आदेश न हो और यह जुर्माना १० रुपया तक हो सकता है और यदि यह उल्लंघन लगातार किया गया हो तो और अधिक जुर्माना किया जायगा जो पहिले दंड के बाद जितने दिनों के लिए अपराधी का अपराध सिद्ध हो चुका है उतने दिनों के लिये १ रु० गेज तक हो सकता है।

नियमों और उपनियमों (राईलाज़) का उल्लंघन करना

६८—प्रान्तीय सरकार नियम बनाते समय और गाँव-पञ्चायत उपनियम बनाते समय नियत अधिकारी की स्वीकृति से यह आदेश



दे सकती है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा और वह जुर्माना १० रु० तक हो सकता है। यदि यह उल्लंघन लगातार किया गया हो तो फिर जुर्माना किया जायगा जो पहिले दण्ड के बाद जितने दिनों के लिए अपराधी या अपराध सिद्ध हो चुका है उतने दिनों के लिये १ रु० रोज तक हो सकता है।

### गाँव-पञ्चायत की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का दंड

६६—( १ ) जो व्यक्ति गाँव-पञ्चायत या और किसी उचित अधिकारी की लिखित स्वीकृति बिना किसी पटरी, नाली और जन-मार्ग की दूसरी और चीजों को, या किसी चहारदीवारी या उसकी दीवार या खम्भे को, या रोंशनी के खम्भों या ब्राकेट को, या ऐसे खम्भों को जिनमें मार्ग-निर्देशन लिखे हों खड़े होने के अड्डों, ऐसे नल को जो बड़े नल से पानी निकालने के लिये लगी हो या गाँव-सभा को और किसी सम्पत्ति को हटायेंगा, स्थानान्तरित करेगा, उसमें कोई रद्दोबद्द करेगा या हस्तक्षेप करेगा, उसको ऐसे जुर्माने का दंड दिया जायगा जो दस रुपये तक हो सकता है।

( २ ) यदि अपने किसी काम में लापरवाही या किसी और प्रकार उसे न कर सकने के कारण किसी भी व्यक्ति को उपधारा ( १ ) के अधीन लगाये हुये जुर्माने का दण्ड दिया गया हो और उसने गाँव-सभा की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया हो तो वह व्यक्ति जिसे दंड दिया गया हो ऐसे नुकसान को पूरा करने और जुर्माना देने का उत्तरदायी होगा और अपराधी से नियत दंड से नुकसान का हर्जाना वसूल किया जा सकेगा।

### जारी किये हुये नोटिस का उल्लंघन करना

१००—यदि किसी व्यक्ति को इस ऐक्ट के आदेशों या उसके अधीन बने हुए किसी नियम या उपनियम ( वाईलाज ) के अधीन

चल या अचल, सार्वजनिक या व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई तामील करने के लिए या नियत समय में उसके सम्बन्ध में व्यवस्था करने, कोई काम करने या न करने के बारे में नोटिस मिला हो और यदि ऐसा व्यक्ति उस नोटिस के अनुसार काम न करे तो—

( क ) गाँव-पञ्चायत ऐसा काम या ऐसी व्यवस्था करा सकती है और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में जो सारा व्यय हुआ है उसे ऐसे व्यक्ति से नियत विधि के अनुसार वसूल कर सकती है।

( ख ) ऐसे व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधी ठहराये जाने पर जुर्माने का दंड भी दिया जायगा और यह जुर्माना १० रुपये तक हो सकता है और बराबर उल्लंघन किये जाने पर पहले दंड के बाद जितने दिनों के लिये अपराधी का अपराध सिद्ध हो चुका है उतने दिनों के लिये एक रुपया रोज तक हो सकता है।

### नोटिस नाजायज नहीं होती

१०१—काई भी नोटिस उसके पार्स में काई दोष होने या उसमें काई त्रुटि होने के कारण नाजायज नहीं होगा।

### अपील

१०२—( १ ) यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसा आदेश या उसके ऐसे आदेश से जो इस ऐक्ट के अधीन या किसी नियम या उपनियम ( चाईलाज ) के अधीन की गई या दिया गया हो नुकसान पहुँचा हो तो वह जब तक इसके विपरीत आदेश न हो ऐसा आदेश या आदेश दिये जाने की तारीख से ३० दिन के अन्दर उस समय को छोड़ कर जो उसकी आदेश या आदेश की नकल प्राप्त करने के लिये दरकार हो, नियत अधिकारी के नामसे अपील कर सकता है और वह अधिकारी हक आदेश या आदेश

को संशोधित, रह या बहाल कर सकता है और उस व्यक्ति को जिसने अपील दायर की हो खर्चा दिलवा सकता है या उससे खर्चा ले सकता है।

( २ ) नियत अधिकारी, यदि उचित समझे, अपील के लिये उपधारा ( १ ) में नियत समय को बढ़ा सकता है।

( ३ ) उपधारा ( १ ) के अधीन नियत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और उसके सम्बन्ध किसी अदालत में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

### मुक्त दशाओं में मुक्तद्वे का स्थगित होना

१०३—जब किसी ऐसी आज्ञा या आदेश के विरुद्ध, जिसकी व्याख्या धारा १०२ में कर दी गई है अपील दायर कर दी गई हो तो अपील का निर्णय होने तक के समय के लिये नियत अधिकारी की आज्ञा से ऐसी आज्ञा या आदेश को लागू करने की कोई कार्यवाही और उसके उत्त्वंधन करने के किसी मुक्तद्वे को स्थगित किया जा सकता है और यदि अपील के निर्णय में ऐसी आज्ञा या आदेश को मंजूर कर दिया जाय तो उसकी अवज्ञा अपराध न समझा जायगा।

### अपराध के सम्बन्ध में राजीनामा कराने का अधिकार

१०४—( १ ) इस सम्बन्ध में बनाये हुये किसी नियम की पावन्दी के साथ कोई गाँव-पञ्चायत मुक्तद्वे दायर होने के बाद या पहले इस ऐक्ट या उसके अधीन बनाये हुए किसी नियम या उप-नियम ( बाइलाय ) के उत्त्वंधन के सम्बन्ध में किसी अपराध के बारे में गाँव-पञ्चायत को ऐसी रकम नकद अदा करने पर जो निम्न की भाँति राजीनामा करा सकती है।

( २ ) जब किसी अपराध के बारे में राजीनामा करा दिया गया हो तो अपराधी यदि हिरासत में हो, तो छोड़ दिया जायगा और इस तरह राजानामा किये हुए अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध आगे और कोई कारवाई न की जायगी ।

इस धारा के अर्धीन राजीनामे के रूप में दी गई रकम में पञ्चायत कोष ( फंड ) में जमा की जायगी ।

### दखल (प्रवेश) और मुआइना

१०५ गाँव-पञ्चायत का सरपञ्च और यदि गाँव पञ्चायत ने इस सम्बन्ध में गाँव पञ्चायत के किसी मेम्बर या अशसर या वर्ग-बारी का अधिकार दे दिया हो तो वह अपने मातहतों या काम करने वालों के साथ या उनके बिना किसी इमारत में या भूमि पर किसी काम का मुआइना ( वें पैमाइश ) और ऐसी तामीर करने के सिलसिले में प्रवेश कर सकता है जिसकी गाँव-पञ्चायत को इस ऐक्ट या इसके अर्धीन बनाये गये नियमों या उपनियमों ( बाईलाज ) के अनुसार तामीर करने या बनाने की इजाजत हो या जिसकी गाँव पञ्चायत को किसी उद्देश्य के लिये या इस ऐक्ट या नियम या उपनियमों ( बाईलाज ) के किसी आदेश के अनुसार बनाने या तामीर करने की आवश्यकता हो पर शत यह है कि :—

( क ) उन दशा के अतिरिक्त जब कि इस ऐक्ट या नियमों या उपनियमों ( बाईलाज ) में स्पष्ट आदेश हो सूर्य-अस्त और सूर्य-उदय के बीच इस तरह प्रवेश नहीं किया जायगा ।

( ख ) उन दशा के अतिरिक्त जब कि इस ऐक्ट या नियमों या उपनियमों में स्पष्ट आदेश हो, किसी इमारत में जो मनुष्यों के रहने के काम में आता हो, उसमें रहने वाले की रजामन्दी के बिना और एक रहने वाले को इस प्रकार प्रवेश करने के इरादे का काम से बच

चार घण्टे पहले लिख कर नोटिस दिये बिना इस तरह कोई प्रवेश नहीं करने पावेगा ।

( ग ) हर दशा में इस बात का काफ़ी नोटिस दिया जायगा, यहाँ तक कि जब किसी मकान पर बिना नोटिस के भी प्रवेश किया जायेगा उस समय भी इसका काफ़ी नोटिस दिया जायगा जिससे कि जानने कमरे में रहने वालों स्त्रियाँ मकान के दूसरे भाग में हट सकें जहाँ उनके अलग रहने में कोई बाधा न हो, और ।

( घ ) जिय स्थानों में प्रवेश किया जाय वहाँ के रहने वालों के धार्मिक व सामाजिक रिवाजों का उचित ध्यान रक्खा जायगा ।

### गाँव-पंचायतों या उसके अफ़सरों के विरुद्ध नालिशें

१०६—( १ ) किसी गाँव सभा या गाँव-पंचायत के विरुद्ध या उसके किसी मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी के विरुद्ध गाँव-सभा, गाँव-पंचायत या उसके किसी अफ़सर के आदेश के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध जो इस ऐक्ट के अधीन सरकारी हैसियत से की गई हो या जिसके बारे में यह समझा जाय कि वह इस ऐक्ट के अधीन की गई है, कोई नालिश या दूसरी कानूनी कार्यवाही उस समय तक दायर न हो सकेगी जब तक कि एक ऐसे लिखित नोटिस देने के बाद दो महीने न गुजर जायँ जो गाँव-पंचायत की दशा में पञ्चायतों के दफ़तर में हवाले कर दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो और मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी या किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उक्त मेम्बर, अफ़सर या कर्मचारी पंचायत के आदेश के अनुसार काम कर रहा हो उसके हवाले कर दिया गया हो या उसके दफ़तर या मकान पर छोड़ दिया गया हो और जिसमें ( लिखित नोटिस में ) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि नालिश किन कारणों और

आधार पर की गई है, जिस तरह की दायगर्ही ( सहायता ) माँगी गई है, मुआविजा, यदि कोई माँगा गया है, तो हमकी ग़म बन्धा है और दावा करने वाले का नाम और हमकी मद्रन्त ( गढ़ने की जगह ) साफ़-साफ़ लिखी होनी चाहिये और अर्जीदाते ने हमसे लिख दिया जायगा कि उस नोटिस द्वारा कर दिया गया है या छोड़ दिया गया है।

( २ ) उपधारा ( १ ) में उल्लिखित कोई दायगर्ही हम हमारे के अतिरिक्त न की जायगी जब तक बिनाए दारा ( गुप्तार ) के कारण या आधार ) पैदा होने के साथ से हम : माँगे न हो चुके हों।

नोट— दो माद की लिखित भियादी नोटिस दीतने से बाद ही हम : मदीने बिना मुबदमा दामिल होने के बाद ही दामि पञ्चायत या उसके इम्मेचारी के खिलाफ़ मुबदमा ख़ाया जा सकेगा परिते नही।

### गाँव और अदालती पञ्चायतों की रक्षा

१०७—( १ ) जुदीरल अप्रसरों की रक्षा के ऐक्ट, १८ सन १८५० ई० के आदेश अदालती पञ्चायतों के मेम्बरों पर लागू होंगे।

( २ ) किसी अदालत में कोई नालिश या मुकद्दमा गाँव-पञ्चायत या उसके किसी मेम्बर या अप्रसर या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे काम के सम्बन्ध में दायर न किया जायगा जो करने पञ्चायत या उसके किसी मेम्बर या अप्रसर के आदेश के अनुसार इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाए हुए किसी नियम या उपनियम ( बाई ला ) के अधीन नेकानियती से साध दिया हो या जिसे करने का इरादा रखता हो।

## अपराधों के बारे में पञ्चायतों को सहायता देने के सम्वन्ध में पुलिस के अधिकार और कर्तव्य

१०८—यदि इस ऐक्ट या इसके अधीन बनाए हुए किसी नियम या उपनियम ( वाई ला ) के विरुद्ध किसी अपराध के किये जाने का ज्ञान किसी पुलिस अफसर को प्राप्त हो जाय तो वह पुलिस अफसर उसकी सूचना तुरन्त गाँव-पञ्चायत को देगा और गाँव-पञ्चायत और पञ्चायती अदालत के सब मेम्बरों और कमचारियों को कानूनी अधिकार को व्यवहार करने में सहायता देगा ।

१०९—यदि दो या उससे अधिक गाँव-पञ्चायतों के बीच या गाँव-पञ्चायत और टाउन एरिया म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बीच कोई झगड़ा हो तो उस झगड़े को नियत अधिकारी के हवाले कर दिया जायगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और किसी अदालत में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

## अध्याय ६

### नियम, उपनियम ( वाईलाज़ ) और उनकी मंजूरी

११०—( १ ) प्रान्तीय सरकार, पहिले से सूचना द्वारा सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन सम्वन्धी शर्त को पाबन्दी के साथ, इस ऐक्ट के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार नियम बना सकती है ।

नोट—इस धारा के अधीन प्रान्तीय सरकार द्वारा निर्वाचन आदि के बहुत से नियम हैं । गाँव समा बन गई हैं ।

( २ ) विशेषकर उपरोक्त अधिकार और नियमों के आशय के

विपरीत गये बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये आदेश देना सकती है—

[ १ ] हर उस मामले के लिये जिसके सम्बन्ध में हम पैक्ट के आधीन आदेश बनने का अधिकार स्पष्ट रूप से या हमके आमान के अनुसार प्रान्तीय सरकार को प्राप्त हो;

[ २ ] गाँव-सभा, गाँव पंचायत और अदालतों पंचायतों स्थापित करने के लिये;

[ ३ ] गाँव-सभा, गाँव-पंचायत और अदालतों पंचायतों की बैठकों की जगह और समय नियत करने के लिये और इन बैठकों के आयोजन का ढङ्ग नियत करने के लिये और उनको ( मूलाना नोटिस ) देने के लिए;

[ ४ ] बैठकों का कार्रवाई संचालित करने के लिए, जिसमें बैठकों में सदस्यों का सवाल पूछना और बैठकों का कार्य स्थगित करना और बैठकों की मिनट बुकों ( आददास्त की किताब ) भी रखना सम्मिलित है;

[ ५ ] कमेटियाँ स्थापित करने के लिये और ऐसे मामले निश्चय करने के लिये जिनका सम्बन्ध ऐसी कमेटियों के विधान और कार्य-विधि से हो;

[ ६ ] पदाधिकारों को मुअत्तल करने और हटाने के लिए;

[ ७ ] ऐसे कागजात और रजिस्टरों के लिये जिन्हें गाँव और पंचायतों अदालतों रखेंगे और उन फार्म के लिए जिसमें वे रखेंगे आर्थिक;

[ ८ ] ऐसी कार्रवाई के लिये कार्यकारिणी-कमेटी, संयुक्त कमेटी, किराया अन्य कमेटी और पंचायतों अदालत में किसी जगह के स्थानी होने पर की जायगी;

[ ९ ] ऐसे अधिकारी के लिये जो कार्यकारिणी कमेटी, संयुक्त



कमेटी, किसी अन्य कमेटी या पंचायती अदालत में नियुक्तियों के सम्बन्ध में झगड़ों का फैसला करेगा और इस सम्बन्ध में जिस कार्य विधि के अनुसार काम किया जायगा उसके लिये;

[ १० ] गांव-पंचायत के किसी ऐसे कर्मचारी से जिससे जमानत लेना उचित और आवश्यक समझा जाय; ऐसी जमानत की रकम और यह नियत करने के लिये कि वह किस रूप में जमा की जायगी;

[ ११ ] गांव-पंचायत के कर्मचारियों को नियुक्त करने, उनकी योग्य बातें निश्चित करने, उन्हें बरखास्त करने, नौकरी से छुड़ाने, हटाने और मज्जा देने के लिए और उनके अपील करने के अधिकार के सम्बन्ध में;

[ १२ ] यदि कोई गाँव-पञ्चायत अपने कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड का तरीका अपनाये तो उसका प्रबन्ध और उसे नियमित करने के लिये;

[ १३ ] प्रारम्भिक स्कूलों को स्थापित करने; उनकी देख-भाल करने और उनका प्रबन्ध करने और उनकी इमारतें बनाने और मरम्मत करने के लिये;

[ १४ ] पुस्तकालयों वाचनालयों और उन औपधालयों ( डिस्पेंसरी ) को जिनका प्रबन्ध किसी संयुक्त कमेटी को सौंप दिया गया हो, स्थापित करने, उनका प्रबन्ध और नियंत्रण करने, के लिये, उनसे सम्बन्धित इमारतों को बनाने और मरम्मत करने और किसी गांव-सभा के स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को दवाइयां देने और उन्हें डाक्टरी सहायता पहुँचाने के लिये;

[ १५ ] किसी भूमि इमारतों या पानी पर जो पानी की बेल उग आई हो उसका पता लगाने, उसको दूर करने या नष्ट करने के लिये ऐसे बाड़ों और गोकों को बनाने के लिए जिससे ऐसी बेल के

बढ़ने को रोका जाय और उस रकम के लिये जो ऐसे कामों में खर्च हो;

[ १६ ] सफाई, कूड़ा-करकट साफ करने, गंदे पानी को नालियाँ इमारतों, जन मार्ग और पानी पहुँचाने ( सफाई करने ) के सम्बन्ध में कार्रवाही करने के लिये और ऐसे कामों को करने में मना करने के लिये जिससे सर्वसाधारण को तकलीफ पहुँचे;

नोट - नियत अधिकारी म्युनिसिपैल्टी ऐक्ट कायदों को पढ़ाई करने के लिये काम में ला सकता है।

[ १७ ] घजट बनाने और खाल कामों के लिये फण्डों को निर्धारित करने के लिये;

[ १८ ] ऐसे नकशों के लिये जिन्हें गाँव और पंचायतों अदालतों को दाखिल करना पड़ता है उस तरीके के लिये जिसके अनुसार यह तय्यार किये जायेंगे और यह नियत करने के लिये निश्चित अधिकारी के पास और किस समय यह नक्शे भेजे जायेंगे।

[ १९ ] टैक्सों और लाइसेंस फीस लगाने के लिये यह निश्चित करने के लिये कि कौन अधिकारी, कहाँ और किस तरीके से यह टैक्स तलाशीस करेगा और किस अधिकारी के सामने इस तलाशीस के विरुद्ध अपील की जा सकेंगी;

[ २० ] टैक्सों और दूसरे मतालबों की अदायगी के तरीके, समय और उनके वसूलयावी का तरीका नियत करने के और यह नियत करने के लिये कि गाँव-पंचायतें इन टैक्सों और मतालबों की वसूलयावी के लिये किस अधिकारी की सहायता ले सकती हैं;

[ २१ ] गाँव-पंचायतों के हिसाब रखने का दफ्त नियत करने के लिये;

[ २२ ] सरकारी इमारतें और नजूल की जमीन के ठीक प्रबन्ध के लिये;

[ २३ ] ऐसे ज्ञान्तों के लिये जिनके अनुसार सम्पत्ति हस्तान्तरित करते समय व्यवहार करना चाहिये और इस ढङ्ग को नियत करने के लिये जिनके अनुसार गाँव-पंचायत मुआहिदे की दस्तावेज तकमील करेगी;

[ २४ ] आडिटों, मुआइना और देख-भाल करने वाले अधिकारियों के जांच करने, गवाहों को तलब करने और उनसे जिरह करने और ऐसी दस्तावेजों पेश करने और ऐसे सारे मामले के बारे में बाध्य करने के लिये अधिकार जिनका सम्बन्ध आडिट ( हिसाब की जांच ) मुआइना और देख-भाल से हो;

[ २५ ] पंचायती अदालतों के सम्मन नोटिसों और दूसरे हुक्मनामों का जारी करने और तामील करने के लिये और गाँव-पंचायतों द्वारा नोटिसों को जारी करने और तामील के लिये;

[ २६ ] किसी पंचायती अदालत के सम्मनों और दूसरे हुक्मनामों को किसी दूसरी पंचायती अदालत या अदालत में इजरा या तामील के वास्ते हस्तान्तरण ( मुन्तकिल ) करने के लिये;

[ २७ ] मुकदमों और नालिशों के दायर करने, हुक्मनामों को जारी करने, दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने और दूसरे मामलों के बारे में पंचायती अदालतों द्वारा फीस लगाने के लिये;

[ २८ ] जब पंचायती अदालत दोनों फ़रीफ़ों की मर्ज़ों से किसी ऐसे मुकदमे की सुनवाई करे जो उसकी अधिकार-सीमा के बाहर हो तो अदालत की जाने वाली कोर्ट फीस और दूसरी फीसों के लिये;

[ २९ ] पंचायती अदालतों को दी हुई डिग्रियों के इजरा करने और हुक्मों और सजाओं की तामील के अद्वैत कार्यवाही ( कार्य-विधि ) के लिये;

[ ३० ] पंचायती अदालतों के लिये इस ऐक्ट के अधीन

अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये गाँव-पञ्चायतों के कांफ ( फंड ) नियत करने के लिये और यह नियत करने के लिये कि गाँव-पञ्चायती अदालतों में अश की हुई फीसों को कहां तक अपने काम के लिये खर्च कर सकते हैं;

[ ३१ ] उन अधिकारों के लिये जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या प्रांत कोई नियत अधिकारी इन पेक्ट के अधीन अपने दायित्वों के दूर करने के सम्बन्ध में प्रयोग कर और उस दफ्तर के लिये जिनमें गनु-सार ऐसे अधिकार प्रयोग में लाये जायें;

[ ३२ ] उस अज्ञात कारवाई ( कार्य-विधि ) के लिये जिस पर नियत अधिकारी गाँव-पञ्चायतों के लिये या गाँव-पञ्चायतों करने लिए उपनियम ( बाईलाज ) बनाते समय व्यवहार करनी;

[ ३३ ] नियत फार्मों या रजिस्ट्रों को छपाने के लिये;

[ ३४ ] नक़्तों, समन ब्योरे और अनुमान पेश करने के लिये;

[ ३५ ] गाँव वालंटियर फोर्स ( सेना ) के कर्तव्य, अधिकार और कामों के लिये;

[ ३६ ] गाँव-पञ्चायतों की वार्षिक रिपोर्टों और उसकी सलाह-लोचना ( रिट्यू ) पेश करने के लिये;

[ ३७ ] गाँव-पञ्चायतों के मेम्बरों के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के लिये जो गाँव-पञ्चायतों की बैठकों में सलाह देने वालों की दृष्टिगत से उपस्थित हों;

[ ३८ ] गाँव-पञ्चायत और दूसरे अधिकारियों के बीच लिखा-पढ़ी का साधन नियत करने के लिये;

[ ३९ ] गाँव-पञ्चायत के टूट जाने के बाद उनके देने-पावने के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने के लिये;

[ ४० ] उस कार्यवाही के लिये जो किसी गाँव-पञ्चायत स्थानीय क्षेत्र के सारे या किसी भाग में किसी म्यूनिसिपैलिटी, नॉटिफाइड

एरिया, टाउन एरिया या कन्टूनमेंट में सम्मिलित किये जाने पर की जाय और उस ढङ्ग के लिये जिसके अनुसार गाँव-पंचायत के देने-पावने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किया जाय;

[ ४१ ] ऐसी शर्तों के लिये जिनके अधीन गाँव-पंचायत को वाजिबुत अदा रकमें वसूल न हो सकने वाली रकमों की तरह खारिज कर दी जायें और ऐसी शर्तों के लिये जिसके अधीन फ्रीस पूरी या कुछ माफ कर दी जाय; और साधारणतया गाँव-पंचायतों पंचायती अदालतों, संयुक्त कमेटियों, दूसरी कमेटियों और राज-कर्मचारियों और दूसरे अधिकारियों के हर ऐसे मामले में पथ-प्रदर्शन करने के लिये जिसका सम्बन्ध इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने से हो;

[ ४२ ] परिगणित जातियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से गाँव-पंचायत के मेम्बरों के चुनाव को नियमित करने के लिये;

## डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का उपनियम ( वाईलाज़ )

### वनाने के अधिकार

१११—किसी नियत अधिकारी को अधिकार होगा और यह कि उसे प्रान्तीय सरकार आदेश दे तो मान्य होगा कि वह अपनी अधिकार-सीमा के अन्दर किसी गाँव-पंचायत के लिये इस ऐक्ट के अनुसार और इसके अधीन बनाए हुए नियमों के अनुसार, गाँव-पंचायत के अधिकार-क्षेत्र के अन्दर रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य सुधारने, बनाये रखने और उनकी रक्षा और सुविधा के प्रयोजनों के लिये और इस ऐक्ट के अधीन गाँव-पंचायतों के शासन प्रबन्ध को अच्छा बनाने के लिये उपनियम ( वाईलाज़ ) बनाये।

## गाँव-पञ्चायतों को उप-नियम ( बाईलाज़ )

### बचाने के अधिकार

११२—( १ ) इस ऐक्ट के आदेशों और इसके अधीन दिये गये नियमों, यदि कोई हों, और नियत अधिकारी के बचाने दिये उप-नियमों ( बाईलाज़ ) यदि कोई हों, के अनुसार गाँव-पञ्चायत निम्न लिखित के लिये उपनियम ( बाईलाज़ ) बना सकती हैं :—

( क ) किसी ऐसे साधन से, पीने के लिये पानी के जल को उसे प्रयोग करने को मना करने के लिये जिसमें स्वास्थ्य का हानि पहुँचने की संभावना हो और किसी ऐसे काम की मनाही के लिये जिससे पीने के पानी का साधन खराब होने की संभावना हो;

( ख ) किसी नाली या हमारत के पानी की निकास को जन-मार्ग पर या नदी या पोखर या तालाब या कुएँ में या किसी और जगह निकास को रोकने या नियन्त्रित करने के लिये;

( ग ) जन-मार्गों या गाँव-पञ्चायत की सम्पत्ति को क्षति में बचाने के लिये;

( घ ) गाँव-पञ्चायतों के क्षेत्र में सफाई, कूड़ा और मैला हटाने और गन्दे पानी के निकास को नियन्त्रित करने के लिये;

( ङ ) जन-मार्गों या दूसरे सार्वजनिक स्थानों का दूषान-कारक या दूसरे व्यक्तियों के प्रयोग करने से या गड़कों में नदर लगी वसूल करने से मना करने या उसे नियन्त्रित करने के लिये;

( च ) उस ढंग को नियन्त्रित करने के लिये जिनके अनुसार तालाब, पोखरे और हीज चरागाह; खेल के मैदान, खाद के गड़कों, लाशों को जलाने या दफन करने की जमीन और नहाने की जगहों को इस्तेमाल किया जायेगा या इनको अच्छी दशा में रखना जायगा ।

(२) गाँव-पञ्चायत के बनाये हुए उप-नियमों के मसविदे को नियत ढंग पर प्रकाशित किया जायगा और इसके सम्बन्ध में जो आपत्तियाँ होंगी गाँव-पञ्चायत की बैठक में उन पर विचार किया जायगा और उपनियम उन आपत्तियों सहित जो आई हों, यदि कोई हों, और उस पर जो निर्णय हुये हों उनके सहित नियत अधिकारी के सामने पेश कर दिये जायेंगे। उपनियम ( बाईलाज ) जैसा कि नियत अधिकारी उन्हें स्वीकार करे नियत ढंग पर प्रकाशित किये जाने के बाद लागू होंगे।

### मंजूरी और अस्थायी आदेश

११३—( १ ) इस ऐक्ट के अधीन किसी क्षेत्र ( इलाके ) में गाँव-सभा के स्थापित किये जाने की तारीख को या उसके बाद से—

( क ) संयुक्त प्रांत का गाँव-पञ्चायत ऐक्ट, सन् १९२० ई० के बारे में यह समझा जायगा कि वह ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में मंजूर हो गया है और पञ्चायत, यदि कोई हो, जो उस ऐक्ट के अधीन ऐसे क्षेत्र में बनाई गई थी तोड़ दो जायगी और उसके कोष (फण्ड) और दूसरी सम्पत्तियाँ और उसके देवन ऐसी गाँव-सभा को हस्तान्तरित ( मुत्तकिल ) हो जायेंगे, और मुकदमे और नालिश; यदि कोई हों, जो ऐसी तारीख को उक्त पञ्चायत के सामने विचारार्थ हों पञ्चायती अदालत को यदि कोई हो, जो उस क्षेत्र में स्थापित हो, हस्तान्तरित ( मुत्तकिल ) हो जायगी या यदि ऐसी पञ्चायती अदालत न हो तो वह फौजदारी या दीवानी की सबसे नीचे दर्जे की अदालतों को, जैसी कि स्थिति हो, और जिनको इनमें मुतबाह का अधिकार हो हस्तान्तरित ( मुत्तकिल ), हो जायगी।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ३, सन् १८९२ ई०

(ख) जहाँ तक ऐसे क्षेत्र (इलाक़े) का सम्बन्ध है संयुक्त प्रान्त का गाँव की अदालतों का ऐक्ट, ३ सन् १८६० ई० मंजूर समझा जायगा और ऐसी सब अदालतें जो उक्त ऐक्ट के अधीन स्थापित हुई हो तोड़ दी जायेंगी और ऐसे सब मुकद्दमे और दृमर्ग कायं-बाहियाँ जो उस तारीख पर उक्त स्थानीय क्षेत्र के किसी गाँव की अदालत में विचाराधीन हों ऐसी पंचायती अदालत को, यदि कोई हो, भेज दी जायेंगी जो उस स्थानीय क्षेत्र में स्थापित की गई हो और जहाँ कोई ऐसी पञ्चायती अदालत न हो तो सबसे नज़ीक़ दूरी की ऐसी अदालत दीवानी को भेज दी जायगी जिसको उन पर विचार करने का अधिकार हो, और

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० २, सन् १८९२ ई०

(ग) जहाँ तक ऐसे क्षेत्र का सम्बन्ध है देहात की सभाई का ऐक्ट, नं० २ संयुक्त प्रान्त सन् १८६२ ई० मंजूर समझा जायगा ।

संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० ६, सन् १९२० ई०

पर शर्त यह है कि यदि किसी ऐसी पञ्चायत के क्षेत्र जहाँ गाँव पञ्चायत ऐक्ट संयुक्त प्रांत, ६ सन् १८६० ई० के अधीन एक से अधिक गाँव-सभायें स्थापित की गई हों तो ऐसी पञ्चायत का कोश पाँट, सम्पत्ति और उसके दायित्व को ऐसी गाँव-सभाओं में निम्न निम्न के अनुसार बाँट दिया जायगा ।

नोट—जहाँ कहाँ गाँव सभायें हों तो पुरानी पञ्चायत की संपत्ति उन सभाओं में बाँट दी जायेंगी ।



## परिशिष्ट

( देखिये धारा ६८ )

नोट— नीचे दी हुई मियाद बीत जाने पर मुकदमा खारिज कर दिया जायेगा तावजूद मियाद का उल्लंघन भी न हो ।

मुकदमों का विवरण	मियाद ( काल अवधि )	समय जब से मियाद ( काल अवधि ) शुरू होती है
१—ऐसे रुपयों के मुकदमे के लिये जो किसी मुआहिदा के अनुसार देना हो	३ वर्ष	जब कि रुपया मुदई को प्राप्त होना हो ।
२—चल सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के मुकदमे के लिये	"	जब कि मुदई को उस चल सम्पत्ति की वसूली का अधिकार प्राप्त हो गया हो
३—किसी चल सम्पत्ति पर बेजा तौर पर कब्जा कर लेने या उसको नुकसान पहुँचाने पर उसके मुआविजे पाने के मुकदमे के लिये	"	जब कि इस चल सम्पत्ति पर बेजा तौर पर कब्जा कर लिया गया हो या उसको नुकसान पहुँ- चाया गया हो ।
४—जानवरों से पहुँचे हुये नुकसान के मुआ- वजे पाने के मुकदमों के लिये	६ महीने	जब कि जानवरों के अनिध- कार प्रवेश से नुकसान पहुँचे ।

संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट के अंतरगत

## नियम व चुनाव की रूप रेखा

Incorporating all the 7 amendments up to the end of January 1949. With up to date notes.)

[ गाँव में किस प्रकार चुनाव होगा, उसका रूप क्या, किस प्रकार के सन्तुष्ट चुने जायें सुग्न, शान्ति और सयत्न पंचायत बनाने के लिये, उनके अधिकार व कार्य पर प्रकाश जो आज तक ७ वीं संशोधित होकर परिस्पष्ट हो गया है और पंचायतें बननी शुरू हैं पाठकों के अनुरोध से प्रकाशित किया है । ]  
लेखक एवं प्रकाशक

श्री सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल एडवोकेट  
हाईकोर्ट इलाहाबाद

लेखक पंचायत राज ऐक्ट, ५४८३ ( नरसीस ) ऐक्ट, संशोधित नया रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट ( अंग्रेजी ) संशोधित विद्वी कर ऐक्ट, ग्राम सुधार ( भूमि अधिकारण ) ऐक्ट ४८ दुकान ऐक्ट सय नियम, सम्पादक नया कानून नरसीस ।

मिलने का पता—कानून महल

१ सी० वाई० चिन्तामनी रोड, इलाहाबाद

सर्वाधिकार सुरक्षित ]

१९४९

[ मूल्य आठ आना

## चुनाव की रूपरेखा

स्वतंत्रता स्वतन्त्रता की पुकार से संसार गुञ्जायमान है । इस देवी के पुजारी रंगा-चन्डी में खून की नदी बहा चुके हैं और अपने को बलिदान कितने ही कर चुके हैं और कितने मर मिटने के लिये सदा सिर हथेली पर लिये फिरते हैं । इस देवी को सहचारी बन्दाने के लिये भारत के लालों ने भारी आंदोलन से देश देशांतरों को हिला दिया, सत्याग्रह की मुसीबते सहीं, जेलें भरीं, बलिदान किया और आतन्कों को न सहन करने वालों ने गोली चलाई, बम फेंके, और हंसते हंसते फासी के तख्ते पर चढ़े ।

फलस्वरूप आज स्वतंत्रता देवी अट्टहास कर रही है, हम स्वयम्—शासक हैं, स्वराज है, प्रजातन्त्र राज्य है । अब प्रजातन्त्र के स्तम्भों को वारीकी से समझना और, उसको ठीक रूप से व्यवहार में लाना आवश्यक हो गया है जिसके साथ हम उल्लास के साथ होली खेले पर हास परिहास में विपदान आजायें, गंभीरता, कहल और घोर संघर्ष के दलदल में, कीचड़ के कीटाणु न वनें और जीवित नारकीय जीवन से बचें और जो स्वतंत्रता का आडम्बर मात्र ही कहलायेगा । ऐसा जीवन स्वतंत्रता का विकृत रूप है, ये होली नहीं खेल रहे हैं होलिका अपनी लाल लाल तपटों में जीवन की कोमलता, सरसता, स्वच्छ विश्वास, सहानिभूति, उदारता, भाई चारा, पड़ोसी धर्म सब ध्वंस करती जा रही है—पञ्च वनने की धुन में अहिर अलग गोल बना रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्री अपनी अपनी

कोशिश में हैं अछूत अपना ही राग गा रहे हैं हालां कि चुनाव संयुक्ति निर्वाचन पद्धति से होगा, और अछूतों और कम संख्या वालों के लिये भी पञ्चों की सीटें रिजर्व होंगी उनकी संख्या के हिसाब से ( Proportional Representation ) । पञ्चों को सारे गाँव के भलाई व उत्थान के लिये होना चाहिये । यह सुनने में आ रहा है कि जातीयता की गोलबन्दी से पञ्च बनने मतवालों ने सिर पुड़उवल लट्टवाजी शुरू कर दी है । किसान ज़मींदार एक दूसरे से शंकित हैं, और ग्राम महाजन कार्जदारों से । जहाँ सदियों से एक दूसरे की मदद करते थे वहाँ वैगनमय, मनमुटाव ने घर कर लिया है, इन स्मर्थअन्धता के पुजारियों ने स्वतंत्रता का विध्वंस कर दिया है ।

अभी स्वतंत्रता पनपने भी नहीं पाई थी कि हाथ हाथ शुरू हो गई । पराये का रुपया या आश्रयदाता का भवान मिलने से अपना मतलब सिद्ध हो जाता है, तो मक्कार व्यक्ति अपने सहायक को भाँस देने में नहीं हिचकता । ऐसे दम्भी, नारकीस कीणों को गाँव वाले पञ्च न चुने, उनकी हरकतों को अच्छी तरह समझ लें उसी में भये हैं । जो गाँव सेवा धर्म समझें, सहयोग, शान्ति व इमानदारी के कट्टर पक्षपाती हों और अपने को सेवक समझें लाठ नहीं वे ही सही पञ्च आसीन भाई चुने तो गाँव जीवन सुख, शान्ति, वैभव का साम्राज्य बन जाये, वरना ये पञ्चायत घोर अंधकार, वर्ग विरोध, भगड़ा, हूसदोरी और लट्टवाजी का अखाड़ हो जायेगा ।

ऐ स्वतन्त्रता के पुजारी जब शासक और शासित एक हूये

तो यह नई विपदा कैसी कुछ बिगड़े दिमाग समझते हैं। सब बन्धनों को ढीला कर देना ही स्वतन्त्रता है क्योंकि बन्धेज एक बन्धन है और जब वह ही रह गया तो स्वतन्त्रता कैसी। विचार कीजिये तो स्वतन्त्रा स्वयम् आंतरिक बन्धन है क्योंकि उसी प्रकार की स्वतन्त्रता औरों की निर्विघ्न हो सके। नहीं तो वह स्वतन्त्रता नहीं जंगलीयुग है। एक बधिया बैल को छोड़ दिया जाये कि अपने साँगे स्वतन्त्रता से चाहें जिसे घुतेड़ दें तो उसी प्रकार हजार बैल हों तो एक दूसरे का पेट फोड़ दें और जीवन ही असंभव हो जाये—इंगलैन्ड राजनीतज्ञ होव्स की अंकित इस अवस्था से हम अग्रसर हो चुके हैं, मनुष्य एक सङ्गठित समाज का जीव है जहाँ, धार्मिक, समाजिक, वैधानिक, कानूनी बन्धनों में रहते हुये व्यक्ति स्वतन्त्रता से विचरता है, धार्मिक बन्धन ईश्वरीय विश्वास, धर्म प्रदर्शकों के उपदेश, से आता है और समाजिक बन्धन पूर्वजों की व्यवस्था मान, मर्यादा का आदर से आता है। कानूनी बन्धन मनुष्य कृत अधिकार और रोक की सूची है जिसका राज शासन नियोजन करता है। शासन करने वाले समाज के अङ्ग हैं और हमारा भी उसमें भाग लेने का अधिकार है और हम अपने आपको शासित करें और सामूहिक रूप से उत्थान करने का प्रयास करें उसके लिये साधन होना चाहिये और यह साधन ग्राम पञ्चायत के रूप में मिल गया है। सेवा धर्म का अथाह समुद्र है। जब गाँव को एक सङ्गठित परिवार की तरह समझा जायेगा उसके ही लिये सब कुछ किया जायेगा जैसे स्कूल, अस्पताल,

खोलना, खेती की उन्नति, सफाई, रोशनी का इन्तजाम और आपस के कलह को शान्त करने के लिये पञ्च अदालत जो असलियत को समझते हैं समय और धन की हानि बचाने के सुलभ न्याय मिल जायेंगा तो हर एक गाँव वाला अपना ही उन्नति करेगा।

गाँव का हर एक योग्य स्त्री, पुरुष २१ वर्ष के ऊपर का जो हुये गाँव सभा के सदस्य होंगे वे वोट देने के अधिकारी होंगे अपने गाँव पञ्चायत के लिये पञ्चों का चुनाव करेंगे। आवासी के हिसाब से कमी बेशी पञ्च चुने जावेंगे जहाँ :—

पञ्च चुने जावेंगे

(१)	गाँव की आवासी १ हजार से अधिक न हो	३
(२)	" " २ " " अधिक	३०
(३)	३ " " " "	३२
(४)	४ " " " "	४५
(५)	५ हजार से अधिक हो	५५

## पंचायत राज विभाग

प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पंचायतों को स्थापित करने तथा उनके निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों की पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाया है। २८ जनवरी, सन् १९४६ तक ७ सरतवा के शंशोधन पूर्णता दे दिये गये हैं। पंचायतों का निर्वाचन शुरू है।

## संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अन्तर्गत नियम व चुनाव

### अध्याय १

भूमिका—संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा ११० के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रान्तीय सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं :—

नियम १—६ तथा प्रारम्भ—(क) ये नियम “पंचायत राज नियम” कहलावेंगे।

(ख) ये उस तारीख से लागू होंगे जो सरकार सरकारी गजट में देकर प्रकाशित करे।

नियम २—परिभाषायें—इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विपरीत न हो:—

(क) “ऐक्ट” से तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० से है।

(ख) “बैंक” में ढाकखाने सेविंग बैंक, सहकारी (कोऑपरेटिव) बैंक तथा कोई अन्य स्थानीय साहूकार सम्मिलित है।

(ग) "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ( जिलाधीश )" में इन नियमों के प्रयोजनों के लिये कोई भी ऐसा अप्रसर सम्मिलित है जिसे उसने अपनी ओर कार्य करने के लिए मनोनीत किया हो।

(घ) "सरकार" से तात्पर्य संयुक्त प्रान्तीय सरकार से है।

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" तथा "स्थानीय स्वशासन संस्था ( लोकल बाडी )" में जिला बोर्ड म्युनिसिपल बोर्ड, निर्दिष्ट क्षेत्र (नोटीफाइड एरिया) तथा टाउन एरिया सम्मिलित हैं।

(च) "पञ्चायत" से तात्पर्य "गांव-पंचायत" से है।

(छ) "जन-संख्या" से तात्पर्य उस जन-संख्या से है जो किसी पंचायत की स्थापना के ठीक पहले भारत-सरकार द्वारा दी गई सब से अंतिम जनगणना (census) में दी हुई हो।

सिवाय किसी गांव सभा के जिसके सन्वन्ध में सरकार विशेष कारणों से अन्य प्रकार से आदेश दे। ( नं० १६३६ P. II. II)- शंशाधन तारीख ३१ जुलाई, ४८ )।

(ज) "निर्धारित अधिकारी" से तात्पर्य इन नियमों के प्रयोजनों के लिये उस अधिकारी ( अप्रसर ) से है जिसे प्रान्तीय सरकार ने नियुक्त या अधिकृत किया हो।

(झ) "स्टिनिंग अप्रसर ( चुनाव अप्रसर )" में महापौर स्टिनिंग अप्रसर भी सम्मिलित है।

(ञ) "सभा" से तात्पर्य गांव-सभा से है।

नियम ३—गांवसभाओं की स्थापना—(१) प्रत्येक ऐसे गांव में जिसकी जन-संख्या १,००० या उससे अधिक हो, एक गांव-सभा स्थापित की जायगी।



किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे गांव के तीन मील के भीतर ऐसे गांव हों जिनकी जन-संख्या ५०० से कम हो और जिनके नीचे लिखे हुए उप-नियमों के अधीन, आसानी से गांव के समूह की किसी गांव-सभा का भाग नहीं बनाया जा सके, तो उनको उस गांव-सभा में सम्मिलित कर दिया जायगा जो ऐसे गांव के लिये बनी हो।

( २ ) यदि किसी गांव की जन-संख्या १,००० से कम हो और यदि किसी कारण से इसको आसानी से किसी निकटवर्ती गांव अथवा गांवों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता तो चाहे इसकी कितनी ही जन-संख्या क्यों न हो, इसमें एक पृथक गांव-सभा होगी।

( ३ ) ऐसा गांव, जिसकी जन-संख्या १,००० से कम हो और जिसमें उपनियम ( २ ) के अधीन एक पृथक गांव-सभा स्थापित नहीं हो, तो ऐसे गांव या गांवों के समूह में सम्मिलित कर दिया जायगा तो तीन मील के भीतर स्थित हों।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव-सभा स्थापित करने के लिए इस प्रकार गांवों का जो समूह बनाया जाय उसकी कुल जन-संख्या साधारणतया न तो एक हजार से कम और न दो हजार से अधिक होगी।

( ४ ) ऐसे गांव में, जिसके तीन मील के अर्ध व्यास के भीतर कोई अन्य गांव स्थित न हो, एक पृथक गांव-सभा होगी चाहे उसकी जन-संख्या कितनी ही क्यों न हो।

नोट—आबादी १,००० या उससे ज्यादा वाले हर एक गांव में गांव सभा बनेगी—जो कम आबादी वाले हैं वे ३ मील के इर्द-गिर्द गांव में शामिल करके एक गांव-सभा स्थापित करेंगे और उनकी आबादी मिलाकर २,००० से बढ़े नहीं—जो ३ मील से दूरी पर स्थित गांव हैं उनमें एक गांव-सभा अवश्य होगी जन-संख्या चाहे जितनी कम हो।

सरकारी नोट—(१) उपर्युक्त नियम के प्रयोजनों के लिए गांवों के बीच की दूरी की गणना एक आबादी से दूसरी आबादी तक की जायगी।

(२) जिलाधीश किसी ऐसे गांव को जहां लोग न जाते हों वैसे हुये ऐसे समीपवर्ती गांव का एक भाग घोषित कर देंगे जहां ऐसे जन-शून्य गांव के किसान पर्याप्त संख्या में रहते हों।

नियम ३ (क) "यदि यू० पी० विलेज पंचायत ऐक्ट, १९५० ई० के अन्तर्गत स्थापित किसी गांव-पञ्चायत ( विलेज पञ्चायत ) के क्षेत्र में संयुक्त प्रान्तीय पञ्चायत राज ऐक्ट, १९४७ ई० के अन्तर्गत एक से अधिक गाँव-सभायें स्थापित हुई हों, तो पुरानी पञ्चायत का कोष, संपत्ति एवं दायित्व ऐक्ट की धारा ११३ (अ) के अनुसार प्रत्येक गाँव सभा को निर्धारित अधिकारी द्वारा सन् भाग में वितरित कर दिया जायगा। ( नं० २७२६ संशोधन ता० ६ नवम्बर, ४८ )

नियम ४—सदस्यों का रजिस्टर—(१) ऐक्ट की धारा ३ के अधीन विलसि देकर जब सरकार ने सभा स्थापित कर दी हो; तो इन नियमों के संलग्न फार्म ( क ) में सभा के सदस्यों का एक

रजिस्टर तैयार किया जायगा। इसमें दो भाग होंगे। पहले भाग में कुटुम्भवार उन सब व्यक्तियों के नाम और व्यौरे होंगे जो ऐसे गाँव में रहते हों जो किसी गाँव-सभा का अङ्ग हो और दूसरे भाग में केवल उन प्रौढ़ों के नाम और विवरण होंगे जो उक्त ऐक्ट की धारा ५ के अधीन सभा के सदस्य होने के अधिकारी हों।

नोट—रजिस्टर गाँव का तैयार होगा उसके दो भाग होंगे पहिला कुटुम्भवार सब गाँव के आबादी के लोग दूसरा २१ वर्ष प्राप्त हुए सब स्त्री, पुरुष जो गाँव-सभा के मेम्बर हो सकें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार आदेश द्वारा फार्म (क) को जब और जैसी आवश्यकता हो, संशोधित कर सकती है।

(२) पहले भाग में साधारणतया एक पृष्ठ एक कुटुम्ब के लिए नियत कर दिया जायगा और हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, परगणित जातियों सिक्खों और पासियों के कुटुम्बों के लिये अलग-अलग खण्ड होंगे। गाँव के प्रत्येक रहने के घर की एक संख्या नियत कर दी जायगी और उसे रजिस्टर के दोनों भाग में दर्ज कर दिया जायगा। दूसरे भाग में मुसलमानों, परिगणित जातियों और सामान्य जातियों के योग्यपौढ़ों के लिये अलग-अलग खण्ड नियत किये जायंगे।

नियम ५—रजिस्टर में लिखना—पञ्चायत, प्रति वर्ष के अन्त में, किसी कुटुम्ब के जन्म, मृत्यु अथवा दूसरे परिवर्तनों के सम्बन्ध में, किसी सदस्य की योग्यता अयोग्यता के सम्बन्ध में, अथवा किसी ऐसे नये कुटुम्ब की वृद्धि के सम्बन्ध में जो उस

वर्ष हुई हो, पहले अथवा दूसरे भाग में अथवा दोनों भागों जैसी भी दशा हो, आवश्यक विवरण लिखेंगी। प्रान्तीय सरकार सदस्यों के रजिस्टर को नियत समय पर दाखलाने का आदेश दे सकती है।

नोट—हमेशा सदस्य रजिस्टर सही रखना चाहिये इसको दाखलाने के लिये प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे सकती है। यह पञ्चायत राज की सराहनीय योजना है और भगड़े पैदाइश, पीती, शादी, जायज सन्तान वाले अच्छी तरह फैसल हो सकेंगे। और गाँव में गरीब शान्ति स्थापित हो सकेंगी और मुकदमा कुशल से भोले-भाले किसानों की रक्षा हो सकेगी।

नियम ६—रजिस्टर का संरक्षण—सभा रजिस्टर का सुरक्षित रखने की उत्तरदायी होगी।

नियम ७—सभा में निर्वाचन-क्षेत्र (१) जिलाधीन सभा के क्षेत्र को उतने ही निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँटेगा जितने गाँव उस क्षेत्र में होंगे। यदि किसी सभा में केवल एक ही गाँव हो, तो ऐसा गाँव ही एक निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी ऐसी सभा जिसमें एक से अधिक गाँव सम्मिलित हों और जिसमें अल्पसंख्यक जाति के लिये एक अथवा एक से अधिक जगहें सुरक्षित हों और ऐसी जगहों की संख्या सभा में सम्मिलित होने वाले गाँवों की संख्या से कम हो तो सभा का क्षेत्र उतने निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँटा जायगा कि जितनी जगहें अल्प संख्यक जातियों के लिये सुरक्षित की गई हों।

( २ ) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये सदस्यों की संख्या जहाँ तक सम्भव होगा, उस क्षेत्र की जन-संख्या के अनुसार ऐक्ट की धारा १२ के आदेशानुसार निर्धारित की जायगी ।

नोट—अल्प-संख्यक ( Minorities ) को जगह देने, और उनकी सुविधा के लिये निर्वाचन क्षेत्र को बांटा जायेगा जहाँ कई गाँव सम्मिलित करके गाँव-सभा बनी हो । धारा १२ ( ४ ) के आदेश यह है कि जहाँ कोई अल्प-संख्यक जाति हो वहाँ हर निर्वाचन क्षेत्र को इस प्रकार बनाया जायगा कि कम से कम एक अल्प-संख्यक जाति का मेम्बर चुना जा सके । चुनाव संयुक्त निर्वाचन ( Joint electorate ) पद्धति से होगी लेकिन अल्प-संख्यकों ( Minorities ) अथवा परिगणित जातियों ( Depressed Classes ) के लिये उनकी जन-संख्या के हिसाब से ( सीटें ) सुरक्षित रहेंगी । ( Proportion )

नियम ८—पंचायत के सदस्यों की संख्या—किसी पंचायत के निर्वाचन सदस्यों की संख्या, जो किसी सभा से सम्बद्ध किए जायेंगे, सभा के प्रधान और उप-प्रधान के अतिरिक्त, उस क्षेत्र की जन-संख्या के अनुपात से, जो किसी सभा में सम्मिलित हों, क्रम से निम्नलिखित नियत की जायगी :—

( १ ) यदि जन-संख्या १००० से अधिक न हो...३० सदस्य

( २ ) यदि जन-संख्या १००० से अधिक

किन्तु २००० से अधिक न हो.....३६ सदस्य

( ३ ) यदि जन-संख्या २००० से अधिक किन्तु

३००० से अधिक न हों.....३८ सदस्य

( ४ ) यदि जन-संख्या ३००० से अधिक

किन्तु ४००० से अधिक न हों.....४५ सदस्य

( ५ ) यदि जन-संख्या ४००० से अधिक हो.....४१ सदस्य

नियम ६—जगहों ( सीटों ) को सुरक्षित रक्खा जाना—  
अल्पसंख्यकों अथवा परिगणित जातियों के लिए उनका जन-  
संख्या के अनुपात से सुरक्षित सीटों की संख्या का हिस्सा लगाने  
समय आपे से कम राशि-भागों को छोड़ दिया जायगा और जो  
अपूर्णार्द्ध आधे से कम न हों उन्हें पूर्णार्द्ध गिना जायगा ।”

नियम १० रजिस्टर के भाग २ का प्रकाशन ( १ )— उस  
तारीख को, अथवा उस तारीख से पहले, जो सरकार निर्धारित  
करे, दावे और आपत्तियाँ मांगने के विषये जिलाधीश, सभा के  
क्षेत्र के अन्तर ऐसे स्थानों पर और उस प्रकार से जैसा कि वह  
उचित समझे रजिस्टर के भाग २ का हिन्दी में प्रकाशन करेंगे ।  
रजिस्टर के प्रकाशन के समय जिलाधीश इस आशय की एक  
सूचना भी प्रकाशित करेंगे कि दावे और आपत्तियाँ, यदि कोई हों  
प्रकाशन की तारीख से पाँच दिन के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे ।  
सूचना में उस व्यक्ति का नाम भी दिया जायगा जिसके नामाने वे  
प्रस्तुत किए जायेंगे और उस स्थान और समय का भी विवरण  
होगा जहाँ और जब ऐसे दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत की  
जायेंगी ।

भाषा—(२)—रजिस्टर और उसकी प्रतिलिपियाँ हिन्दी भाषा  
तथा नागरी लिपि में तैयार की जायेंगी और उनके तैयार करने  
का खर्च सम्बन्धित सभा उठायेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस ऐक्ट के लागू होने के पश्चात् पहले निर्वाचन के लिये रजिस्टर तथा उसको प्रतिलिपियों के तैयार कराने का व्यय सरकार के जिम्मे होगा ।

( ३ ) रजिस्टर का भाग २ किसी विशेष त्योहार की या वड़े महत्व की छुट्टियों को छोड़कर शेष प्रति दिन १० बजे प्रातःकाल से ४ बजे सायंकाल तक देखा जा सकेगा और गाँव-सभा का कोई भी निवासी बिना कुछ शुल्क दिये इसके उद्धरण ( नकल ) ले सकेगा ।

नियम ११—(१)—नियम १० में उल्लिखित रजिस्टर के प्रकाशन के पश्चात् शीघ्र ही जिलाधीश दावों और आपत्तियों को सुनने के लिये एक तारीख समय तथा स्थान और एक पदाधिकारी (अरुसर) नियुक्त करेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित गाँव-सभा में क्षेत्र में ढिंढोरा पिटवा कर देगा ।

( २ ) रजिस्टर के भाग २ के प्रकाशित किये जाने के ५ दिनों के भीतर कोई व्यक्ति, जिसका नाम उसमें दर्ज नहीं है, और जो उसमें अपना नाम लिखवाने का दावा करता हो, या कोई व्यक्ति, जिसका नाम उक्त रजिस्टर में लिखा है और जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम के लिखे होने पर आपत्ति करता हो, एक लिखित दावा या आपत्ति, जैसी भी स्थिति हो, उस पदाधिकारी के पास भेज सकता है जिसे जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में नियुक्त किया हो । उक्त पदाधिकारी दावा या आपत्ति करने वाले व्यक्ति को प्राप्ति स्वीकार-पत्रक (रसीद) के रूप में

उस दावा या आपत्ति की एक प्रतिलिपि अपने हस्ताक्षर करने दे देगा, और उसमें उस दावा या आपत्ति की जो भी दो सम्-  
संख्या लिख देगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति एक ही प्रार्थना-पत्र द्वारा, जिसमें किसी टिकट आदि लगाने की आवश्यकता न होगी, चाहे जितने दावे या आपत्तियाँ, जिनमें अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले दावे या आपत्तियाँ भी सम्मिलित हों, प्रस्तुत कर सकता है । ऐसे दावों या आपत्तियों की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जायंगी और उन्हें स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायगा ।

नियम १२—वह पदाधिकारी, जिसके सामने दावे और आपत्तियाँ प्रस्तुत की जायंगी, दावे और आपत्तियों का प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नियत अन्तिम तिथि के बाद शीघ्र ही किसी तिथि में, इनको ऐसे स्थान पर और इस तंग से प्रकाशित करेगा, जिनका जिलाधीश द्वारा निर्धार किया गया हो । इस प्रकार के दावे तथा आपत्तियाँ प्रकाशित की जायंगी वह निरीक्षण के लिए तीन दिन तक ६ बजे दिन से ४ बजे संध्या तक खड़ी रहेंगी ।

नियम १३—दावे तथा आपत्तियों का सुना जाना तथा उनके अनुसार रजिस्टर में संशोधन किया जाना—(१) जिलाधीश द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया पदाधिकारी नियत तिथि, समय तथा स्थान पर, ऐसी जोड़ करने तथा ऐसे



आपत्तियों को सुनने के पश्चात् जो आवश्यक प्रतीत हों, दावों तथा आपत्तियों का निर्णय करेगा उनके अनुसार रजिस्टर के दूसरे भाग में संशोधन करने की यदि कोई हो, आज्ञा देगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हाकिम परगना उस परगने का, जिसमें गांव स्थित हो, या कोई अन्य पदाधिकारी, जिसे जिला-धीश ने इस सम्बन्ध में अधिकृत किया हो, इस नियम के अधीन दिये गये हुक्म के ६ दिन के भीतर अपनी इच्छा से या उक्त आज्ञा के ३ दिन के भीतर प्रार्थना-पत्र मिलने पर उक्त आज्ञा का पुनरावलोकन कर सकता है ।

(२) दावों तथा आपत्तियों से सम्बन्धित पक्ष पदाधिकारियों के सामने या तो स्वयं या किसी प्रतिनिधि के द्वारा, जिसे लिखकर ( और जिसमें टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं ) अधिकृत किया हो, उपस्थित हो सकते हैं ।

नियम १४— संशोधित रजिस्टर को अन्तिम रूप देना तथा उसका प्रकाशित किया जाना—नियम १३ के उपनियम (१) के अधीन पुनरावलोकन करने वाले पदाधिकारी द्वारा रजिस्टर के दूसरे भाग में की गई किसी शुद्धि के अधीन—

( क ) दावों तथा आपत्तियों की सुनवाई करने वाले पदाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा अन्तिम समझी जायगी ।

( ख ) इस प्रकार संशोधित किये हुए रजिस्टर को तुरन्त ही अन्तिम रूप दिया जायगा और प्रकाशित किया जायगा और सिवा ऐक्ट की धारा ८ के अन्तर्गत दिये गये आदेश के, उस

समय तक उसमें कोई परिवर्तन न किया जायगा जब तक कि वह लागू रहेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधीश, रजिस्टर की नकल स्थिति में उसमें से किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को निकाल देने की आज्ञा दे सकता है, जो मर गया हो या जो पेंक्ट की प्राग १ में अधीन अयोग्य हो गया हो या जिसे पेंक्ट की प्राग १ में अधीन सदस्य रहने का अधिकार न रह गया हो। इसी तरह वह किसी लिपि सम्बन्धी भूल को शुद्ध करने की भी आज्ञा दे सकता है।

नियम १५—अयोग्य व्यक्तियों के नाम लिखा जाना—यदि सरकार को, जिलाधीश को, या अन्य किसी अप्रामाण्य को, जिसे इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त हो; यह विचार होगा कि वह किसी आवेदन-पत्र के दिये जाने या सूचना मिलने पर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जो यद्यपि नाम दर्ज किया जाने योग्य था, पर जिसका नाम दर्ज नहीं किया गया या जिसका नाम रजिस्टर तैयार करने, संशोधन करने या दुहराने के समय किसी वर्तमान अयोग्यता के कारण दर्ज नहीं किया जा सका हो, रजिस्टर के भाग २ में दर्ज किये जाने का आदेश दे, यदि उक्त अधिकारी को इस बात का संतोष हो जाय कि उसका नाम दर्ज किया जाना चाहिये या उसकी ऐसी अयोग्यता काद वृत्तमान नहीं है।

नियम १६—निर्वाचन कार्य-क्रम और कर्मचारियों की नियुक्ति (१) नियम १० के अधीन रजिस्टर के भाग २ के प्रक-

शित होने के १० दिन के भीतर जिलाधीश प्रत्येक गाँव सभा के लिये एक रिटर्निंग अफसर की और हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिये एक सहायक रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति करेगा और उस क्षेत्र के अन्तर्गत पञ्चायत के प्रधान, उप-प्रधान तथा सदस्यों और पञ्चायती अदालत के पञ्चों की नामजदगी और चुनाव के निमित्त इसकी बैठक के लिये एक तारीख, समय तथा स्थान नियत करेगा।

यह तारीख ऐसे प्रकाशन के एक महीने बाद होगी, परन्तु किसी भी दशा में यह उसके छः सप्ताह से अधिक देरी में न होगी। ऐसी तारीख, समय तथा स्थान की घोषणा डुग्गी पीटकर और किसी दूसरे ऐसे ढङ्ग से, जिसे जिलाधीश उपयुक्त समझे की जायगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐक्ट के लागू होने के बाद जो प्रथम चुनाव होगा उसकी तारीख सरकार द्वारा जारी किये हुए आदेशों के अनुसार जिलाधीश नियत करेगा।

( २ ) अपनी नियुक्ति होने के बाद ही रिटर्निंग अफसर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये उतनी संख्या में पोलिंग अफसरों को नियुक्त करेगा जितनों की चुनावों में वोट (मत) लेने के लिये आवश्यकता हो और उसको यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह चुनाव के सम्बन्ध में उनको आवश्यक आदेश जारी करे।

नियम १७-(१) "रिटर्निंग अफसर या उसका सहायक चुनाव के एक दिन पहले उम्मीदवारों से नियत समय तथा स्थान

पर मनोनीत पत्र प्राप्त करेंगे" (शंशोधन न० २००१ ता० ११-६-४८)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान, उप-प्रधान और पञ्चायती अदालत के पञ्चों के मनोनीत-पत्र निर्वाचन-क्षेत्र के मन्तव्य रिटर्निङ्ग अफसर द्वारा न लिये जाकर गाँव-सभा के निर्वाचन अफसर द्वारा लिए जायेंगे।

(२) मनोनीत पत्र प्रान्तीय शासन के मन्त्रिपरिषद् द्वारा निर्धारित एक रूपपत्र ( फार्म ) पर होगा, जिसे उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि, जिसे वह लिखकर अधिकार देगा, निर्वाचन अफसर या सहायक रिटर्निङ्ग अफसर के मासने, नीचे लिखी फीस के साथ प्रस्तुत ( पेश ) करेगा। फीस जमा करने की राशि वह होगी जिसको प्रान्तीय शासन विशेष आज्ञा द्वारा निर्धारित करेगा। किसी भी स्थिति में नामजदगी फीस नहीं लौटाई जावेगी। ( शंशोधन ता० १६-१-४६ न० ५१/P.R.V. )

नियत फीस इस प्रकार होगी :—

- |   |     |             |
|---|-----|-------------|
| ( १ ) प्रधान पद के लिए                  | ... | दस रुपये।   |
| ( २ ) उप-प्रधान पद के लिये              | ... | पाँच रुपये। |
| ( ३ ) गाँव पञ्चायत के सदस्य पद के लिये  | ... | चार रुपये।  |
| ( ४ ) पञ्चायती अदालत के पञ्च पद के लिये | ... | चार रुपये।  |

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार को यह अधिकार न होगा कि एक साथ ही किसी गाँव सभा के प्रधान या उप-प्रधान और गाँव पञ्चायत के सदस्य या किसी गाँव

सभा के प्रधान और उप-प्रधान के पदों के लिये चुनाव में खड़ा हो। ( शंशोधन न० १५ २७/P.R.D. २२-४८ ता० २४-७-४८ )

नियम १८—मनोनीत पत्रों की जांच (१)—(क) “मनोनीत-पत्र के पाने के पश्चात् नियम नं १७ (२) में उल्लिखित अधिकारी (अफसर) उम्मीदवार के सामने, यदि वह उपस्थित हो, उसकी जांच करेगा और यदि उम्मीदवार का नाम रजिस्टर के दूसरे भाग में दर्ज है तो उसकी उम्मीदवारी स्वीकृत करेगा (शंशोधन न० ३६१८ ता० १८-१२-४८ )

मनोनीत-पत्र के अस्वीकृत अथवा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी कार्यवाही में उसका प्रश्न नहीं उठाया जायगा।

(ख) गांव-सभा का रिटर्निङ्ग अफसर प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक रिटर्निङ्ग अफसर को ऐसे उम्मेदवारों के नामों की सूचना जो नियमानुसार प्रधान उप-प्रधान और पंचायती अदालत के पञ्चों के स्थानों के लिये मनोनीत हुए हैं, चुनाव होने के कम से कम चार घंटे पहले देगा।

(ग) यदि कोई उम्मेदवार जो नियम पूर्वक मनोनीत किया गया है वोट लिये जाने के पहले मर जाता है अथवा नियम पूर्वक मनोनीत उम्मेदवारों की संख्या उस संख्या से कम है जो निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्धारित है तो रिटर्निङ्ग अफसर खाली जगह के चुनाव तथा मनोनीत-पत्रों के लिए दूसरी तारीख नियत करेगा।

(२) यदि नियम पूर्वक मनोनीत उम्मेदवारों की संख्या उन्नी ही है जितनी कि जगहें हैं अथवा कम है तो रिटर्निंग अफसर ऐसे उम्मेदवारों की सम्बन्धित पदों के लिये निर्वाचित घोषित कर देगा और बाकी खाली जगहों के लिए यदि कोई दो विना-धीश नियमानुसार यथोचित समय पर नई कार्यवाही करेगा। यदि नियम पूर्वक मनोनीत उम्मेदवारों की संख्या एक जगह पर उन्नी जगहों की संख्या अधिक है और कोई उम्मेदवार रिटर्निंग अफसर को अपनी नामजदगी वापिस लेने की लिखित सूचना भेज संग्रह करने (वोट लेने) के पहिले नहीं देता तो वह गिने जायेंगे। (ता० १६-१-४६ का शंशोधन)

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव सभा के प्रधान, उपाध्यक्ष तथा पञ्चायत अदालत के पञ्चों की नामजदगी वापिस लेने की सूचना, जहां तक सम्भव हो नामजदगी वापिस लेने के पश्चात् शीघ्र ही रिटर्निंग अफसर द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के नामजद रिटर्निंग अफसर के पास भेज दी जावेंगी। परन्तु यदि किसी सूचना किसी निर्वाचन क्षेत्र में वोट गिने जाने के पहिले नहीं पहुँचे, तो वहां वोट तो ले लिये जावेंगे, लेकिन उस उम्मेदवार के वोटों को जिस ने नामजदगी वापिस लेली है, रिटर्निंग अफसर द्वारा चुनाव के परिणाम को घोषित करते समय हिसाब में नहीं लिखा जावेगा। (ता० १६-१-४६ शंशोधन)

(३) पञ्चायती अदालत के पञ्चों के मनोनीतिकरण की दशा में रिटर्निंग अफसर को इस बात को देख लेना चाहिये कि

उम्मीदवार का नाम रजिस्टर के दूसरे भाग में दर्ज है और वह हिन्दी नागरी लिपि में पढ़ और लिख सकता है ।

नियम १९—निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का समूहों में विभाजन—(१) रिटर्निङ्ग अफसर बैठक की नियत तारीख, समय और स्थान पर चुनाव-क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग के उपस्थित सदस्यों को, यदि आवश्यक समझे, तो सुविधाजनक समूहों में विभाजित करेगा और प्रत्येक समूह को एक पोलिंग अफसर के अधीन रखेगा ।

( २ ) चुनाव प्रारम्भ होने के ठीक पहले रिटर्निङ्ग अफसर निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर उन उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा, जो प्रत्येक पद के चुनाव के लिए नियमानुसार मनोनीत हुए हैं ।

( ३ ) निर्वाचन—क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होगा, जितने कि उस क्षेत्र में पञ्चायत के सदस्यों के लिये तथा गाँव-सभा में अन्य पदों के लिए, जैसी भी दशा हो, उम्मीदवार हों ।

नियम २०—विभिन्न पदों का निर्वाचन पृथक पृथक होगा—विभिन्न पदों, अर्थात् ( क ) सभा के प्रधान, ( ख ) उप-प्रधान, ( ग ) पञ्चायत के सदस्य और ( घ ) पंचायती अदालत के पञ्च के चुनाव की कार्यवाही पृथक-पृथक की जायगी और एक पद से सम्बन्धित कार्यवाही, दूसरे पद से सम्बन्धित

कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पहले समाप्त की जायगी। प्रत्येक गाँव-सभा, अदालत के पाँच पञ्चों का चुनाव करेगी। यदि नियत तारीख पर चुनाव की कार्यवाही समाप्त नहीं होती, तो वह उसके अगले दिन रिटर्निंग अफसर द्वारा नियत समय पर होगी।

नियम २१ मत देने की कार्य-विधि—(१)—प्रत्येक समूह (ग्रूप) का पोलिंग अफसर, सभा के प्रधान, उप-प्रधान, पंचायत के सदस्य तथा अदालत के पदों के लिये खड़े होने वाले प्रत्येक स्वीकृत उम्मीदवार के लिए हाथ उठाकर मत लेंगा, और रिटर्निंग अफसर को लिखित रूप में, प्रत्येक उम्मीदवार का जितने मत प्राप्त हुए, सूचित करेगा।

( २ ) जब कि गाँव-पंचायतों के पंचों के चुनाव के सम्बन्ध में अल्प संख्यक सम्प्रदाय तथा परिगणित जातियों के लिये स्थान ( सीट ) सुरक्षित रखे जायं तब अल्प संख्यक सम्प्रदाय, परिगणित जातियों तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए, जैसी भी स्थिति हो- पृथक्-पृथक् रूप से एक के बाद दूसरे के लिये मत संग्रह किये जायेंगे। जिन उम्मीदवारों को प्रत्येक स्थिति में सर्वोच्च अधिक मत प्राप्त होंगे, उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

नियम २१ (घ) - चुनाव को स्थगित करने का अधिकार - जिलाधीश अपने आदेश द्वारा रिटर्निंग अफसरों को अधिकार देगा कि यदि रिटर्निंग अफसरों के पास ऐसा विश्वास करने के कारण हों कि निश्चित तिथि पर चुनाव करने से निर्णय न हो सके, तो वह दंगा या उपद्रव होंगे की अपेक्षा है तो वे उन्हें



निश्चित तिथि पर होने वाले किसी भी गांव सभा के चुनाव को किसी अगली तिथि को, जिसे जिलाधीश बाद को निश्चित करे, स्थगित कर दें। (संशोधन ता० ११-१-४६)

नियम २२ सफल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा—

(१)—निर्वाचन-क्षेत्र के सम्प्रदायों के सब उम्मीदवारों के सम्बन्ध में मत संग्रह करने के बाद, रिटर्निंग अफसर सफल उम्मीदवारों के नाम, तथा उसके साथ-साथ सफल और असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की संख्या भी घोषित करेगा।

(२) सभा के प्रधान, उप-प्रधान और पंचायती अदालत के पंचों के पदों के निर्वाचन के सम्बन्ध में मत-संग्रह का नतीजा प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का सहायक रिटर्निंग अफसर चुनाव समाप्ति के पश्चात् तत्काल ही गाँव-सभा के रिटर्निंग अफसर के पास भेजेगा, और रिटर्निंग अफसर ऐसे चुनाव का नतीजा नियमानुसार घोषित करेगा।

(३) रिटर्निंग अफसर एक ऐसी सूची तैयार करेगा और उसकी शुद्धि प्रमाणित करेगा, जिसमें प्रत्येक पद (स्थान) के सम्बन्ध में ऐसे मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने मत दिया, उनके उम्मीदवारों के नाम, चाहे वे सफल हुए हों या असफल, और प्रत्येक द्वारा प्राप्त मतों (वोटों) की कुल संख्या का विवरण दिया रहेगा।

(४) उप-नियम (३) के अधीन तैयार किया गया नक्शा नियम २४ के अन्तर्गत लाटरी (पुर्जी) के परिणाम के सहित अगर कोई हो निर्वाचन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर जिलाधीश के पास भेज दिया जायगा।

नियम २३—परिणाम की घोषणा—जिलाधीन, चुनाव के परिणाम की घोषणा के पश्चात् जितने शीघ्र सम्भव होगा, सभी उम्मीदवारों के नामों की एक सूची नदर्नाल के आधिकार में, और दूसरी गांव सभा के क्षेत्र के भीतर किसी मुख्य स्थान पर, टंगवा कर प्रकाशित करेगा। दुर्गो पोटवार भी इसकी सूचना दी जायगी।

नियम २४—घोटों (मतों) की सामान्यता पर आधारित मतों वोटों का निर्णय किया जाना—जब कि उम्मीदवारों के मतों की समानता हो और उनमें से किसी उम्मीदवार के पक्ष में मत की और वृद्धि कर देने से वह इस बात के योग्य हो, कि उसे निर्वाचन घोषित किया जाय, तो इस बात पर निर्णय लेता अतिरिक्त वोट किस के पक्ष में दिया जाय, ताकि (एक) द्वारा रिटर्निङ्ग अप्रसर और उम्मीदवारों के नामों के आधार से जिसे उक्त अप्रसर निर्धारित करें, किया जायगा।

नियम २४ (अ) अध्याय में किन्दा बात के सम्बन्ध में मतों के होने हुए भी प्रान्तीय शासन का अधिकार होगा कि इसी भी समय, इस पंचट के लापू होने के पश्चात् होने वाले पाले चुनाव के लिए, सामान्य अध्याय विशेष प्रस्तावना, मतों के रजिस्टर का प्रकाशन तथा निगरानी, मतसूची और चुनाव के विधि (तारीख) समय और स्थान तथा इसके मतों और मत-विधि का नियत करने के निर्देश देवे। (संशोधन नं० १६-१-१९४६)

न किया जाना—कोई भी व्यक्ति अफसरों तथा उन व्यक्तियों के कर्त्तव्य-पालन में, जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये हों, किसी तरह की बाधा या हस्तक्षेप न करेगा ।

नियम २६—सरकारी, अथवा स्थानीय संस्था के कर्मचारी का हस्तक्षेप करना—सरकारी अथवा किसी स्थानीय अधिकारी संस्था का कर्मचारी किसी निर्वाचन में, किसी के पक्ष के प्रचार करके या अन्य रूप से हस्तक्षेप न करेगा और न किसी विधि से अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा ।

नियम २७—दण्ड—कोई भी ऐसा व्यक्ति दण्डित किया जायगा और ऐसा दण्ड जुर्माना के रूप के दस रुपये तक हो सकेगा, जो :—

( १ ) नियमों का उल्लंघन कर सदस्यों के रजिस्टर या उसकी प्रतिलिपि या किसी अन्य लेख-पत्रों में निशान बनायेगा या परिवर्तन करेगा, या

( २ ) किसी रूप में कोई बाधा या हस्तक्षेप किसी ऐसे अफसर या कर्मचारी कर्त्तव्यों के पालन में करेगा जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किया गया हो या रखा गया हो, या

( ३ ) इन नियमों के अधीन तहसील या अन्यत्र लगाये गये या अन्य रूप से प्रकाशित किये गये प्रतिलिपि, सूचना या अन्य नियम २५—अफसरों आदि के कर्त्तव्य-पालन में हस्तक्षेप

लेख-पत्रों को विकृत करेगा, छानि पहुँचायेगा, अदल-बदल करेगा या हटायेगा, या

( ४ ) इन नियमों द्वारा बांछित किसी कार्य या कार्रवाई करने की अवहेलना करेगा या करने से इन्कार करेगा, या

( ५ ) सरकारी, अथवा किसी स्थानीय अधिकारी संस्था का कर्मचारी होते हुये नियम २६ का उल्लंघन करेगा ।

नियम २८—बचाव—इन नियमों में किसी बात के होने हुये भी निर्वाचन के संचालक, सदस्यों या रजिस्टर मैग्स्ट्रेट या अन्तिम रूप देने या गाँव-सभाओं और पंचायतों आदिको की स्थापना में नियम विरुद्ध कोई कार्रवाई होने की दशा में प्रान्तीय सरकार, इस ऐक्ट के आदेशानुसार कोई भी ऐसा आज्ञा दे सकती है जो उसे विधियुक्त और उचित जान पड़े ।

## अध्याय २

नियम २९—( १ )—निर्धारित अधिकारी ( Prescribed Authority )—की नियुक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति न होने की स्थिति में ऐक्ट की धारा ५, ६, धारा १२ की उप-धारा ( ३ ) और ( ४ ), ५२, १०२ और १०३ के प्रयोजनों के लिये निर्धारित किया हुआ अधिकारी जिलाधीश होगा ।

( २ ) इस ऐक्ट की धारा १७ (ग) २५, २७, ३० ( २ ), ३६, ४१ ( ३ ), ४४, ४७, ४८, ६६ और ६८ के प्रयोजनों के लिए

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष ( प्रेसीडेन्ट ) या अध्यक्ष द्वारा नियुक्त बोर्ड का कोई सदस्य या प्रान्तीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई इन्स्पेक्टर या कोई अन्य अफसर उन प्रयोजनों के लिए जो उसको सौंपे जायँ, निर्धारित अधिकार होगा ।

( ३ ) प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि वह इस विधान ( ऐक्ट ) की धारा ६५ के अधीन अपने अधिकार किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी ऐसे अधिकारी ( अफसर ) को प्रदान कर दे, जिसके सम्बन्ध में प्रान्तीय गजट में निकली हो ।

( ४ ) सरकार को अधिकार है कि वह विज्ञप्ति द्वारा नियम में वर्णित निर्धारित अधिकारियों के स्थान पर या उनके अतिरिक्त कोई अन्य निर्धारित अधिकारी नियुक्त करे ।

नियम ३०—इस विधान ( ऐक्ट ) की धारा १०६ के अन्तर्गत दो या अधिक पंचायतों या किसी पंचायत और टाउन एरिया के बीच भगड़ों का निवटारा करने वाला निर्धारित अधिकारी या तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अध्यक्ष होगा या बोर्ड का कोई सदस्य, वा कोई इन्स्पेक्टर या कोई अन्य अधिकारी होगा जिसे प्रान्तीय सरकार ने उस क्षेत्र के लिये नियुक्त किया हो । किसी पंचायत और म्यूनिसिपल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बीच भगड़ा होने की दशा में निर्धारित अधिकारी से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से होगा जिसे प्रान्तीय सरकार इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे । और यदि ऐसी कोई नियुक्ति न हुई हो तो प्रान्तीय सरकार स्वतः निर्धारित अधिकारी समझी जायगी ।

## अध्याय ३

नोट—आगे के अध्याय सब ता० १९ मार्च सन् १९५९ के गजट में प्रशोधित करके पूर्वप्रकाशन के बाद प्रकाशित होंगे ( ३३१७ । पं० रा० वि० २२-४८ )

## सभा पंचायत तथा समिति

गाँव सभा तथा गाँव पञ्चायत की बैठक,  
उनके फोरम और उनकी कार्यकारिणी  
के सम्बन्ध में नियम

११—बैठक, समय, तारीख और स्थान—सभा १५ ( २२३ ) की बैठकें सप्ताहवारी ऐसे दिनों में होती होंगी, उनके कार्यक्रम ( २२४ ) में दिये गए हों। इन बैठकों का समय, तारीख और ठीक स्थान, पंचायत या उसकी अनुवर्धिता में उप-सभापति निर्दिष्ट करेगा।

१२—बैठक की सूचना—सभा के बैठक की सूचना १५ ( २२३ ) की तारीख के कम से कम १५ दिन पहिले दी जाएगी और संस्था के बैठक की सूचना में कम से कम सात दिन की सूचना दी जाएगी।

१३—बैठक का बुलावा—पंचायत का सभापति या उसकी अनुवर्धिता में उप-सभापति किसी भी समय संस्था के बैठक बुला सकते हैं और इन्हें अपने मान्य ( अनिवार्य ) होना पड़ेगा, ऐसे बुलावे प्रार्थना-पत्र के दाने पर, जिसमें कम से कम एक सदस्य के हस्ताक्षर हों, ऐसे प्रार्थना-पत्र के मिलने से १५ दिन के भीतर बुलावा की बैठक बुलाई।

३४—सूचना में कार्यवाही का उल्लेख—सभा या पंचायत के बैठकों की सूचना में यह लिखा होगा कि किस प्रकार की कार्यवाहियाँ बैठक में की जायँगी जो कि सदैव धारा ३१ के अन्तर्गत नियम के अधिन होगी !

३५—कोरम और विधि—( क ) पंचायत के 'मेम्बरो' की पूरी संख्या की एक तिहाई, जिसमें सभापति और उप-सभापति भी सम्मिलित हैं, बैठक की निर्दिष्ट संख्या होगी ।

नोट—१।३ मेम्बर अवश्य मौजूद हों ।

( ख ) यदि कोई बैठक निर्दिष्ट संख्या की कमी के कारण स्थगित कर दी जाय तो स्थगित की हुई बैठक के लिये निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु बैठक की पुनः सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा ।

( ग ) गत बैठक की कार्यवाहियाँ अगली बैठक में पढ़ी जायँगी और सभापति उनको प्रमाणित करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा और पिछले महीने का हिसाब पंचायत के सामने विचारार्थ उपस्थित किया जायगा ।

३६—हिन्दी में कार्यवाहियों का विवरण रखना—सभा और पंचायत अपनी बैठकों और कार्यवाहियों का एक संक्षिप्त विवरण एक पुस्तक में ( फ़ार्म नं० ८ ) हिन्दी में रखेगी । कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि नियत अधिकारी के पास बैठक के बाद ही सात दिन के भीतर भेज दी जायगी ।

३७—बैठकों की सूचना—( १ ) सभा के बैठक की सूचना का प्रकाशन निम्नलिखित रीतियों से किया जायगा :—

( क ) गांव-सभा के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर सूचना चिपकाकर ।

( ६ ) हुगहुगी पीठपर घोषणा करके ।

( ७ ) यदि संभव हो तो स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करके ।

( २ ) 'चायत के बैठक की एक सूचना चौकीदार या 'चौकीदार' के द्वारा प्रत्येक सदस्य के पास भेज दिया जायगी और पंचायत की कार्य-सीमा के भीतर प्रमुख स्थानों पर एक सूचना लगाकर उसका प्रकाश किया जा सकता है ।

३८—बैठक की अवधि—पंचायत की बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

३९—प्रश्न या प्रस्ताव की सूचना—यदि पंचायत का कोई सदस्य किसी बैठक में, कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे अथवा कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वह अपने आग्रिप्राय की एक सूचना उसके पहले की बैठक में देगा या बैठक के कम से कम १० दिन पहले अपने आग्रिप्राय के सम्बन्ध में सभापति को या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति को या मंत्री को लिखकर सूचना देगा ।

पर प्रतिबन्ध यह है कि सभा का सभापति स्वेच्छानुसार, बिना ऐसे प्रस्ताव पर वाद-विवाद किये जाने की या किसी ऐसी कार्य-वृत्ति के किये जाने की आशा के, जिसके लिये पहले से सूचना न दी हो, परन्तु जो उससे विचार के रहनी आवश्यक हो कि वह उन तुरन्त विचार निश्चित करना आवश्यक है ।

४०—किसी निर्णय पर गौद-स्तना या पंचायत द्वारा पुनर्विचार—किसी ऐसे विषय पर, जिसका सम्बन्ध निर्णय सम्बन्धित या पंचायत द्वारा कर लिया गया हो, प्रस्ताव के एक वर्ष के बाद ही तीन मास के भीतर पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि आम-स्थान या पंचायत के सदस्य, किसी संख्या के निर्धार के बल



न हो, ऐसा करने के लिये किसी प्रायोजना-पत्र पर अपने हस्ताक्षर द्वारा अनुमति न दें।

४१—गाँव-सभा या पंचायत के सामने प्रस्ताव या सुझाव—  
(क) किसी गाँव-सभा या पंचायत का सभापति किसी ऐसे प्रस्ताव या सुझाव को, जिसके सम्बन्ध में उसका यह विचार हो कि इस पर गाँव-सभा या पंचायत को विचार करने का अधिकार नहीं है, विचार-विनिमय किये जाने के उद्देश्य से स्तुत किये जाने से रोक सकता है और वह ऐसा करने के कारण लखे।

(ख) ऐसे सब स्तावों या सुझावों पर, जिनको प्रस्तुत किये जाने की सभापति ने आज्ञा दे दी हो, विचार-विनिमय किया जायगा और उनको बहुमत से पास किया जायगा, किन्तु बराबर वोटों के आने की दशा में सभापति को नजीक ट देने का अधिकार होगा।

(ग) सभापति की आज्ञा के बिना, प्रस्ताव प्रस्तुत करनेवाले के अतिरिक्त कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर अवश्य से दूसरी बार नहीं बोल सकता है।

४२—पूछे जानेवाले प्रश्न—पंचायत के सदस्य जो प्रश्न पूछेंगे वे इस ऐक्ट के अधीन पंचायत के शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में होंगे, किन्तु वे न तो विवादास्पद, न काल्पनिक और न किसी जातिविशेष या व्यक्ति के लिये अपमानजनक होने चाहिए और न वे किसी ऐसे मुकद्दमे नालिश या कार्यवाही के सम्बन्ध में होंगे जो पंचायती अदालत के विचारधीन हों या जिन पर कोई अदालत या ठठका कोई पंच कानूनी कार्यवाही कर रहा हो।

४३—प्रश्न को रोक देना—पंचायत के सभापति को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे प्रश्न को पूछे जाने से रोक दे जो उपरोक्त नियम के अनुसार न हो और हर ऐसी दशा में वह प्रश्न मिनिट्स में कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण में नहीं लिखा जायगा।

४४—प्रश्नों पर कार्यवाही—प्रश्नों के मिलने पर सभापति सेक्रेटरी या कोई अन्य सदस्य, जो सभापति द्वारा अधिकृत हो, उन्हें मिलने की तारीख के अनुसार उन पर नियमानुसार नमूना जवाब देगा और उनको सभापति के सामने रखेगा जो पंचायत के किसी अध्यक्ष या कर्मचारी को इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करने का आदेश दे सकता है।

४५—प्रश्नों का उत्तर—( १ ) पंचायत की अगली बैठक में सभापति या उसकी आज्ञा से उपसभापति या पंचायत का मंत्री उन प्रश्नों के उत्तर पढ़ेगा जो बैठक के पहले नियमानुसार मिले हों, बिना पूर्व प्रश्नों की आज्ञा नहीं दी जायगी।

( २ ) प्रश्न पूछनेवाला सदस्य प्रश्न को किसी भी समय बैठक के प्रश्न के पढ़े जाने के पहले वापस ले सकता है, लेकिन हर ऐसी दशा में प्रश्न मिनिट्स-कार्यवाहियों के संक्षिप्त विवरण से निकाल दिया जायगा।

( ३ ) अगर किसी सदस्य ने, जिमने किसी प्रश्न के नियमानुसार नोटिस दी हो, उस प्रश्न की बैठक होने से पहले वापस न लिया हो और वह स्वयं बैठक में उपस्थित न हुआ हो तो सभापति उस प्रश्न को पूछे जाने की अनुमति किसी दूसरे सदस्य को, जो उपस्थित हो दे सकता है और उसके उत्तर के पढ़े जाने की भी अनुमति दे सकता है।

४६—बैठक का अख्तियार सभापति—सभापति या इसकी अनुपस्थिति में उपसभापति या अध्यक्ष या पंचायत की प्रत्येक बैठक में सभापति के आसन को ग्रहण करेगा और उक्त दोनों सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में सभापति द्वारा मनोनीत पंचायत का कोई सदस्य सभापति के स्थान पर काम करेगा और वह उन सभी कृतिकारों को चलेगा और उन सभी कृतिकारों को स्मरित करेगा जो विधान के द्वारा दिये गये हो या और दिये गये हो।

४७—पंचायत के सभापति के कर्तव्य—सभापति का कर्तव्य होगा कि—

क. ( १ ) गांव-सभा और पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाये और उनका सभापतित्व ग्रहण करे ।

( २ ) बैठक में की जानेवाली कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखेगा और सुव्यवस्था स्थापित करेगा ।

ख. पंचायत की आर्थिक व्यवस्था तथा शासन-विभाग की देखभाल करे और यदि उनमें त्रुटि हो तो उसकी सूचना पंचायत को दे ।

ग. पंचायत के कर्मचारीवर्ग की देखभाल करे और उन पर नियंत्रण रखे ।

घ. नियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न रजिस्ट्रों को सुव्यवस्थित रखने का प्रबन्ध करे और पंचायत की ओर से समस्त पत्र-व्यवहार करे ।

च. विभिन्न कार्यों के कार्यान्वित कराने का, पंचायत की सम्पत्ति की रक्षा का और पंचायत द्वारा लगाये गये कर या शुल्क के बाँधने और इकट्ठा करने का प्रबन्ध करे ।

छ. पंचायत की ओर से नालिश करे और मुकदमे-दायर करे ।

ज. उन अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो कि अन्य विधान के अन्तर्गत लगाये गये हों या उनसे सम्बन्धित हों ।

४७ अ.—सभापति के विशेषाधिकार—विशेष आवश्यकता पड़ने पर नियत अधिकारी को सूचना देकर बिना पंचायत की स्वीकृति पास किये हुए भी सभापति को कोई भी कार्य करने का अधिकार होगा । पंचायत की अगली बैठक में वह उस विषय को पंचायत के धमक रहेगा ।

४७ व.—संक्रामक रोगों को रोकने और वश में करने के दिव्य स  
सभापति के अधिकार—

किसी गांव में किसी छूत की बीमारी तथा अन्य बीमारी को फैलाने से रोकना और वश में करने के प्रयोजनार्थ सभापति को विभिन्न मेडिकल अप्रसर या उनके द्वारा अधिकार प्राप्त अप्रसर के आदेश तथा आज्ञानुसार वह समस्त अधिकार होंगे जो कि रोगग्रस्त व्यक्तियों तथा वस्तुओं को गांव में आने व बाहर जाने से रोकने के लिये, गांव में रहनेवाले समस्त व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से बीमा लगाने व प्रबन्ध के लिये, गन्दे खाद्य-पदार्थों को अधिकार में लेने के लिये, चूतों को नष्ट करने के लिये और यह त्याग कराने के प्रबन्ध के लिये आवश्यक हो और अन्य ऐसे कार्य करे जो कि सभापति की मर्यादा में बीमारी को रोकने और वश में लाने के लिये आवश्यक हो।

४७ स.—अधिकारों का प्रदान करना—सभापति, इन स्थानों के अधीन, जिन्हें वह लागू करना ठीक समझे आपने किसी भी प्रकार की उप-सभापति या मन्त्री के प्रदान कर सकेगा।

## पंचायत की बैठकों में सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोगों की उपस्थिति

४८—सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति—नियत अधिकारी या पंचायत का सभापति पंचायत के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोगों को परामर्शदाता के रूप में पंचायत या स्थानीय समितियों की बैठकों में उपस्थित होने की आज्ञा दे सकते हैं।

## समितियाँ बनाने के सम्बन्ध में नियम

४९—शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी समितियों का बनना—(क) अपने शासन प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिये कोई गांव

पंचायत ऐसी समिति बना सकती है जिसमें साधारणतया पाँच से कम और सात से अधिक सदस्य न होंगे, जो इन पदों पर एक वर्ष तक रहेंगे, किन्तु पंचायत के सदस्य न रहने पर उन्हें अपना पद त्याग देना होगा। समिति की बैठक में सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या तीन होगी। यदि निर्दिष्ट संख्या की कमी के कारण कोई बैठक स्थगित हो जाय तो स्थगित की हुई बैठक के लिये निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) कोई व्यक्ति एक या उससे अधिक समितियों का मेम्बर हो सकता है।

(ग) कोई समिति एक ऐसे बाहरी आदमी को भी सम्मिलित कर सकती है जो समिति की राय में, अपनी योग्यता तथा अनुभव की विशिष्टता से, समिति के काम के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हो।

५०—(क) समिति का सभापति पंचायत द्वारा समिति ही के सदस्यों में से नियुक्त किया जायगा और वोटों के बराबर-बराबर बँट जाने पर उसे एक और वोट देने का भी अधिकार होगा।

(ख) यदि कभी कोई बैठक हो और उसका सभापति अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक को उस बैठक का सभापति चुन लेंगे।

५१—समिति ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी जो उसे पंचायत द्वारा दिए जाएँगे और उस पर पंचायत का साधारण नियंत्रण रहेगा।

५२—यदि गाँव-पंचायत की आरक्षित-सीमा का विस्तार एक से अधिक गाँवों तक हो तो हर ग १५५ से कम एक सदस्य हर समिति में लिया जायगा।

५३—हर समिति की कार्यवाहियाँ पंचायत की बैठक के सामने पढ़ी जायँगी जो पर्याप्त कारणों का उल्लेख करते हुए किसी समिति के निर्णय को बदल सकती है।

## समितिघों में नियुक्तिघों किने जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न होनेवाले झगड़ों के धारे में निम्न

५४—समिति में नियुक्ति पर विवाद—कोई भी व्यक्ति, जिस पर किसी संयुक्त (ज्वाइंट) समिति या किसी दृग्गी समिति का अदालत में होनेवाली नियुक्ति का अग्र पदें श्रीर यह उक्त निर्णय के विरुद्ध आपत्ति प्रगट करना चाहे, तो नियत अधिकारी से सामने एक प्रार्थना-पत्र उपरिधत कर सकता है जिसमें वह यह कल्पना कि वह किस कारण या किन कारणों के आधार पर उक्त निर्णय के विरुद्ध आपत्ति करता है।

५५—विरोधी पक्ष को सूचना देना—नियत अधिकारी, जो पार्टी को, जिसकी नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है, यह सूचना देगा कि वह एक नियत समय के अन्दर, जो नोटिस में दिया गया होगा, सकारण बताए कि हम प्रार्थना-पत्र को क्यों न स्वीकार कर सकते हैं। उक्त पार्टी प्रार्थना-पत्र के उत्तर में अपनी लिखित बयान प्रदान अधिकारी के सामने उपरिधत करेगी।

५६—अभियोगों की जाँच—नियत अधिकारी, प्रार्थना-पत्र का लिखित बयान में लगाये हुए अभियोगों की सत्यता या असत्यता मालूम करने के लिये या तो स्थानीय जाँच करेगा या सचि को भेजेगा, जो भी वह उपयुक्त समझे।

५७—प्रार्थना-पत्र पर निर्णय—(क) यदि जाँच करने पर यह पता चले कि 'लेने पर नियत अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि उक्त आपत्ति के लिये जो किसी नियुक्ति के विरुद्ध की गई हो कोई ठोस कारण नहीं है तो प्रार्थना-पत्र को रद्द कर सकता है।

(ख) किन्तु यदि उसको यह विश्वास हो जाय कि वह निर्णय जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, चले-प्रयोग, हल-कल, फरेक, झग-

भूमकर प्रार्थना-पत्र देने या किसी मूल्यवान् वस्तु के भेंट या स्वीकार करने के परिणामस्वरूप हुई थी तो वह उस नियुक्ति को मन्सूख कर देगा और या तो एक आकस्मिक स्थान रिक्त होने की घोषणा करेगा या किसी दूसरे उम्मीदवार के बारे में यह घोषणा करेगा कि वह नियमानुसार नियुक्त हो गया है, जैसा भी वह उस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अधिक उपयुक्त समझे ।

( ग ) ( क ) और ( ख ) के अन्तर्गत आनेवाले मामलों में नियत अधिकारी स्वेच्छानुसार खर्चा दिये जाने की आज्ञा दे सकता है जो किसी दशा में पाँच रुपये से अधिक न होगा ।

५८—समिति में आकस्मिक स्थान रिक्त होना—आकस्मिक स्थान रिक्त होने की घोषणा किये जाने की दशा में, नियत अधिकारी आदेश देगा कि सम्बन्धित समिति में नहीं नियुक्ति की जाय ।

## पदाधिकारियों की मुअत्तली या उनके हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम

५९—सदस्य या चेयरमैन की मुअत्तली या उनका हटाय़ा जाना—पंचायत किसी समिति के सदस्य या सभापति को एक प्रस्ताव के द्वारा, जो पंचायत के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास किया गया हो, मुअत्तल कर सकती है या हटा सकती है, किन्तु ऐसे प्रस्ताव पास करने के पहले पंचायत सभापति या सम्बन्धित सदस्य से उन अभियोगों के सम्बन्ध में, जो उसके विरुद्ध लगाए गए हों, जवाब तलब करेगी और उस पर अपनी बैठक में विचार करेगी जिसमें मुअत्तली या हटाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचार किया जायग

६०—सभापति या उप-सभापति द्वारा त्यागपत्र—

सभा का सभापति या उप-सभापति या किसी पंचायत का सदस्य, जो अपने पद को त्यागना चाहता हो, एक लिखित त्यागपत्र उस नियम अधिकारी के पास भेजेगा और जब त्यागपत्र की मदीर्धान सभापति या उप-सभापति या सदस्य को, जैसी कि स्थिति हो, मिल जाय तो सभापति या सदस्य को सन्मन्धित व्यक्ति ने पद त्याग दिया ।

६१—सदस्य, सरपंच या पंच को पदच्युत करना—

नियम अधिकारी या प्रान्तीय सरकार सन्मन्धित सदस्य या सरपंच से जवाब तलब करने के बाद किसी भी समय किसी पंचायत के सभापति या उप-सभापति या अदालत के पंच या सरपंच को हटा सकता है ।

( क ) अगर वह कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने के आयोग्य हो जाता है या पंचायत या अदालत की सभा में किसी बैठकों से बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है और अगर पंचायत या अदालत सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इसके हटाने की सिफारिश करती है । या

( ख ) यदि उसका अपने पद में बना रहना इनका पदच्युत के हित को देखते हुए पर्याप्त कारणों से अवांछनीय है । या

( ग ) अदालत के पंच या सरपंच की दशा में उसके ऐक्ट की धारा ४६ की उपधारा ( ३ ) के आदेशों का पालन नहीं किया है ।

( घ ) यदि उसने अपनी पदवी का दुरुपयोग किया है या दुरुपयोग का, जो कि इस ऐक्ट द्वारा या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा उस पर लागू हैं, पालन करने में विफल हो जाती है ।

( २ ) इस नियम के अधीन हटाना गया कोई व्यक्ति तीन महीने के लिये किसी भी ऐसियत के सिर से सार्वसभा या पंचायत में चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा ।



६२—रिक्त स्थान भरने का तरीका—पंचायत या गांव-सभा या समिति के किसी सदस्य या सभापति या उप-सभापति या अदालत के पंच या सरपंच के अवकाश ग्रहण करने, मरने, अयोग्य सिद्ध होने, त्याग-पत्र देने या हटाये जाने पर नियत अधिकारी चुनाव के लिये तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और चुनाव उसी तरीके से किया जायगा जो ऐक्ट और उसके अधीन बनाए हुए नियमों में, जहाँ तक कि यह लागू होता हो, दिया हुआ है। इस प्रकार चुने हुए व्यक्ति पंचायत, अदालत या समिति के, जैसी भी दशा हो, कार्यकाल के शेष समय के लिये ही पदाधिकारी होंगे।

६२ (क) किसी कार्य या कार्यवाही की वैधानिकता—यदि किसी गांव-पंचायत या पंचायती अदालत अथवा गांव-पंचायत की किसी समिति के सदस्यों में कोई आकस्मिक या अन्य कारणवश कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो इसके कारण गांव-सभा, गांव-पंचायत पंचायती अदालत या ऐसी किसी समिति का कोई काम या कार्यवाही अवैध न होगी।

६२ (ख) गाँव-सभा आदि का कार्य-संचालन—कोई गांव-सभा, गांव-पंचायत और पंचायती अदालत स्थापित होने के पश्चात अपना कार्य-संचालन ऐसी तिथि से आरम्भ करेगी जिसे प्रांतीय शासन साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे।

## अध्याय ४

काराज-पत्र और उनका निरीक्षण  
गाँव-पंचायत और पंचायती अदालत द्वारा रखने  
जानेवाले काराज-पत्र और रजिस्ट्रों के  
सम्बन्ध में नियम

११—( अ ) गाँव-पंचायत द्वारा रखे जायेंगे रजिस्ट्रों में

लेख-पत्र—पंचायत उन रजिस्ट्रों, वारियों मांग सामग्री के  
जिनका उल्लेख इन नियमों के अध्याय १० में किया गया है  
लिखित रजिस्टर, विताय और काराज-पत्र रखेंगी जो  
अवधि प्रत्येक के समुल्लेख दिये गये सामग्री के अनुसार होयें।—

(१) पंचायत के कोष का बहीखाता

(२) प्रतिपत्रक (प्राजन्टर पत्र) रजिस्ट्रों

(३) कार्यवाहियों की बही

(४) रजिस्टर जिसमें दैवसी और दूसरे फारसों के सार

सामग्री और बदलियों की बही हो

(५) पंचायत के पत्र-व्यवहार और उसके बहरी निर

दिए नोटिसों का रजिस्टर

(६) निरीक्षण रजिस्टर

(७) हर रजिस्टर, वारियों और समर्थित पत्रों के सम्बन्ध में

जाने के एक साल के बाद लिखित होयें के रजिस्टर के सार

दिए जायेंगे।

१४ पंचायती अदालत द्वारा रखने जानेवाले रजिस्ट्रों—

पंचायती अदालत निम्नलिखित रजिस्ट्रों रखेंगी :—

( १ ) दीवानी नज़िरों का रजिस्टर ।

( २ ) अदालत माल की कार्यवाहियों का रजिस्टर ।

( ३ ) दीवानी नालिशों और फौजदारी मुकद्दमों के लिये अलग-अलग रूपों की रसीदबहियाँ ।

( ४ ) आज्ञापत्रों ( प्रोसेसेज ) और सम्मनों, जो तामील होने के लिये जारी किए गए हों या भेजे गए हों, का रजिस्टर ।

( ५ ) खूराम के खर्च का रजिस्ट ।

( ६ ) फौजदारी मुकद्दमों का रजिस्टर ।

( ७ ) जुर्माने का रजिस्टर ।

( ८ ) निरीक्षण की बही ।

( ९ ) पंचायती अदालत के कोष का बहीखाता ।

६५—अतिरिक्त रजिस्टर—इन रजिस्ट्रों के अतिरिक्त जो कि उक्त धाराओं में दिये जा चुके हैं प्रान्तीय सरकार जब कभी उचित समझे पंचायती अदालत या पंचायत को कोई और रजिस्टर या बही रखने का आदेश दे सकती है ।

६६—लेख-पत्रों की अवधि—दीवानी नालिशों, अदालत माल की कार्यवाहियों और फौजदारी के मुकद्दमों के रजिस्टर क्रमशः बारह, सात और पाँच वर्षों के बाद नष्ट कर दिये जायेंगे और दूसरे कागज़-पत्र और रजिस्टर तीन साल बाद नष्ट कर दिए जायेंगे ।

६६ ( अ ) जमा करने का स्थान—पंचायती अदालत के सब रजिस्टर, बहियाँ और सम्बन्धित कागज़-पत्र बन्द किये जाने के एक वर्ष के उपरान्त तहसील के कार्यालय में जमा कर दिये जायेंगे ।

६७—रजिस्ट्रों के प्रकार—जक्त नियमों के अनुसार नियत रजिस्टर और बहियाँ इन नियमों के साथ नत्थी कामों में होंगी; किन्तु प्रान्तीय सरकार अपने साधारण या असाधारण आदेश द्वारा इनमें परिवर्तन कर सकती है ।

## गाँव-पंचायत और पंचायती राजदालत के द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले कागज-पत्रों के सम्बन्ध में नियम

६८—(१) वार्षिक रिपोर्ट—पंचायत मिलने आर्थिक वर्ष के प्रपने कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष पहली जून से पहले नियत अधिकारी के पास भेजेगी। रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना होगी :-

- (१) पंचायत का विधान।
- (२) एक विवरण-पत्र जिसमें आर्थिक, सामान्य और अन्य चरों और उनका उपयोग दिखाया गया हो।
- (३) कागज-पत्र विवरण-पत्र जिसमें गाँव, कच्चा, दूर और चक का दिखाया गया हो।
- (४) वह आय में पौजदारी के मुकदमों के दिने करे जुर्मानों के अनिवार्य दूसरे जुर्मानों से प्राप्त हुई।
- (५) दूसरे गाँवों के होनेवाली आय।
- (६) व्यय ( ) आयी ( ) अरथायी।
- (७) भाग १४ और भाग १८ में बताये हुए प्रदेयों के लिये निधि के अर्धीन पूरे वर्ष के पंचायत द्वारा की हुई कार्यवाहियों और उनमें से कौन से प्रदेयों के पंचायत आवश्यक समझती है।
- (८) एक विवरण पत्र जिसमें ऐसी रखने दिखायी गई हो जो वर्ष के लिए रखने हुई हो और वह वर्ष में ही दिनांक में हो कि वह कभी रहने नहीं हुई।
- (९) एक रिपोर्ट जिसमें निर्माण और सम्पन्न के चले कार्य, निर्माण वर्ष पूरे दिने गए हो, बालू रे हो

किसी भावी योजना के साथ किये जानेवाले हों, दिखाये गये हों।

(१०) कोई अन्य आवश्यक कार्य।

६८ (२) पंचायत रिपोर्ट के साथ एक विवरण-पत्र फार्म नं० १ में जिसमें उस वर्ष की उसके आय और व्यय का व्योरा और उसके बैंकर का हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रमाण-पत्र दिया हो, नत्थी करेगी। यदि डाकखाने में धन जमा हो तो सभापति का हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण-पत्र नत्थी किया जायगा।

६९—अदालत के मुकदमों के हिसाब को भेजने का समय—अदालत नियत रजिस्ट्रों के फार्म में फौजदारी मुकदमों के सम्बन्ध में हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त किसी अफसर के पास अदालत माल की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में हाकिम परगना के पास, दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में उस मुंसिफ के पास, जिसकी अधिकार-सीमा में वह अदालत हों, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले सप्ताह में भेजेगी।

**पंचायत और उसके उप-समितियों के काम के निरीक्षण, देख रेख और नियंत्रण के लिये नियम**

७०—पंचायत-कार्यालय का निरीक्षण—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कोई अफसर या सदस्य या कोई ऐसा अफसर, जिसे सरकार ने नियुक्त किया हो और जिसे इस सम्बन्ध में कानूनी अधिकार दिया गया हो किसी पंचायत के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है। उसके निरीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट नियत अधिकारी को भेजी जायगी।

**निरीक्षण का अधिकार**

७१—पंचायत को निर्माणकार्य, रजिस्टर और लेखपत्र का निरीक्षण—पंचायत या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कोई सदस्य तथा अफसर और

कोई सरकारी अफसर जिसको हम सम्बन्ध में अधिकार दिया गया हो और सभापति या उप-सभापति की पहले से स्वीकृति लेकर सम्बन्धित सम्पत्ति का कोई सदस्य किसी निर्माण-कार्य को जो पंचायत के क्षेत्र में किया गया है, या जिसका रख रखाव पूर्णतया या आंशिक रूप में उसके द्वारा होता हो और किसी रजिस्टर, चट्टी या हिमाच या दूसरे दस्तावेज का जो पंचायत का हो या पंचायत या उसकी समिति के अधिकार में हो, निर्दिष्ट कर सकता है।

७२—जांच कराने का अधिकार—पंचायत का सभापति या उप-सभापति अधिकार-प्राप्त कोई सदस्य और सरकार या जिलाधिकारी कोई भी अधिकार-प्राप्त कोर्ट अफसर किसी प्रकार की जांच पंचायत के शासन के सम्बन्ध में कर सकता है और उस सम्बन्ध में सम्बन्धित अदालत की ऐसा आदेश गवाहों के नाम सम्मन भेज सकता है और हम ऐक्ट के किसी प्रावधान के लिये कोई दस्तावेज कागज प्रस्तुत करने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को बाध्य कर सकता है।

शासन-सम्बन्धी मामलों में दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिये गाँव पंचायतों से दस्तखत की जानेवाली पीस का नियत करने और उन प्रतिलिपियों के प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में की जानेवाली कार्यवाहियों के निर्णय करने का नियम

७३—दस्तावेजों की प्रतिलिपियों और इनका हस्तक्षेप—पंचायतों के दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के लिये प्रथम बार पंचायत के सभापति के पास भेजे जायेंगे। प्रतिलिपि बनाने का शुल्क की दरों के और उन

प्रतिलिपियों के स्वीकार करने के ढंग के सम्बन्ध में नियम १०७ से १११ तक में बताई हुई कार्यवाही की जायगी ।

## पंचायती अदालतों के जुडिशियल मिस्ट्रो और शांख-पंचायतों की शासन-सम्बन्धी कार्य- वाहियों के निरीक्षण के नियम

७४—मिस्ट्रो और कार्यवाहियों का निरीक्षण—इस सम्बन्ध में दिये हुए नियमों के अधीन सब न्याय सम्बन्धी मिस्ट्रो और पंचायतों की शासन-सम्बन्धी कार्यवाहियों का निरीक्षण किया जा सकेगा ।

### जुडिशियल मिस्ट्रो का निरीक्षण

७५—विचाराधीन जुडिशियल मिस्ट्रो का निरीक्षण—विचाराधीन मुकदमों या नालिशों या कार्यवाहियों के मिस्ट्रो का या जिनका निर्णय हो चुका है परन्तु जिनकी मिस्ट्रो पंचायत-कार्यालय में जमा नहीं की गई है, मुकदमे का कोई पक्ष निशुल्क निरीक्षण कर सकता है ।

कोई अन्य व्यक्ति जो उस मिस्ट्रो को देखना चाहे एक प्रार्थना-पत्र भेजकर, जिसमें यह बताया गया हो कि किस हित की रक्षा के लिये वह निरीक्षण करना चाहता है उस सभापति की स्वीकृति प्राप्त करेगा जिसकी अदालत में मुकदमा या नालिश या कार्यवाही विचाराधीन हो या अदालत के सरपंच की, यदि मुकदमे का निर्णय किया जा चुका हो, अनुमति प्राप्त हो जाने पर नियम ७७ में दिए हुए शुल्क के देने पर वह निरीक्षण कर सकता है । विचाराधीन मुकदमे या नालिश या कार्यवाही के मिस्ट्रो में निर्णय किये हुए मुकदमे की मिस्ट्रो, जो कि किसी विचाराधीन मुकदमे या नालिश या कार्यवाही के सम्बन्ध में मांगी जाय, सम्मिलित मानी जायगी ।

## पंचायत कार्यालय में जमा की हुई शिम्लों का जनता द्वारा निरीक्षण

७६—जमा किए हुए शिम्लों का निरीक्षण—पंचायत कार्यालय में जमा की हुई शिम्लों के निरीक्षण की आज्ञा सरपंच की अनुमति पर निरीक्षण शुल्क देने के बाद दी जायगी।

७७—शुल्क-निरीक्षण—शुल्क-निरीक्षण—शुल्क पाने के बाद ४ आना और उसके बाद के प्रत्येक घंटे या जगहों पर १०० के लिये २ आना प्रत्येक मिनट के लिये, जगह निरीक्षण किया जायगा। इस नियम के अधीन ली जानवाली प्रीम निरीक्षण के प्रार्थनापत्र के साथ नकद सभापति या सरपंच को दी जायगी जो उसे पंचायत कार्यालय में जमा करेगा और उसी समय नियत पारम में अपने हस्ताक्षर करके दे-रखी देगा।

७८—निरीक्षण का स्थान समय—निरीक्षण पंचायत कार्यालय में या पंचायती अदालत के कार्यालय में और पंचायत के कार्यालय के काम के घंटों में किया जायगा।

७९—निरीक्षण की रखता—एक ही निरीक्षण के लिये ३५ निरीक्षण-वाली करा गया है प्रत्येक पंचायत द्वारा रखने वाली प्रत्येक व्यापक जो निरीक्षण करना चाहें, निरीक्षण की के लिये ३५ तक की भरेगा।

८०—निरीक्षण पर साधारण निषेध और निर्देश—पंचायत निरीक्षण के समय कलम और दूसरी कलम के लिये का निर्देश निषेध है। पेंसिल और कगार बिना के लिये रखने का हमारी प्राप्ति के लिये रखने के काम में लाया जा सकता है, बल्कि निषिद्ध का कगार पर, जिसका निरीक्षण किया गया, कोई बिन्दु नहीं लगाया जायगा।



रिकार्ड का निरीक्षण केवल पञ्चायत या अदालत के, जैसी भी दशा हो, किसी अधिकारी की उपस्थिति में किया जायगा ।

८१—शासन सम्बन्धी कार्यवाइयों का निरीक्षण—किसी पंचायत की सब शासन-सम्बन्धी कार्यवाइयों का निरीक्षण सभापति की इच्छा से किया जा सकेगा । जुडिशियल मिस्ट्रो के निरीक्षण के लिये निर्धारित कार्य-विधि इनके सम्बन्ध में भी लागू होगी, यदि निरीक्षण की आज्ञा दे दी गई हो ।

**नियम जिसमें वह सीमा निर्धारित की गई है, जहाँ तक गाँव पंचायत और पंचायती अदालत से किये हुए जुर्माने छोड़े जा सकते हैं ।**

८२—जुर्मानों को छोड़ देना—यदि कोई जुर्माना जो किसी शासन सम्बन्धी मामले में किसी पंचायत द्वारा या किसी जुडिशियल मुकदमे में किसी अदालत द्वारा किया गया हो, वसूल न हो सकता हो, तो वह पंचायत या सम्बन्धित अदालत द्वारा छोड़ा जा सकता है, पर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस जुर्माने का रुपया किसी जुडिशियल मुकदमे में ५ रुपये से अधिक हो, तो पंचायत के सम्बन्ध में नियत अधिकारी या पंचायती अदालत की दशा में पहले से उच्च अदालत से पूर्व स्वीकृति लिये बिना नहीं छोड़ा जायगा । जिला पंचायत अफसर इसमें नियत अधिकारी है ( बजट २६ मार्च ४६ ) ।

## अध्याय ४.

## पंचायती अदालत, उसका विधान और कार्य-विधि

८३—पंचायती अदालत का अधिकांश क्षेत्र—विभिन्न मजिस्ट्रेट अदालत स्थापित करने के लिये तत्समीपता द्वारा जिले की प्रत्येक तहसील को सर्किलों में इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि जिले के गांव-सभाओं के क्षेत्र एक सर्किल में आ जाएं ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विभिन्न मजिस्ट्रेट को किसी बन्दर्ज जमीनानी अदालत का क्षेत्र अधिकृत करने का विशाल प्रतीत हो तो वह सरकार के पूर्व अनुमति से गांव-सभाओं को कम या अधिक कच्चे एक सर्किल बना सकता है ।

८३ अ—सरपंच का चुनाव—( १ ) किसी सर्किल में एक सभाओं में इस ऐक्ट की धारा ४३ के अन्तर्गत अदालत के पदों का चुनाव हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही उक्त पंचों को एक बैठक सम्मेलन द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके बाद, जिसमें सभा का पदपूर्ति मजिस्ट्रेट पहले से देगा, ऐसे समय व स्थान पर जो जिलाधीश नियत करे धारा ४४ के अन्तर्गत, किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्षता में जिसने जिला मजिस्ट्रेट से इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किया हो की कार्यवाही

८६—अ ( १ ) के अन्तर्गत नियम—सभा करने का (कोरने)—सभा में पंचायती अदालत के इस समय तक जहाँ तक हो सकेगा मजिस्ट्रेटों में आये सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है ।

( २ ) यदि कैपल एक ही समीपता प्रत्येक जिले में स्थित होता है तो वह चुनाव हुआ सरपंच स्वभावात् जिला मजिस्ट्रेट के पास

कि एक से अधिक उम्मेदवार प्रस्तावित और समर्थित हों तो वह उम्मीदवार जो सबसे अधिक संख्या में वोट पाता है चुना हुआ समझा जायगा। बैठक के सभापति का कोई वोट न होगा किन्तु ऐसी स्थिति में जब कि वोट बराबर हों, तब वह बैठक में प्रस्तुत पंचों की उपस्थिति में चिट्ठी डालकर चुनाव का निर्णय देगा।

( ३ ) सभापति चुनाव के श्चात् तुरन्त ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चुनाव का परिणाम प्रस्तुत करेगा।

८४—( अ ) विशेष बेंच की रचना—किसी मुकदमे की सुनवाई या निर्णय के लिये, जिसके फरीक-पक्ष और निपक्ष के लोग भिन्न-भिन्न अदालती पंचायत के क्षेत्रों के रहनेवाले हों, नियत अधिकारी को एक विशेष बेंच बनाने का अधिकार होगा जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों की अदालतों के कुछ पंच रहेंगे और वह बेंच का एक सरपंच नियुक्त करेगा। यह बेंच उस स्थान पर बैठेगी जो नियत अधिकारी द्वारा निश्चित की गई हो और उसकी कार्य-विधि अदालत के पथ-प्रदर्शन के लिये बनाए हुए नियमों के अनुसार होगी।

नोट—इसमें इन्सपेक्टर नियत अधिकारी है।

८४ ( ब )—यदि किसी नालिश, मुकदमा या कार्यवाही में किसी पंचायती-अदालत का सरपंच या उसका निकट-सम्बन्धी, उसका मालिक ( employer ) या नौकर ( employee ) या उसका करीबवार का कोई हिस्सेदार स्वयं एक पक्ष है या जिसमें इनमें से कोई व्यक्तिगत प्रयोजन रखता हो या ऐक्ट वी धारा ४६ के अनुसार सरपंच को बेंच बनाने में कोई कठिनाई हो, तो उक्त धारा के अन्तर्गत बेंच बनाने के बजाय सरपंच तुरन्त ही नालिश, मुकदमा या कार्यवाही, जैसी भी दशा हो, दायर होने के पश्चात्, नियत अधिकारी के पास सब कागज-पत्र भेज देगा, जो कि इन पर कार्यवाही करने के लिए एक बेंच बनाएगा।

नोट—इसमें इन्सपेक्टर नियत अधिकारी है।

नोट—नियम ८४ ( ब ) में सम्बन्धी का तात्पर्य है—पिता, प्रपिता, स्वश्वर, मामा या चाचा, पुत्र या पौत्र, दामाद, भर्ता, भतीजा, मामा या चाचा का पुत्र, साला, बहनोई, पत्नी, भर्ता का पुत्र या भतीजा ।

८५—पंचों के लिये योग्यता—कोई व्यक्ति, जो गांव-पंच का पंच चुने जाने योग्य है और जो हिन्दी पद और लिख सम्मति है, धारा ४३ के अधीन पंचायती अदालत का पंच होने योग्य समझा जायगा ।

८६—पंच या सदस्य द्वारा पद-ग्रहण की शपथ—जब भी के अधीन चुना हुआ प्रत्येक पंच और गांव पंचायत का अध्यक्ष सदस्य अदालत या पंचायत की, जैसी भी दशा हो पहिली बार पद ग्रहण करने की शपथ लिखे हुए ढंग से कमशः करने पद का शपथ लेगा ।

### शपथ

मैं..... ( नाम ) .....

शपथ लेता हूँ कि मैं सर्वप्रथम स्थापित भारत के शासन के प्रति श्रद्धा तथा पूर्णनिष्ठा रहूँगा और मैं समस्त प्रकार के लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और भय, पक्षपात, रंजित अथवा-दुष्कामना से विना प्रभावित हुए अदालती पंच । पंचायत के सदस्य के नाते अपने पद के सम्बन्ध में सच्चाई के साथ धारण करूँगा । अतः ईश्वर मुझे सहाय्य दे

**पंचायती अदालत की इजलासों के लिए नियम**

८७—अदालत की इजलास का समय और स्थान—अदालत पंचायती इजलास उस समय, उस स्थान और हर वेदव्यक्त रूप से करेगी जो नियत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो ।

नोट—जिला पंचायत अध्यक्ष हरमे नियत अधिकारी है सब २३ ३ ३३

८८—काल—अदालत मास में उतने दिन इजलास करेगी जितने दिन कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये आवश्यक हों, या नियत अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए हों। जिला पंचायत अफसर यहाँ नियत अधि.

८९—मामलों की अवधि की सीमा—प्रत्येक मुकदमा, मामला या अदालती कार्यवाही का उसके चलावे या उसे अदालत में आने से साधारण तौर पर छः सप्ताह के भीतर अन्तिम निर्णय किया जायगा। यदि उसका निर्णय इस अवधि में नहीं किया गया तो अदालत मामलों और मुकदमों के नियत रजिस्ट्रों में और नियत अधिकारियों को पेश की जानेवाली त्रैमासिक रिपोर्टों में विलम्ब के कारण लिखेगी। जिला पंचायत अफसर यहाँ नियत अधिकारी है।

९०—इजलास का सूचित किया जाना—मास के तीसरे सप्ताह में पंचायती अदालत अगले मास की अपनी बैठकों की तारीखें निर्धारित करेगी और उसकी सूची न्यायलय (अदालत) के बाहर लगा देगी।

९१—मामलों की साप्ताहिक सूची सूचना के लिये—मुकदमों नालिशों और कार्यवाहियों की एक साप्ताहिक सूची, जिसमें पक्षों के नाम और वह तारीखें दी गई हों, जिन पर वह सुने जानेवाले हों जनता और पक्षों की सूचना के लिये अदालत के कार्यालय के बाहर, लटका दी जायगी।

९२—सुनवाई की तारीख का पता निःशुल्क—किसी पक्ष या गवाह से उसके मुकदमे, मामले या कार्यवाही की सुनवाई की निश्चित तारीख का लिखित या मौखिक पता लगाने के लिये कोई फीस नहीं ली जायगी।

९३ (१)—धारा ७५ के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र—जैसे ही कोई प्रार्थना-पत्र मौखिक या लिखकर धारा ७५ के अधीन दिया जाय उसका संरांश नियत रजिस्टर में लिखा जायगा और प्रार्थों का हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिह्न रजिस्टर में करा लिया जायगा।



पूर्णतया स्वीकार कर लेता है तो पंचायती अदालत को कोई साक्षी लेना आवश्यक न होगा ।

(२) प्रत्येक पक्ष को अभियुक्त के अतिरिक्त दूसरे पक्ष व उसके गवाहों को ठीक उनके बयान के पश्चात् प्रश्नोत्तर करने की आशा देनी होगी । परन्तु पंचायती अदालत स्वयं या किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर किसी व्यक्ति का बयान, कार्यवाही के किमी. भी अवसर पर अंतिम निर्णय देने के पूर्व ले सकती है और ऐसी दशा में प्रत्येक पक्ष को इस प्रकार सुने जाने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने का अधिकार होगा ।

(३) किसी व्यक्ति को सुने जाने के पूर्व अभियुक्त के अतिरिक्त पंचायती अदालत उससे निम्नलिखित शपथ देगी—

मैं सत्य कहूँगा और सत्य के अतिरिक्त और कुछ न कहूँगा । अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे ।

९६—विधि का अनुगमन—जो कार्यवाही ऐक्ट के धारा ७३ से ८४ तक निहित की गई है और जो संयुक्त प्रान्तीय भूमिपर विधान (कानून मालगुजारी) के धारा ४० और ४१ में दी गई हैं उसका प्रयोग कार्यवाहीयों के निर्णय करने में किया जायगा ।

९७—किसी अधिकार प्रश्न पर जांच—उन मामलों में जिसमें पक्ष के व्यक्तिगत जाति-विशिष्ट विधान ( निजी कानून ) के अन्तर्गत स्वत्वाधिकार या अधिकार का प्रश्न उठता है अदालत केवल एक सरकारी (संक्षिप्त) जांच करेगी और दीवानी और व्यक्तिगत जाति विशिष्ट विधान (निजी कानून) पर अवलम्बित स्वत्वाधिकार के उल्लेख हुए प्रश्नों की जांच न करेगी । रुन्देह और कठिनाई की दशा में वह सब डिवीजनल अफिसर





अदालत नियत रजिस्टर ( फ़ार्म २ या ३ ) जैसी भी दशा हो, अपना विचार, निर्णय या आदेश संक्षेप में लिखेगा और पंचों के और पक्षों के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ चिह्न जो कि निर्णय के समय उपस्थित हों, ले लिये जायेंगे, रेकार्ड पर लगा दिया जायगा और नालिश की दशा में एक निर्णय ( decree ) नियत फ़ार्म नं० २४ के अनुसार बनाई जायगी ।

१०१—किसी पक्ष के मरने पर रुके हुए मामलों का निपटारा—यदि किसी फौजदारी के मुकदमे में पुलिस मुकदमे के अतिरिक्त विचाराधीन काल में अभियोगी या अभियुक्त मर जाता है तो मुकदमा समाप्त हो जायगा । परन्तु यदि किसी दीवानी की नालिश या माल की कार्यवाही के विचाराधीन काल में कोई पक्ष मर जाता है तो उक्त पक्ष का प्रतिनिधि नालिश या कार्यवाही का, जैसी भी दशा हो, ऐक्ट की धारा ८७ के अनुसार, पक्ष बनाया जायगा ।

१०२—किसी जुर्माने या क्षतिपूर्ति का चुकाना—किसी अदालत द्वारा किया हुआ जुर्माना या स्वीकार की हुई क्षतिपूर्ति की रकम सरपंच या पंचायत से इस सम्बन्ध में सवैध रूप से अधिकार दिये गए किसी सदस्य को या उस पंच को जिसे सरपंच ने अधिकार दिया हो, दिया जायगा और वह नियत फ़ार्म पर उस रुपये की रसीद देगा ।

१०३—अदालत की भाषा—अदालत और उसके सब पत्रों और रजिस्टर की भाषा हिन्दी होगी ।

१०४—अदालत की मोहर—प्रत्येक अदालत अपने नाम की एक मोहर रखेगी और सब कार्यवाहियों, आदेशों और प्रतिलिपियों पर उसका प्रयोग करेगी ।

रा ७५ के अधीन लोगों द्वारा दी जानेवाली  
 शुल्क और अदालत से काराजों की प्रतिलिपियों  
 और उन प्रतिलिपियों को देने के सम्बन्ध  
 में की जानेवाली कार्रवाई पर विचार  
 करने के लिये ली जानेवाली मुन्क  
 को नियत करने के नियम ।

१०५—अदालती शुल्क—फोई मुकदमा या कार्रवाई करने के  
 से पहले अदालत नीचे दी हुई शुल्क नकद लेगी—

दीवानी मुकदमे	ली जानेवाली प्रतिलिपियाँ
जब भागद्वे का विषय रुपये या मूल्य में १० रुपये से अधिक न हो	..... ५०० रुपये
जब वह १० रुपये से अधिक और २५ रुपये से अधिक न हो	... ५०० रुपये
जब वह २५ रुपये से अधिक और ५० रुपये से अधिक न हो	... ५०० रुपये
जब वह ५० रुपये से अधिक और २०० रुपये से अधिक न हो	... प्रत्येक १०० रुपये तक के अन्तरे में ५०० रुपये १ हजार
जब वह २०० रुपये से अधिक हो	... प्रत्येक १०० रुपये तक

उसके भाग के लिये

छः आना

(१) फौजदारी के मुकदमे

.....

आठ आना

(२) विविध प्रार्थना-पत्र, नालिश मुकदमा व  
कारवाई में

...

एक आना

पर प्रतिबन्ध यह है कि अदालत को अधिकार होगा कि यदि वह चाहे तो किसी फौजदारी के मुकदमे में फीस छोड़ सकती है, परन्तु उसे ऐसा करने के कारण फौजदारी के मुकदमों के रजिस्टर में नोट करने होंगे।

दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि जिस मामले में अदालत यह निश्चय करती है कि वह उसकी अधिकार सीमा में नहीं है, वह प्रार्थी द्वारा दी हुई फीस उसके प्रार्थना-पत्र के साथ, यदि वह लिखा हुआ हो, लौटा देगी।

१०६—इजरा के प्रमाण-पत्र पर शुल्क—उसी दर से जो कि नियम १०५ में दी हुई है, हिसाब लगाई हुई शुल्क अदालत डिग्रीदार से दूसरी अदालत को उसके इजरा का प्रमाण-पत्र लिखकर भेजने से पहले लगा ली जायगी और वह प्रमाण-पत्र के अधीन वसूल किये जानेवाले रुपये में जोड़ दी जायगी।

१०७—मिस्ट्रों के प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना-पत्र और उन पर शुल्क—अदालत या पंचायत के मिस्ट्रों की प्रतिलिपियों के लिये प्रत्येक प्रार्थना-पत्र सरपंच या समाजति या कोई दूसरा पंच या सदस्य के पास जिसको सवैध रूप से अधिकार दिया गया हो, एक आना शुल्क-सहित भेजा जायगा।

१०८—प्रतिलिपि का शुल्क—प्रतिलिपि का शुल्क-प्रत्येक २०० शब्दों या उनके भाग के लिये तीन आने की दर से लिया जायगा।

होए काग़ज़ों में अदालत अपने निर्णय की प्रामाणिक अदालती को  
उसे दूर पा जाने पर निःशुल्क दे सकती है ।

१०५—पेशगी व्यय—प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ कुछ प्रार्थना पेशगी) रुपया जो मैंने कुछ प्रार्थनापत्र के अनुमान के हिसाब से देना करने के लिये पर्याप्त है, देना चाहता हूँ।

११०—प्रतिलिपि दो तैयार तथा विनग्रा करणत—सबसे  
 बाद पंचायती, अदालत वा सभपंच या पंचायत या सभ नि गरी  
 कागज पर प्रतिलिपि तैयार करायेगा, अपने मोहर छापे, हस्ताक्षर के  
 ऊपर सच्ची प्रतिलिपि प्रमाणित करेगा और उसे प्रार्थी या सभ  
 समुचित रूप से अधिकांश दिने हुए प्रतिनिधि (जो) पंचायत में  
 और पेशगी रूपसे में से प्रतिनिधि के लिये निवाकने से सदा के लिए  
 रूपया शेष रहेगा वह भी उसे लीज दिया जायगा ।

१११—(क) मुख्य, अन्य और जुर्मानों का वर्ग करना - १९५५, १९६५ और १९७२ के अधीन रखे की जाने वाली एक ही नवद संपन्न या सभापति को दी जायेगी जो निम्नलिखित में से या पंचायती अदालत में, अभी भी दशा हो, क्या करेगा और गुरन्त एक नियत प्रार्थ में अपने हरतहर सहित एक २०० के

[illegible]

श्री-कौटिल्यः अथवा श्री-कौटिल्यः

पञ्चायती अदालत के कार्य की व्यवस्था करने  
 वाले नियम और सम्मनों और दूसरी कार-  
 वाइयों का पञ्चायती अदालत द्वारा  
 साधारण अदालतों को उनके  
 इजरा या पालन के लिये भेजने  
 की व्यवस्था करने और  
 उन पर कार्रवाई करने  
 के नियम ।

२१२—आह्वान-पत्र ( सम्मन ) और सूचना का विषय—  
 प्रत्येक आह्वान-पत्र ( सम्मन ) या सूचना ( नोटिस ) जो किसी अदालत  
 से जारी की जायगी, दो प्रतिनितियों और नियम फार्म ( फार्म नं० ४ )  
 में होगी । उसमें समय, तारीख और स्थान जहाँ उस व्यक्ति को उपस्थित  
 होना आवश्यक हो, लिखित रहेगा और यह भी लिखित रहेगा कि  
 उसकी उपस्थिति अपराधी, प्रतिवादी, डिग्री के देनदार, दूसरे पक्ष या  
 साक्षी या साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के प्रयोजन से या दूसरे  
 प्रयोजनों के लिए आवश्यक है । यदि कोई विशेष दस्तावेज पेश करना  
 है तो वह यथोचित रूप से ठीक-ठीक सम्मन या नोटिस में लिखा जायगा ।

११३—लेख-पत्र प्रस्तुत करने का आह्वान-पत्र—किसी व्यक्ति  
 के पास गवाही देने का सम्मन न भेजकर दस्तावेज पेश करने का सम्मन  
 भेजा जा सकता है और किसी व्यक्ति के लिये जो केवल दस्तावेज पेश  
 करने के लिये बुलाया जाय, यह समझा जायगा कि उसने सम्मन स्वी-  
 कर कर लिया है, यदि वह दस्तावेज पेश करने के लिये स्वयं उपस्थित  
 होने के बजाय उसे दूसरे से उपस्थित करवा देता है ।

११४—ऐसे व्यक्ति जिन्हें उपस्थिति से मुक्त किया गया हो—  
कोई अदालत ऐसे व्यक्तियों की गयाही देने के लिये न्यायालय में नहीं  
बुलायगी जो देश की प्रथा या मिथिल प्रोसीजर कोड, सन् १६८८ ई.  
के आदेशों के अनुसार न्यायालय में मध्य उपस्थित होने से मुक्त हैं ।

११५—आज्ञान-पत्र भेजना—यदि एक व्यक्ति, जिसके सम्पत्ति  
सम्पत्ति या नोटिस निकलनेवाला है अदालत की आभियानगीया के अन्तर्गत  
है तो नियम ११७, ११८ में बताई हुई धारणाई की जायगी ।

११६—भेजने की शक्त—यदि सम्पत्ति या नोटिस किसी एक या  
अन्य पर जारी किया जाता है तो पंचायती अदालत को अधिकार है कि  
मुकदमे के अतिरिक्त जो किसी पुनित अपराध से सम्बन्धित है, उसे  
प्रत्येक सम्पत्ति या नोटिस के लिये एक अलग शक्ति के अन्तर्गत  
पंचायत-कोष में जमा कर दी जायगी और आदेशानुसार, के अन्तर्गत  
दे दी जायगी ।

११७—सम्पत्ति ले जानेवाला—सम्पत्ति या नोटिस के अन्तर्गत  
तौर पर चीनीदार या आदेशानुसार के अन्तर्गत ले जायगी, परन्तु पंचायत  
पंच जो उसे जारी करने का आदेश देता है, उसके अन्तर्गत  
किसी दूसरे व्यक्ति से जारी करवा सकता है ।

११८—अधिकार क्षेत्र के अन्दर पहुँचाने की शक्ति—यदि  
पत्र या सूचना को सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायगा, यदि वह  
क्षेत्र या अंगुष्ठान्तर्गत दूसरी प्रतिलिपि पर लिखा जायगा । यदि वह  
व्यक्ति नहीं मिल रहा है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि वह  
इसे लेना नहीं चाहता है तो सम्पत्ति या नोटिस, आदेशानुसार  
कि वह आज्ञान-पत्र या सूचना इस अन्तर्गत के अन्तर्गत ले जायगी  
पर के किसी प्रौढ़ पुरुष को दे दिया जायगा, जो इस अन्तर्गत के अन्तर्गत  
भाग में लगा दिया जाय किन्तु वह व्यक्ति सम्पत्ति या नोटिस लेता है ।

११९—भोजन व्यय—किसी व्यक्ति को भोजन-व्यय नहीं दिया जायगा जो अदालत के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत रहता है।

१२०—अधिकार क्षेत्र के बाहर पहुँचाने की विधि—यदि किसी नालिश मुकदमे या कार्यवाही में अदालत की ओर से बुलाये जानेवाला व्यक्ति अदालत के अधिकार-क्षेत्र के बाहर रहता है तो अदालत आह्वान-पत्र डाक द्वारा या किसी और रूप से उस पंचायती अदालत या अन्य अदालत के पास, जिसके अधिकार-क्षेत्र में वह व्यक्ति जिसको आह्वान-पत्र दिया जानेवाला है रहता हो और ऐसी अदालत उसे उसी प्रकार पहुँचावा देगी जैसे कि वह उसी का आह्वान-पत्र हो और उसकी दूसरी प्रतिलिपि सम्बन्धित अदालत को लौटा देगी। यदि वह व्यक्ति जिसके नाम आह्वान-पत्र भेजा गया है, कोई साक्षी है तो अदालत उस व्यक्ति से जिसकी ओर से आह्वान-पत्र जारी किया जानेवाला है, यह चाहेगी कि वह आह्वान-पत्र जारी करने के पहले इन्हीं नियम के अनुसार साक्षी को दिया जानेवाला भोजन-व्यय जमा कर दे। भोजन-व्यय आह्वान-पत्र (सम्मन) पर लिख दिया जायगा और उपस्थित होने पर साक्षी को दिया जायगा।

१२१—नियम १२२ अन्तर्गत जारी किये गये आह्वान-पत्र (सम्मन) की विधि—नियम १२२ के अधिन अदालत की ओर से जारी किया जानेवाला आह्वान-पत्र (सम्मन) सम्बन्धित पंचायती अदालत को डाक-द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भेज दिया जायगा और उसमें यह लिखकर दिया जायगा कि उसे अदालत ने स्वयं अपने ओर से जारी किया है और यह कि भोजन-व्यय अदालत की ओर से साक्षी को उसके उपस्थित होने पर दिया जायगा।

१२२—पंचायत-कोष से भोजन-व्यय—यदि कोई अदालत किसी साक्षी को स्वयं अपनी ओर से आह्वान-पत्र भेजकर बुलाती है

और वह साक्षी उसकी अधिकार सीमा के बाहर रहता है जो वह सर्व्व के भोजन-व्यय पंचायती अदालत क्षेत्र में से हिये जाने की क्षमता रखती है।

१२३—किरसी साक्षी की तुलना में अर्द्धाधिकार क्षेत्र—— यदि अदालत किसी साक्षी को आपान-पत्र ( गारण्ट ) देकर किसी के अर्द्धाधिकार क्षेत्र रखती है यदि उसका मत में उसकी उपस्थिति किसी दूसरे के खिलाफ़, धन्य या असुविधा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती है। जो कि वर्तमान अवस्था में अनुमान योग्य।

१२४—भोजन-व्यय की व्याख्या——कानून के अन्तर्गत भोजन-व्यय दैनिक भोजन-व्यय तथा मार्ग-व्यय को ( २ ) रूप में वर्गीकृत किया है और साक्षियों को उनमें उन अधिकारियों से हिये जा सकते हैं जो उनको अदालत के सामने उपस्थित होने में समर्थ माने हैं।

१२५—यात्रा और दैनिक भोजन-व्यय और मार्ग-व्यय——दैनिक भोजन और मार्ग-व्यय साक्षी को है तथा यात्रा व्यय के लिए नीचे लिखी हुई दर से दिया जायगा :—

( १ ) दैनिक भोजन-व्यय——१२ आना से १५ आना तक प्रति दिन।

( २ ) यात्रा से आना करने के मार्ग पर प्रति दिन प्रति मील प्रति दिन। अधिक से अधिक ६ आना प्रति मील तक ही।

( ३ ) रेल के द्वारा होनेवाला मार्ग-व्यय——आवरे के दूरी के हिसाब से बिलाने या १॥।

( ४ ) यदि कोई सरकारी वर्गस्थानी या दफ्तर के अधिकारी सरकारी या दफ्तर या वर्गस्थानी साक्षी के रूप में अदालत में उपस्थित होकर हजारा जान तो हमने विचार-विचार के बाद सरकारी या वर्गस्थानी या दफ्तर के अधिकारी के रूप में दशा ही न माना जायगा। यदि इस रकम के अतिरिक्त सरकारी या वर्गस्थानी के अधिकारियों के लिए कोई नियम चले है तो विचार-विचार के बाद यात्रा-व्यय का निर्धारण चलेगा।



१२६—भोजन-व्यय और रसीद का रजिस्टर—भोजन-व्यय जमा किये जाने पर अदालत जमा करनेवाले व्यक्ति को एक रसीद देगी और उसी समय भोजन के व्यय के रजिस्टर रूपपत्र संख्या ६ में जमा करनेवाले का नाम और जमा किया हुआ रुपया लिखेगी। साक्षी के या भोजन-व्यय जमा करनेवाले के भोजन-व्यय का भुगतान करने पर, सरपञ्च या सदस्य, जिसकी उपस्थिति में रकम दी गई है, भोजन-व्यय के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा।

## धारा ८३ के अधीन अदालत द्वारा अपने अधिकारों को काम में लाने का नियम

१२७—जाँच करने का अधिकार—अदालत या उसका कोई सदस्य, जिसको इस सम्बन्ध में उचित रूप से अधिकार दिया गया हो, किसी मुकदमे या मामले के उचित रूप से निर्णय करने के सम्बन्ध में तथ्यों का निश्चय करने के लिये, स्वत्वाधिकार रखनेवाले या भूमि या भवन के मालिक, या उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि को, उस दशा में जब कि उस पर उसका अधिकार न हो, २४ घण्टे की सूचना देने के बाद, सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच किसी समय किसी भूमि या भवन पर प्रवेश कर सकता है। यदि भूमि ऐसे व्यक्तियों के अधिकार में हो, जो देश की प्रथा के अनुसार सर्वसाधारण के सम्मुख नहीं आते-जाते तो उनको हट जाने की उचित सूचना दी जा सकती है।

## डिग्री का इजरा

१२८—प्रार्थना-पत्र का इजरा करना—डिग्री या आज्ञा हो जाने के बाद, डिग्रीदार या आज्ञा पानेवाला वही शुल्क देकर जहाँ मौलिक मुकदमों या नालिश या कार्यवाही के लिये नियत है उस अदालत में डिग्री इजरा के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है, जिसने डिग्री या आज्ञा दी हो।

( २ ) अदालत दूसरे पक्ष के नाम चुनना देगी कि वह चुन सके  
 वो, जिसके लिये हिस्सी हुई है, या आज्ञा को दो दिन में  
 भीतर या ऐसी अधिक अवधि के भीतर हिस्से बढ़ (इष्टतम)  
 मोटिस को तारीख के बाद देना उचित समझे तो भीतर समय  
 में अधिक न होगी. आज्ञा कर दे या पालन करने में यदि  
 उचितचित्त समय के भीतर स्वयं सुपरीस न करे तो वह या  
 आज्ञा या पालन न हुआ हो तो फल केन्द्र ही आज्ञा को  
 की उपभाग ( २ ) के अनुमान परत हिस्से को बढ़ावे कि  
 या आज्ञा पालन करने के लिये सुनिश्चित करे. यदि  
 भेज दी जायगी और केन्द्रों को स्वयं न करे तो फल केन्द्र ही  
 हिस्सी हुई है. नाभिषा दायर होने की तारीख को फल केन्द्र  
 की स्वयं की प्राप्ति की तारीख तक फल केन्द्र ही  
 व्याज अदा करना होगा।

### परिभाषा ६

अपत्ति व लये रखना तथा उत्पत्ति व प्राप्त करना  
 आयत की सम्पत्ति प्राप्त करने, लपने, लपाना  
 में रखने और उत्पत्ति कराने तथा रखने  
 सम्पत्ति में कोई अनुपलब्धतादि करने  
 के लक्षितियों को निरस्यन्त  
 करने के निरस ।

१९९—शुद्धि की प्राप्ति—यदि यह देखा हो सके कि  
 जिनके कार्य के लिए किसी शुद्धि की आवश्यकता है तो वह कार्य

अधिकार होगा कि वह पञ्चायत की प्रार्थना पर जिसका समर्थन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के किसी प्रस्ताव द्वारा हुआ हो, भूमि-प्राप्ति सम्बन्धी ऐक्ट, सन् १८६४ ई० के आदेशों के अधीन ऐसी भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही करे और जब कि पञ्चायत उसके अधीन नियत की हुई क्षति पूर्ति कर दे तो वह भूमि पञ्चायत की सम्पत्ति हो जायगी जो कि भार रहित होगी और उसी उद्देश्य के लिये प्रयोग में लाई जायगी जिसके लिये ली गई थी ।

१३०—अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण—पञ्चायत को मान्य होगा कि वह अपनी कोई अचल सम्पत्ति यदि उसका वास्तविक मूल्य ५०० रुपये से अधिक हो, कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के बिना और ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जिनकी कमिश्नर स्वीकृति दे केवल पट्टे के द्वारा हस्तान्तरित करे और किसी प्रकार का अधिशुल्क न ले और दूसरी दशाओं में जिलाधीश पूर्व स्वीकृति ऐसे प्रतिबन्धों के साथ, जिनको वह लगाना उचित समझेगा, लेना अनिवार्य होगा ।

१३१—भूमि का नक्शा—ऐसी दशाओं में जब कि पञ्चायत को अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरित करने के लिए कमिश्नर या कलेक्टर की स्वीकृति की आवश्यकता हो, पञ्चायत अपने प्रस्ताव की रिपोर्ट रूप पत्र संख्या २३ पर भेजेगी और इसके साथ उस भूमि या उसके आसपास की भूमि आदि के मानचित्र की दो प्रतिलिपियाँ संलग्न होंगी ।

१३२—बिना अधिशुल्क के पट्टा—उस दशा में जब कि पञ्चायत ऐसी कोई अचल सम्पत्ति अधिशुल्क (प्रीमियम) के बिना पट्टे हस्तान्तरित करे, वार्षिक कर का कोई उचित रकम नियत किया जायगा और वह पट्टे की पूरी अवधि के भीतर देय होगी और पञ्चायत के प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किये बिना न तो कोई पट्टा दिया जायगा और न उसके देने के सम्बन्ध में कोई स्वीकार पत्र लिखा जायगा ।

पर प्रविष्टय यह है कि जब पट्ट की अर्धति दस वर्ग में आविष्ट हो  
लेकिन तीस वर्ग से अधिक न हो तो फलेवटन की पूर्ण संकुचन में होने  
जब कि ऐसी अर्धति तीस वर्ग से अधिक हो तो प्रविष्टय की पूर्ण संकुचन  
होनी पड़ेगी ।

१३३—नीलास या प्रस्ताव-पत्र (टेन्टर) द्वारा पट्ट—प्रस्ताव  
की मान्य होना कि यह अथवा कोई भी समान विना नीलास या प्रस्ताव  
पत्र माँगें (टेन्टर) साधारणतया पट्ट पर न लटकाए जायें अथवा यदि ऐसा  
कि टेन्टर न माँगे गये हों, प्रस्ताव की मान्य होना कि यह पट्ट की विना  
प्रस्ताव (आपार) स्वीकार करने के कारण और अधिक समान विना पट्ट के  
की यह नीति जिसके द्वारा ऐसा किया गया है ।

१३४—जिनाचीश या कमिशनर द्वारा प्रस्ताव—प्रस्ताव  
इन नियमों के अन्तर्धानुसार माँग प्रचारित की जायेगी कि प्रस्ताव  
रक्त के समान में फलेवटन या प्रविष्टय की पूर्ण संकुचन की अवस्था  
हो तो किसी ऐसे लेखन में जिसके द्वारा समान विना पट्ट की मान्य  
यह बात भी जिस ऐसी आदि कि कमिशनर या निरीक्षक की आज्ञा  
से ली गई है ।

१३५—नजूल भूमि—उन नियमों के अन्तर्धानुसार प्रचारित की जायेगी  
में निम्नलिखित कोई भी बिन्दु बनाये हैं नजूल की भूमि निम्नलिखित नियमों के  
अन्तर्गत प्रवृत्त किया जायगा ।

ऐसी सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो जिसके निम्नलिखित

नजूल की न हो और जो ताँद-पंचायत

की स्वामित्व में हो या उत्तरे

प्रदत्त में रखाई गई हो ।

१३६—प्रचल सम्पत्ति की रजिस्टर—प्रचल सम्पत्ति की रजिस्ट्रार  
होना कि यह सम्पत्ति सम्पत्ति १३६ के अन्तर्धानुसार प्रचारित की जायेगी

समस्त अचल सम्पत्ति का, जिसमें वृक्ष सम्मिलित हैं, एक रजिस्टर रखे जिसका वह स्वामी हो या जो उसके प्रबन्ध में रखी गई हो या जिस पर वह किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो ।

१३७—विभिन्न सम्पत्ति के लिये भिन्न-भिन्न रजिस्टर—ऐसी सम्पत्ति जिसकी पंचायत स्वामी हो, ऐसी सम्पत्ति जो पंचायत के प्रबन्ध में रख दी गई हो और ऐसी सम्पत्ति जिस पर पंचायत किसी पट्टे द्वारा अधिकार रखती हो रजिस्टर के अलग अलग भागों में क्रमानुसार लिखी जायगी ।

१३८—रजिस्टर का सामयिक निरीक्षण—पंचायत को मान्य होगा कि वह वर्ष में कम से कम एक बार नियत अधिकारी द्वारा नियत अवधि पर उपरोक्त रजिस्टर का निरीक्षण कराये, और निरीक्षक अफसर यह प्रमाणित करेगा कि “रिकार्ड” (रजिस्टर के इन्दराज आदि) वही हैं । इन्स्पेक्टर इसमें नियत अधिकारी है ।

१३९—हस्तान्तरण—सरकार की स्वीकृति और पंचायत के प्रस्ताव के बिना, ऐसी कोई अचल सम्पत्ति जिसकी पंचायत मालिक हो या जो उसके स्वामित्व में हो, विक्रय दान-पत्र या बन्धन, या लेन-देन के द्वारा हस्तांतरित न की जायगी ।

१४०—टेन्डरों को बुलाना और काम का ठेका देना—समस्त ठेके चाहे वह किसी कार्य के करने के लिये हों या किसी वस्तु के परिपूर्ण करने के लिये हों पंचायत द्वारा स्वीकार किये जायेंगे । और यदि ठेकों का मूल्य ५० रुपए से अधिक हो तो ठेके केवल प्रस्ताव-पत्र (टेन्डर) देने के पश्चात् ही स्वीकार किये जायेंगे और लिखित होंगे तथा उस पर समापति तथा पंचायत के एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे ।



करेगा और वह अधिकारी जिसको कि ऐसी सूचना दी गई है सूचना देनेवाले को एक रसीद देगा। कोई व्यक्ति जो बिना किसी पर्याप्त कारण के इन नियमों के अधीन रिपोर्ट न देगा पंचायती अदालत से जुर्माने के दंड का भागी होगा जो एक रुपये से अधिक न होगा।

१४४—चौकीदार द्वारा जन्म और मृत्यु की सूचना—चौकीदार का कर्त्तव्य होगा कि वह गांव-सभा के सभापति या उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति या सेक्रेटरी को प्रत्येक जन्म और मृत्यु जो कि पंचायत द्वारा सौंपे गये उसके क्षेत्र में हुई हो, के होने के दो दिन के भीतर सूचना दे।

### जल-कुम्भी आदि का हटाया जाना

१४५—जलकुम्भी को नष्ट करना—किसी पंचायत को अधिकार होगा और जब कि उसके क्षेत्र में रहने वाले प्रार्थना करें तो उसके लिये मान्य होगा कि वह किसी भूमि, आहाते या पानी की जगह जल-कुम्भी की उपज को रोकने के लिये उसको दूढ़े, हटा दे और नष्ट कर दे और उसे रोकने के लिए घेरों और रोकों को बनावे। पंचायत को अधिकार होगा कि वह उस जगह के रहनेवालों से इस काम का खर्चा बसूल कर ले जब तक कि इस उद्देश्य के लिये वहां के रहनेवाले बिना मजदूरी के काम करनेवालों का स्वयं प्रबन्ध न कर दें।

### मलिनता दूर करने (कन्सरवेन्सी) और पानों की सफाई के नियम

१४६ (अ)—स्वच्छ और स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारों का उपयोग—जब कभी कोई पंचायत अपने क्षेत्र की सफाई का प्रबन्ध और उसकी निगरानी अपने हाथ में ले ले और उसकी उत्तरदायी हो





( छ ) गांव की सीमा के भीतर सुअर पालने और रखने का निषेध कर दे : इसके अतिरिक्त कि वह उपयुक्त स्थानों या बाड़ों में रखे जायं ।

( ज ) गांव से २२० गज दूरी के अन्दर किसी आपत्तिजनक व्यापार की व्यवस्था करे या निषेध करे जैसा कि युक्तप्रान्तीय म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा २६६ ( २ ) ( जी ) में दिया हुआ हो ।

( झ ) खाद या कूड़ा या दूसरे आपत्तिजनक पदार्थों का ढेर करने या इकट्ठा करने का जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा तथा आराम के लिये हानिकारक हो, निषेध करेगी या उसका प्रवन्ध करेगी ।

१४७—पानी के प्रवन्ध के अधिकार—जब कभी कोई पंचायत अपने क्षेत्र के पानी का प्रवन्ध और उसकी निगरानी का प्रवन्ध अपने हाथ में ले ले और उसकी उत्तरदायी हो तो वह निम्नलिखित अधिकारों में से किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है:—

पंचायत को अधिकार होगा कि यह:—

( क ) खरीद, दान-पत्र या किसी और प्रकार से कोई तालाब, कुआँ, नदी, सोता प्राप्त करे और उससे पानी प्राप्त करने के लिये सुविधाएँ प्रदान करे ।

( ख ) सरकारी तालाब और कुएँ बनाए, उनकी मरम्मत कराये और उनको सुरक्षित रखे और समयानुसार इन तालों, कुआँ, नदियों और सोतों की सफाई का प्रवन्ध करे ।

( ग ) किसी महामारी फैलने के दिनों में किसी नदी का पानी पीने, घर के बर्तन धोने, कपड़े धोने या मवेशियों को पानी पिलाने के काम में लाने के सम्बन्ध में निषेध करे, और

( घ ) विज्ञप्ति प्रकाशित करके कुएँ और तालाब इत्यादि जल पीने के लिये, बरतन धोने के लिये, कपड़े धोने के लिये, अन्त्येष्टि



(२) जब की पंचायत इस नियम के अधीन सूचना तामील करने के लिये गांव के चौकीदार को नियुक्त करे तो पंचायत के लिये मान्य होगा कि वह चौकीदार को उक्त सूचना के साथ साथ एक आना प्रति सूचना (नोटिस) का शुल्क दे और उक्त फीस पंचायत कोष से दी जायगी।

१५०—सूचना को स्वीकार करना—प्रत्येक व्यक्ति जो ऐक्ट के अन्तर्गत या इन नियमों के अधीन निकाली गई सूचना की प्राप्ति की रसीद देना अस्वीकार करेगा वह पंचायती अदालत के आदेशानुसार जुर्माने के दंड का भागी होगा जो कि १० रुपये से अधिक न होगा।

## अध्याय ८

# योजना तैयार करना और निर्माण कार्य करना

## गाँव पंचायत के निर्माण कार्य के मानचित्र

## (नक्शा) तथा अनुमान तैयार करने के

## सम्बन्ध में और निर्माण कार्य

## करने और उनकी स्वीकृति

## के सम्बन्ध में नियम

### १—निर्माण कार्य का वर्गीकरण।

१५१—निर्माण-कार्य का वर्गीकरण—इन नियमों के उद्देश्यों के लिये निर्माण कार्य का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जायगा:—

(क) सामान्य निर्माण कार्य वह है जिसकी लागत १००० रुपये से अधिक न हो।



(२) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्जीनियरिंग विभाग के सभापति की अनुमति से बोर्ड का कोई अधीनस्थ कर्मचारी तैयार कर सकता है, पर प्रतिबन्ध यह है कि उक्त निर्माण कार्य की लागत २०० रुपये से कम और ५,००० रुपये से अधिक न हो, या

(३) कोई ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिशनर तैयार कर सकता है जिसके पास इस सम्बन्ध में कला कौशल सम्बन्धी योग्यता हो और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्जीनियर द्वारा स्वीकृत हो।

(ख) “स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण कार्य” की दशा में कोई भी ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिशनर तैयार कर सकता है जिसके पास इस सम्बन्ध में कला कौशल सम्बन्धी योग्यता है और जिसे ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्जीनियर द्वारा स्वीकृत हो।

(ग) वृहत् निर्माण कार्य की दशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का चीफ इन्जीनियर यदि वह कार्य स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण कार्य हो अथवा समुचित अनुभव वाला परामर्शदाता इन्जीनियर जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो।

### ३—विवरणपत्र और अनुमान की तैयारी की विधि।

१५३—अनुमानित व्यय तैयारी करने की विधि—(क) गांव पंचायत सामान्य और अल्प निर्माण कार्य के विवरणपत्र और अनुमान नियम १५२ (क) और (ख) के अधीन किसी भी साधन द्वारा तैयार करा सकती है।

(ख) नियत अधिकांशों के लिये मान्य होगा कि वह सम्भाव्य न बृहत् निर्माण कार्य के अनुमानित व्यय के सम्बन्ध में आदेशित साधन द्वारा, और ऐसे साधन ( प्रायः प्रारम्भिक साधन ) के प्रत्येक होने पर हस्ताक्षर के साथ निर्माण विभाग से, और यदि निर्माण कार्य "सम्पन्न" हो, तो सावजनिक व्यापक विभाग से, और इन्फ़ीनिटिव के द्वारा सम्भाव्य अनुमान विचारार्थ प्रेषित है, यात्रा इत्यादि के लिये निर्माण विभाग कि वह उक्त रिपोर्ट को स्वीकार करती है या नहीं। यदि वह स्वीकार कर ले, तो नियत अधिकांशों के लिये मान्य होगा कि वह साधनों में से किसी अन्तिम योजना मांसे । इन्फ़ीनिटिव लिये "स्वीकार" इसमें है ।

४—उन योजनाओं के सम्बन्ध में जहाँ जहाँ स्वीकृति, जिनके लिए प्रास्ताविक स्वरूप या प्रारम्भिक स्वरूपता न है ।

(नियत अधिकारी इस नियम में हैं इन्स्पेक्टर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत १००० रुपये से अधिक, किन्तु ५,००० रुपये से कम हो। ५,००० रु० से ऊपर की लागत के कार्यों के लिये संचालक पंचायत राज)

(ग) ऐसे अल्प या बृ.त् निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सबसे प्रथम पंचायत एक नियमानुक्रम प्रस्ताव द्वारा अनुमति देगी और उसके बाद उन्हें नियत अधिकारी के पास स्वीकृति के लिये भेजा जावगा। (नियत अधिकारी यहाँ पर इस प्रकार नियुक्त हो गये हैं जिला पंचायत अफसर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत १००० रु० से अधिक, किन्तु ५,००० रु० कम हो। ५,००० रु० से ऊपर की लागत के कार्यों के लिये संचालक पंचायत राज।)

(घ) ऐसे बृहत् निर्माण कार्य भी दशा में उसकी योजना यदि उसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (सार्वजनिक निर्माण विभाग) ने तैयार किया हो, नियत अधिकारी (प्रान्तीय शासन) के पास शासन प्रबन्धात्मक स्वीकृति के लिये भेज दी जायगी।

**५—उन योजनओं के सम्बन्ध में अनुमति और स्वीकृति, जिनके लिए प्रान्तीय सरकार ऋण या आर्थिक सहायता के रूप में धन दे।**

१५५—ऋण लेकर चलाई जानेवली योजनाएँ—(क) किसी सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माणकार्य के मानचित्र और अनुमानित व्यय, जिनके लिये पंचायत ने नियमनुक्रम प्रस्ताव द्वारा अनुमति दे दी हो, उन्हें नियत अधिकारी (जिला पंचायत अफसर) के पास भेज दिया जायगा

और जो पल्लव, हेतु धीरे ( मार्गज्ञान स्वयम्भूत ) के लक्षण प्रकटमानक स्वीकृति के लिये अपने विचारों सहित मार्गज्ञान स्वयम्भूत समिति के सेक्रेटरी के पास भेज देगा ।

(२) दत्त निर्माणकार्य की दशा में यह आवश्यक है कि अपने अपने समय अनुमानित व्यय तैयार करा लिया जाय और उसे संलग्न की जायिक गदायता या द्रुत गहन प्रयत्नों सहित निरूपित की जायिक समर्पित द्वारा मार्गज्ञान स्वयम्भूत समिति के पास भेज देना । यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने अपने अनुमानित व्यय के समक्ष में मार्गज्ञान स्वयम्भूत समिति के पास भेज देना । जो चाहे के बाद अन्तिम या अन्तिम बोधना की जायिक प्रकटमानक स्वीकृति और अनन्त प्रकट के लिये समस्त आधिकारी ( निर्माणकार्य ) द्वारा मार्गज्ञान स्वयम्भूत समिति के पास भेज देना ।

६—निर्माणकार्य का प्रारम्भ ।



न हो, पंचायत स्वयं कर सकती है या उसे नियम १५२ (क) और (ख) उल्लिखित साधनों द्वारा दैनिक श्रम ठेके द्वारा करा सकती है।

(ख) ऐसे समस्त सामान्य निर्माण कार्य, लागत १५२ रुपये से ऊपर हो और अल्प निर्माणकार्य, नियम १५२ के आदेशों के प्रतिबन्धों सहित, उस साधन द्वारा किये जायेंगे तथा उनकी नाप-जोख होगी, जिनके सम्बन्ध में ऐसे नियत अधिकारी (इन्सपेक्टर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत ५०० रु० से अधिक, किन्तु १,००० रु० से कम हो) ने अपनी अनुमति दे दी हो, जो अदायगी के सम्बन्ध में नाप-जोख का आधार निर्धारित करेगा।

(ग) ऐसे समस्त बृहत् निर्माणकार्य, नियम १५२ के आदेशों के प्रतिबन्धों सहित, उस साधन द्वारा किये जायेंगे तथा उनकी नाप-जोख होगी, जिसके सम्बन्ध में ऐसे नियत अधिकारी ने अपनी अनुमति दे दी हो, जो अदायगी के सम्बन्ध में नाप-जोख का आधार निर्धारित करेगा। (नियत अधिकारी इसमें हैं, जिला पंचायत अफसर उन कार्यों के लिये, जिनकी लागत १,००० रु० से अधिक, किन्तु ५,००० रुपये से कम हो। ५,००० रुपये से ऊपर की लागत के कामों के लिये संचालक पंचायत राज)

(घ) यदि किसी बृहत् निर्माण कार्य को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के चीफ इंजीनियर को सौंपा जाय, तो सम्बन्धित डिपार्टमेंट उस निर्माण-कार्य को पूरा करेगा, उसकी नाप-जोख करेगा और उसकी रकम अदा करेगा।

## ८—निर्माण कार्य का-निरीक्षण।

१५८—अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य—(क) गांव पंचायत द्वारा निर्माण किये गये। प्रत्येक सामान्य, अल्प बृहत् निर्माण



( ख ) प्रारम्भिक योजना के लिये दिया जानेवाला शुल्क अनुमानित खर्च का  $\frac{1}{2}$  प्रतिशत होगा, पर प्रतिबन्ध यह है कि साधारण ट्यूबवेल की योजना के सम्बन्ध में कम से कम शुल्क ५० रुपया होगा । यदि बाद कोई अन्तिम रूप से पूर्ण योजना तैयार की जाती है, तो प्रारम्भिक योजना के लिये दिया गया शुल्क अन्तिम रूप से पूर्ण योजना के शुल्क में से काट लिया जायगा ।

( ग ) अन्तिम रूप से पूर्ण योजना के लिये दिया जानेवाला शुल्क निम्नलिखित दर से लगाया जायगा—

अनुमानित व्यय	जब पड़ताल या चौरसाई नहीं की जाती	जब पड़ताल या चौरसाई की जाती है
१०,००० रुपये तक	.... एक प्रतिशत	... दो प्रतिशत
२०,००० रु० के ऊपर	... $\frac{1}{2}$ प्रतिशत	... एक प्रतिशत

प्रतिबन्ध यह है कि योजना के तैयार करने में कोई पड़ताल या चौरसाई की ऐसी मिस्लें जो पहले से मौजूद हों काम में लाई जा सकती हैं, किन्तु और अधिक पड़ताल या चौरसाई करने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के चीफ इन्जीनियर इस बात की पुष्टि करेंगे कि पड़ताल चौरसाई की वर्तमान मिस्ल किस अंश तक उपयोगी है और उस अनुपात से अपनी शुल्क घटा सकते हैं, जितना वर्तमान पड़ताल और चौरसाई की मिस्ल के कारण उनकी चौरसाई या पड़ताल का खर्च कम हो गया हो ।

( घ ) जब प्रारम्भिक या अन्तिम रूप से अनुमानित व्यय परिवर्तित दर और मूल्य के अनुसार दुहराया जाता है तो उस दशा में जब कि अनुमानित व्यय में कमी कर दी जाय तो पहले से दिये जा चुके शुल्क में कोई कमी नहीं की जायगी । किन्तु यदि योजना में ही परिवर्तन किया



१६१—सार्वजनिक स्वास्थ्यविभाग के साधारण निर्माण कार्य का शुल्क—निर्माण-कार्य की प्रारम्भिक या अन्तिम रूप से पूरा जयाना के लिये दिये जानेवाले शुल्क की दर और साधारण निर्माण-कार्य के निर्माण का शुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य द्वारा वह होगा जो नीचे दिया गया है—

- (क) व्योरेवार योजना और अनुमानित खर्च को तैयार करने के लिये ... २ प्रतिशत
- (ख) काम के निरीक्षण के लिये ... २ प्रतिशत
- (ग) काम कराने के लिये जिसमें निरीक्षण भी सम्मिलित है ... ७ प्रतिशत

वाटर वर्क्स (पानोघरों) और दूसरे स्वास्थ्य सम्बन्धी कामों के निर्माणकाल में मानचित्र और विवरण तैयार करने में गाँव पंचायत के पथ प्रदर्शन के लिये निमम

१६२—त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इंजीनियर, जन स्वास्थ्य विभाग को—पंचायत जिसकी प्रान्तीय सरकार से सीधे या जन स्वास्थ्य बोर्ड के द्वारा जल-प्रवन्ध (वाटर वर्क्स) के लिये या दूसरे स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्माण-कार्य के लिये अनुमानित खर्च ₹ ३,००० रुपया या अधिक की आर्थिक सहायता या त्रैमासिक ऋण मिला है वह इन



# नियम १६२ के अधीन नियत किया हुआ रूप पत्र

सरकारी सहायता द्वारा किये जानेवाले  
निर्माण-कार्य की प्रगति का विवरण  
.....को समाप्त होने वाली  
तिमाही के.....द्वारा\*

१—पंचायत का नाम

२—निर्माण-कार्य का नाम

३—अनुमानित व्यय

४—विवरण

५—पंचायत की स्वीकृति देनेवाला प्रस्ताव  
संख्या.....

६—जन-स्वास्थ्य बोर्ड की स्वीकृति देनेवाला प्रस्ताव  
संख्या..... दिनांक .....

७—प्रान्तीय फंड से प्राप्त धन  
(क) .....रु०

(ख) ऋण.....रु०

८—पहली त्रैमासिक के अन्त तक किया व्यय.....रु०

९—.....को समाप्त होनेवाली त्रैमासिक में हुआ व्यय.....रु०

१०—विवरण भेजने की तारीख तक का व्यय.....रु०

११—कार्य-क्रम के अनुसार व्यय ..... रु०

❖ जिसकोउक्त काम दिया गया हो ।





हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त निर्माण-कार्य.....  
 .....की मास ..... १६ .....को पूर्ति हुई और  
 अधिकारियों द्वारा स्वीकृत परिवर्तनों के अतिरिक्त स्वीकृत योजना में  
 कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।  
 हस्ताक्षर.....  
 पंचायत के मंत्री .....  
 दिनांक.....  
 संख्या.....  
 चीफ़ इजीनियर सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के पास भेजा गया.....  
 जिलाधीश, संयुक्त प्रान्त, सूचना के लिये।  
 पंचायत के सभापति  
 दिनांक.....

## अध्याय ६

### कर्मचारियों की नियुक्ति इत्यादि

### गाँव पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति

### इत्यादि के नियम

१६५—अफसर, उसके अमले तथा वेतन, भत्ते और कर्तव्यों की सूची—गाँव पंचायत अपनी बैठक में एक प्रस्ताव द्वारा सेक्रेटरी के अतिरिक्त अन्य अफसरों और कर्मचारीवर्ग की एक सूची आय-व्यय (बजट) के नियमों के अधीन, तैयार करेगी और उनको दिये जानेवाले वेतन, भत्ते और उनके कर्तव्यों को निश्चित करेगी।



उसके द्वारा निश्चित वेतन दर तथा अन्य प्रतिबन्धों के अधीन एक ही सेक्रेटरी की नियुक्ति की आज्ञा दे सकता है।

नोट—सेक्रेटरी हर जिले में बनाये जा रहे हैं। उनको प्रारम्भिक वेतन ५० रु० मासिक है।

(२) जहां कहीं प्रान्तीय शासन उपनियम (१) के अधीन आज्ञा दे; वहां की गांव पंचायतों के प्रधान नियत विधि से, निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में एक व्यक्ति को चुनेंगे और ऐसा चुना हुआ व्यक्ति सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया जायगा, परन्तु एसी नियुक्ति निर्धारित द्वारा स्वीकृत होगी जिसे अधिकार होगा कि उसे स्वीकृत करे या अपने लिखित कारण देकर ऐसे प्रस्ताव को संशोधित या अस्वीकृत कर दे। (नियत अधिकारी यहाँ एक समिति, जिसका अध्यक्ष जिला बर्ड का प्रधान तथा सदस्य, डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर स्कूल्स और जिलाधीश या उसका मनीनीत कोई अफसर होगा)

१६९—सेक्रेटरी के कर्त्तव्य—सेक्रेटरी का यह कर्त्तव्य होगा कि—(१) वह पंचायत के विधान, नियमों तथा उपनियमों और प्रान्तीय सरकार या निर्धारित अधिकारी के समस्त आदेशों या अधिकारों का स्वयं पालन करे और देखे कि पंचायत और पंचायत अदालत उनका पालन करती हैं और इस सम्बन्ध में यदि उनसे कोई असमाधानी अथवा त्रुटि हो तो उससे उनको सावधान करे।

(२) पंचायत तथा प्रधान या उपप्रधान के उन आदेशों का पालन करे जो ऐक्ट के अन्त में दिये गये हों और अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे और अन्य अधिकारों का प्रयोग करे जो विधान अथवा किसी अन्य नियम के द्वारा उनके लिये निर्दिष्ट किया गया हो या उनको प्राप्त हो।

१७०—अन्य कर्मचारी के लिये योग्यता—पंचायत या अदालत का जो दूसरा कर्मचारीवर्ग आवश्यक है उसे हिन्दुस्तानी मिडिल



१७४—किसी सेवक के पदका अवधि काल—पंचायत और अदालत के कर्मचारी की नौकरी की अवधि उस समय तक समाप्त नहीं होगी—

(क) जब तक उसका त्यागपत्र उस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत नहीं हुआ है, जो उसके स्थान पर दूसरे की नियुक्ति करने का वैधानिक अधिकार रखता है।

(ख) जब उसका वेतन १५ रु० प्रतिमास से अधिक है उसने कम से कम तीन महीने की सूचना ऐसे अफसर को दे दी है और इससे कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों की अवस्था में एक मास के वेतन के बराबर घन दे दिया हो।

(ग) उसने जब उसका वेतन १५ रु० से अधिक है पंचायत को ३ मास का वेतन अदा कर दिया है या उसे भेज दिया है और यदि वेतन १५ रु० मासिक से कम है तो एक मास के वेतन के बराबर रकम दे दी है या

(घ) ऐसे अधिकारी द्वारा जो उसके स्थान पर नियुक्ति का वैधानिक अधिकार रखता है उसे कम से कम तीन महीने की सूचना या सूचना के स्थान पर ३ महीने का वेतन उसको उस दशा में देता है, जब उसका वेतन १५ रु० से अधिक है और यदि वेतन १५ रु० मासिक से कम है तो १ महीने से कम की सूचना या सूचना में एक मास के वेतन के बराबर रकम देता है।

## कर्मचारियों को छुट्टी और अवकाश ग्रहण करने के नियम

१७५—अवकाश और स्थानापन्न स्थानों का प्रवन्ध—पंचायत और अदालत के कर्मचारियों की छुट्टी की स्वीकृति और उनकी



## कर्मचारियों की सूची, जिनकी अवस्था आर्थिक वर्ष में ६० वर्ष से अधिक हो जायगी

संख्या	अफसर का	अगले ३१ मार्च	अगले ३१ मार्च	भेजनेवाले
	वेतन पद, नाम	को अवस्था	को नौकरी का वर्ष	अधिकारी
				की व्यक्ति को
				रखने या अव-
				काश ग्रहण करने
				के सम्बन्ध में राय
				और सिफारिश ।

वर्ष मास

वर्ष मास दिन

### प्राविडेंट फंड

१७७—प्राविडेंट फंड—यदि कोई पंचायत प्राविडेंट फंड के नियम स्वीकार करे तो उसके लिये आवश्यक होगा कि वह उन नियमों और अनुशासनों का जो इस सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पथप्रदर्शन के लिये बनाये गये हैं, पालन उन संशोधनों के साथ करे जो नियत अधिकारी ( संचालक पंचायतराज नियत है ) उन नियमों और अनुशासनों में करे ।

— — — — —

## अध्याय १०

नोटः--आयुर्वेद, परिचर्येण रचितः यः प्रकृतः  
पञ्चायनी स्यात्कालः १०० वर्षाः  
आयुः प्रोक्तः ।

पञ्चायन योषः श्री गङ्गा प्रीतः  
कश्यपः प्रकृतः



१७९—रोकड़ बाकी और स्थायी पेशगी धन—(१) पंचायत कोष का रोकड़ बाकी साधारण तथा सबसे निकट के पोस्ट आफिस सेविंग बैंक या पड़ोस के किसी कोऑपरेटिव बैंक में या निर्धारित अधिकारी की स्वीकृति से किसी स्थानीय महाजन ( बैंकर ) या किसी अन्य व्यक्ति के यहां अथवा पंचायत के नाम से पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट के रूप में रक्खा जायगा । ( हाकिम परगना इसमें नियत अधिकारी हैं । )

पर प्रतिबन्ध यह है कि कोई रकम जो २५ रुपये से अधिक न हो सभापति के पास चालू खर्च के लिये स्थायी अग्रिम ( पेशगी ) के रूप में रखी जा सकती है और यह रकम विशेष अवस्था में निर्धारित अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।

( २ ) यदि ऐसी रोकड़ किसी स्थानीय महाजन ( बैंकर ) या किसी अन्य व्यक्ति के पास रक्खी गई हो तो :—

( १ ) ऐसे बैंकर या व्यक्ति की साख उसके पास रुपया जमा करने के पूर्व जांची और प्रमाणित की जायगी और प्रति वर्ष एक बार निर्धारित अधिकारी द्वारा उसके ऋण चुकाने की क्षमता की पुष्टि करेगा ।

( २ ) रूप-पत्र संख्या १२ के अनुसार एक पास बुक रक्खी जायगी और ऐसे महाजन ( बैंकर ) या व्यक्ति के पास वह हर बार जमा करने या निकालने के लिये भेजी जायगी । वह पास बुक में निकाले हुए या जमा किये हुए रुपये जैसी भी दशा हो लिखेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा । पास बुक में प्रतिमास का हिसाब बन्द किया जायगा और रोकड़ बाकी शब्दों और अंकों में लिखी जायगी और ऐसे बैंकर या व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर होगा ।

( ३ ) पास बुक या पोस्ट आफिस कैश सर्टिफिकेट जो भी हो सदैव सभापति के पास रक्खा जायगा ।



१८३—कर वसूल करने या वहियों के भरने के लिये वंचित व्यक्ति—किसी ऐसे व्यक्ति से जो ऐसे बैंक के कारबार में काम करता हो, जिसके यहां कोष जमा हो उसको पंचायत कोष का कर वसूल करने या पंचायत-कोष की वहियों को भरने के लिये न तो कहा जायगा और न उसे ऐसा करने की आज्ञा दी जायगी ।

१८४—हिसाब-किताब की भाषा व रखने में सावधानी—हिसाबों और रजिस्ट्रों में अंक हिन्दी में लिखे जायेंगे । हिसाब की वहियों और रजिस्ट्रों की जिल्द मजबूत होनी चाहिए और प्रयोग में लाने के पूर्व उन पर पृष्ठ-संख्या डाल देनी चाहिये ।

१८५—शुद्धियों की पुष्टि करना—हिसाबों के अंकों को शुद्ध करने के या परिवर्तन करने में स्वच्छता के साथ लाल स्याही का प्रयोग किया जायगा और संशोधन और परिवर्तन करने वाला व्यक्ति उसकी पुष्टि करेगा । साधन-लेख ( वाउचर ) के परिवर्तनों और संशोधनों की पुष्टि रुपया पानेवाला व्यक्ति करेगा, और रोज़बही में सभापति या ऐसे दूसरे अफसर द्वारा उनकी पुष्टि होगी जो स्थीकृति अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से इस प्रयोजन के लिये नियुक्त हों, रजिस्ट्रों, मानचित्रों, चेकों, साधन-लेखों ( वाउचरों ) या किसी प्रकार के हिसाब में अंकों या अक्षरों को मिटाने या उन पर दूसरे अंक या अक्षर लिखने की आज्ञा किसी भी दशा में न दी जायगी । ( इन्स्पेक्टर नियुक्त अधिकारी है । )

### हिसाब की जांच

१८६—हिसाबों की सामयिक जांच—फंड ( कोष ) के हिसाब की जांच का प्रान्तीय सरकार के आदेशों के अनुसार निश्चित अवधियों पर नियत अधिकारी ( इन्स्पेक्टर ) द्वारा प्रबन्ध किया जायगा ।

१८७—हिसाब की जांच के बाद कार्यवाही—हिसाब की प्रत्येक जांच के पश्चात् नियत अधिकारी की आज्ञानुसार, प्रधान सभापति को



जिसका उल्लेख रूप-पत्र संख्या १६ में किया गया है। इसमें नामों का पूरा व्यौरा होगा और स्तम्भ ३ में वेतन और छुट्टी का भत्ता जो उस महीने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये मांगा गया हो, चाहे वह लिया गया हो या न लिया गया हो अलग-अलग दिखाया जायगा और स्तम्भ ४ में वह धन दिखाया जायगा जो न लिया गया हो। परन्तु जो बाद में दिये जाने के लिए रोक लिया गया हो। स्तम्भ ५ में वह धन दिखाया जायगा जो प्रत्येक कर्मचारी के लिये लिया गया हो। जब वेतन केवल महीने के किसी भाग के लिये लिया जाय तो बिल में कर्मचारियों के नामों के सामने, वह दर, जिसके अनुसार वेतन लिया गया हो, और जितने दिन के लिये लिया गया हो लिखा जायगा। अस्थायी कर्मचारी वर्ग का वेतन अलग पत्र में बनाना चाहिये और जिसकी स्वीकृति से बनाया गया हो उसका उल्लेख करना चाहिये। साधारण मासिक पत्र में बकाया वेतन नहीं लेना चाहिये परन्तु उसके लिये अलग पत्र बनाना चाहिये और उसमें उस पत्र का उल्लेख करना चाहिये जिसमें वह रकम शामिल नहीं की गई थी या रोक ली गई थी।

## मार्ग-व्यय आकस्मिक खर्च के समान लिया जायगा

(२) वेतन का पत्र या उसकी एक प्रतिलिपि भरपाई (एक्वीटेंस रौल) के समान काम में लाई जायगी और जब कर्मचारियों को वेतन बांटा जाय तो उसी पर प्रत्येक व्यक्ति की रसीद ली जायगी।

नोट—नियत अधिकारी (जिला पंचायत अफसर) को अधिकार होगा कि वह सभापति को गांव-पंचायत के कार्य के सम्बन्ध में यथार्थ मार्ग व्यय के हेतु इतनी रकम तक स्वीकृत करे जो दू सरे दर्जे के सरकारी कर्मचारी को मार्ग व्यय के लिये मिल सकती हो।



( २ ) प्रत्येक आर्थिक वर्ष के अन्त में पंचायत के प्रधान और अदालत के सरपंच को मान्य होगा कि उन कर्मचारियों के काम और चाल-चलन के बारे में लिखें जिनके चाल-चलन के स्मृति-पत्र ( केरेक्टर रोल ) रखने हों । ये लोग उसमें दोष, दंड, प्रशंसा, अथवा पारितोषिक को भी लिखेंगे जो वर्ष के भीतर, किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा दिया गया हो ।

### आकस्मिक व्यय

१९२—आकस्मिक व्यय का हिसाब—आकस्मिक व्यय में कर्मचारी-वर्ग पर होनेवाले व्यय के अतिरिक्त सब व्यय सम्मिलित है । सब आकस्मिक व्यय जो स्थायी पेशगी रकमों ( एडवान्स ) में से किये जायं वह स्थायी पेशगी रकम के हिसाब के रजिस्टर में जो रूप-पत्र नं० १८ में रखा जायगा, लिखे जायंगे । यदि रुखा चेक के द्वारा दिया जाय तो वह सीधे ग्राम रोकड़बही में दिखाया जायगा ।

### अग्रिम धन ( एडवान्स )

१९३—स्थायी अग्रिम धन—प्रेसीडेंट ( प्रधान ) या उसकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा सदस्य, जिसे इस सम्बन्ध में गांव-पंचायत के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया गया हो, एक स्थायी अग्रिम धन जो ५ रुपये से अधिक न होगा, ऐसे छोटे-मोटे व्यय के लिये, जिसकी अदायगी खजांची से रुपया मिलने से पहले तुरन्त करनी पड़ती है, अपने पास रखेगा ।

१९४—वार्षिक स्वीकृति—प्रधान ( प्रेसीडेंट ) या सदस्य जिसके पास स्थायी अग्रिम धन हो प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को एक ऐसी रसीद में अपने हस्ताक्षर करने होंगे कि उक्त धन उसके पास अमानत है और वह उसका हिसाब देगा ।





में ऐसे सदस्य के सामने जिसे पंचायत के प्रस्ताव द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किया गया हो, रखना चाहिये और यदि मांग ठीक हो, आशा-नुसार हो, हस्ताक्षर सही और ठीक स्थान पर हो, तो वह भुगतान के लिये वाउचर के अन्त में आदेश लिख देगा और अपने हस्ताक्षर बना देगा। पंचायत के कर्मचारी-वर्ग के वेतन के विलों पर भुगतान का आदेश पंचायत का सभापति देगा।

१९८—अदायगी की रसीद—भुगतान के आदेश के वाउचर में लिखे जाने और उसके पास किये जाने के प्रधान पंचायत-कोष से रकम निकालेगा और कर्मचारी को भुगतान कर देगा।

प्रत्येक अदायगी के लिये पानेवाले के यथार्थ हस्ताक्षर लिये जायेंगे।

१९९—जब लेन-देन किये जायें, तो प्रधान या सदस्य जिसे इस सम्बन्ध में गांव-पंचायत ने नियुक्त किया हो ग्राम रोकड़बंदी रूप-पत्र सं० ६ को प्रतिदिन बन्द करेगा, उसका योग लगाएगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। प्रत्येक मास के अन्त में इसे पासबुक से मिलाना चाहिये और ठीक कर लेना चाहिये और किसी अन्तर के होने पर ग्राम रोकड़बंदी के फुटनोट में उसे स्पष्ट कर देना चाहिये और उसका हिसाब देना चाहिये। वही को निर्धारित अधिकारी (इन्स्पेक्टर) के सामने ऐसे स्थान और ऐसी तारीख पर जिसे वह नियत करे कम से कम तीन महीने में एक बार निरीक्षण के लिये भेजना चाहिये।

## औजारों और मशीनों का रजिस्टर

२००—औजारों और मशीनों (प्लान्टों) का रजिस्टर रखना—औजारों और मशीनों का एक रजिस्टर रूप-पत्र सं० १७ में रक्खा जायगा, जिसमें वह सब चीजें जैसे औजार और मशीन, लैम्प, लैम्प के खम्भे, सीढ़ियां आदि जो पंचायत के स्टॉक-बुक में न हों,



प्रयोग में आने वाले तमाम रूप-पत्रों ( फार्मों ) की रक्खी जायगी।  
स्टाक की जांच ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे प्रधान आदेश दे ६ महिने में  
होनी चाहिये और निरीक्षण की बातें लिखी होनी चाहिए।

## कार्यालय का आदेश रजिस्टर ( आफिस-आर्डर-बुक )

२०३—आदेश रजिस्टर ( आर्डर-बुक )—गांव पंचायत को  
एक कार्यालय-आदेश-रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें साधारणतया समस्त  
नियुक्तियां, तरक्की, छुट्टी, मुअत्तिली, जुर्माने, कार्यालय का प्रबन्ध  
और आदेश आदि लिखे जावें। आदेश-रजिस्टर को पूर्ण और ठीक  
रखने का उत्तरदायित्व प्रेसीडेंट ( प्रधान ) पर होगा।

## वाउचरों की फाइल सुरक्षित रखना

२०४—वाउचरों का भरना—प्रत्येक महीनों के वाउचरों में  
क्रमानुसार सख्या डालनी चाहिये और उन्हें गार्ड-फाइल में रखकर  
पंचायत के कार्यालय में जमा कर देना चाहिये, उन्हें पत्रावलियों  
( मिसली ) में जमा नहीं करना चाहिये।

## वाउचरों और रजिस्ट्रों का नष्ट किया जाना

२०५—वाउचरों आदि के रखने का अवधिकाल—वाउचरों,  
रजिस्ट्रों और दूसरे रूप-पत्रों को, जो इन नियमों के अधीन निर्धारित किये  
गये हैं, सम्बन्धित अवधि से सम्बन्ध रखने वाली हिसाब की जांच की  
त्रुटियों के ठीक किये जाने के पश्चात् नीचे दिये ढंग पर रखना या छ्वांटना  
या नष्ट करना चाहिये—

क्रम-संख्या	परामर्श
१	आयुर्वेदसंग्रह ( २५३३ के. ए. ए. )
२	भारत निधायिका की माहिती
३	भारत और उसके लोग ( १९०० )
४	भारत का भूगोल ( १९०० )
५	भारत का इतिहास
६	भारत का भूगोल
७	भारत का भूगोल
८	भारत का भूगोल
९	भारत का भूगोल
१०	भारत का भूगोल
११	भारत का भूगोल
१२	भारत का भूगोल
१३	भारत का भूगोल
१४	भारत का भूगोल
१५	भारत का भूगोल
१६	भारत का भूगोल
१७	भारत का भूगोल
१८	भारत का भूगोल
१९	भारत का भूगोल
२०	भारत का भूगोल

जिले के गांव-पंचायत और पंचायती अदालतों के लिये छपवा ले परन्तु जब तक छपे हुए रूप-पत्र न हों तब तक गांव-पंचायत और पंचायती अदालत, जैसी भी दशा हो, ऐसे रूप-पत्री को अपने कार्यालय में सादे कागज पर बनवा लेवे।

### पब्लिक वर्क्स रजिस्टर

२०७—पब्लिक वर्क्स रजिस्टर—पंचायत-कोष से किये जाने वाले हर काम का अनुमान, जैसे ही वह स्वीकृत करने वाले अफसर द्वारा स्वीकृत कर दिया जाय, पब्लिक वर्क्स क्लर्क इनचार्ज पब्लिक वर्क्स के रजिस्टर में, जो रूप-पत्र संख्या २१ में रक्खा जायगा, लिख लिया जायगा। इस रजिस्टर में हर काम के लिये एक अलग पृष्ठ रक्खा जायगा।

### पत्रों ( विलों ) की जांच और उनका भुगतान

२०८—कार्यों का पत्र ( विल )—जैसे-जैसे काम की प्रगति हो समय-समय पर काम का व्यौरा पब्लिक वर्क्स के रजिस्टर ( फार्म ) में लिखा जायगा और जब ठेकेदार पत्र ( विल ) पेश करे तो वह पहले उस अफसर के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जाय, जिसके निरीक्षण में कार्य हो रहा हो। यह अफसर उस पत्र ( विल ) की जांच अपने रजिस्टर से करेगा और तब उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा और या तो उसकी भुगतान अपनी स्थायी अग्रिम धन-राशि ( पेशगी रकम ) से कर देगा या पंचायत-कोष के कार्यालय में भेज देगा जहां जैसा कि साधारणतया किया जाता है, सीधे ठेकेदार को रुपया दे दिया जायगा।

### काम पूरा होने का प्रमाण-पत्र

२०९—प्रमाण-पत्र का विवरण—इससे पहले कि किये गये काम की अंतिम रूप से सम्पूर्ण भुगतान कर दी जाय प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य, जिसे इस सम्बन्ध में गांव-पंचायत के प्रस्ताव



## अध्याय ११

### आय-व्यय (फाइनेन्स)

#### आय-व्ययक (बजट)

२१३—अनुमान—प्रत्येक पंचायत आनेवाले वर्ष की पहली अप्रैल से आरम्भ होनेवाले वर्ष के लिये नियत रूप-पत्र (ग) में अपनी आय और व्यय का (बजट) अनुमान तैयार करेगी और उसे गांव-सभा की खरीफ की बैठक के सामने रखेगी।

२१४—यथार्थ और अनुमानित व्यय—इसी प्रकार प्रत्येक गांव-पंचायत को मन्य होगा कि रबी की सभा में गत ३१ मार्च को समाप्त होनेवाले आर्थिक वर्ष का वास्तविक व अनुमानित आय-व्यय विवरणों सहित उपस्थित करे।

#### अदालत के लिये पूंजी का निर्धारित करना

२१५—अदालत का आय-व्ययक (बजट)—धारा ३६ के अनुसार पंचायत अपने आय-व्ययक में पंचायती अदालत के कर्मचारी वरग के कार्यालय और अन्य सब व्यय के लिये पर्याप्त धन का विधान करेगी और उसी प्रकार अपने आय में अदालत द्वारा लगाये गये शुल्क तथा जुर्माने को सम्मिलित करेगी जिसको वह नियम १११ (ब) के अनुसार प्राप्त करेगी।

२१६—पंचायती अदालत का आय और व्यय—पंचायती अदालत गांव सभा के खरीफ मीटिंग के दो मास पूर्व अपने क्षेत्र के प्रत्येक गाँव पंचायत में आनेवाले आर्थिक वर्ष के लिये आय और व्यय का अनुमानित आय-व्ययक अनुमान भेजेगी।

## कम से कम काम चालू बकाया व भिन्न-भिन्न व्ययके लिये पूंजी अलग करना

२१७—पंचायत के पास न्यूनतम नकद (बकाया)—पंचायत यथार्थ में एक रकम नकद बकाया अपने पास रखेगी जो उसकी साधारण वार्षिक आय के १।१० से कम न होगी । नियत अधिकारी ( जिला पंचायत अप्रसर ) किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी गांव-पंचायत को, किसी विशेष परिस्थिति के होने पर इस नियम की प्रतिबन्धता से मुक्त कर सकता है ।

२१८—विभिन्न मदों के अन्तर्गत पंचायत के व्यय—पंचायत अपनी वार्षिक आय से शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरी मदों पर, जिन्हें नियत अधिकारी (जिला पञ्चायत अप्रसर) निर्धारित करे, व्यय करने के लिये अलग अलग धन-राशि निश्चित दर में रखेगी ।

२१९—सभा और पंचायत के बीच वातचीत का द्वार—सभा अपने आदेशों और प्रस्तावों को धारा ४१ (२) के अधीन प्रेसी-डेन्ट (प्रधान) द्वारा पंचायत के पास भेजेगी, परन्तु यदि सभा और पंचायत में मतभेद हो और उनका समाधान धारा ४१ की उपधारा (३) के अधीन सुधारों और पुनर्विचार द्वारा न हो सकता हो, तो मामले को निर्धारित अधिकारी ( जिला पञ्चायत अप्रसर ) के पास भेजा जायगा जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

(ग) आय-व्ययक उस समय तक कार्यान्वित न होगा जब तक कि उसे नियत अधिकारी स्वीकृत न कर ले जो स्वीकृति देने से पहले उसमें सुधार कर सकत है, परन्तु वह उसे स्वीकृत न करेगा यदि उसमें नियत कम से कम चालू बकाया न रक्खा गया हो या कि जैसा उसने निर्धारित किया हो उसके अनुसार धनराशि अलग-अलग न रखी गयी हो ।



## कर-निर्धारण तथा धन की वसूली

२२०—कर लगाने का ढंग—(१) यदि घारा ३७ के अधीन पंचायत किसी कर के लगाने का प्रस्ताव करे, तो उसे मान्य होगा कि वह सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये चाहे हुग्गी पिठवाकर या अपने क्षेत्र के विशेष स्थानों पर लिखित सूचना लगाकर या दोनों प्रकार से प्रस्ताव के उद्देश्य की घोषणा करे और ऐसी घोषणा की तारीख से १५ दिन के अन्दर उनसे आपत्तियां भी मांगे। प्रस्ताव पर आई आपत्तियों सहित उस बैठक में विचार किया जायगा, जो इस प्रयोजन के लिये बुलाई जायगी। यदि कर लगाने का निर्णय हो जाय, तो विरोधों के सहित यदि कोई हो, पंचायत द्वारा नियत अधिकारी (जिला पंचायत अफसर) के पास उसका स्वीकृति प्राप्त करने के लिये भेजा जायगा।

(२) निर्धारित अधिकारी का अधिकार होगा कि वह उक्त प्रस्ताव को और अधिक विचार करने के लिये वापिस कर दे या ऐसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के स्वीकृत कर ले। यदि वह संशोधन, जो निर्धारित अधिकारी ने दिये हों विशेषता (महत्त्व) रखते हों, इसके पहले कि पंचायत उसे अंतिम रूप से अंगीकार कर ले, आपत्तियों के लिये संशोधित प्रस्ताव के प्रयोजनों को फिर से उसी प्रकार घोषित किया जायगा जिस तरह कि ऊपर बताया गया है।

(३) नियत अधिकारी का अधिकार होगा कि वह प्रत्येक ऐसे प्रस्ताव में जिसे वह स्वीकृत करे उस तिथि का उल्लेख करे जिस तिथि से उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित कर लागू होगा।

(४) गांव-पंचायत अपने कर्मों व दातव्य धन को या तो अपने एक सदस्य द्वारा या टैक्स कलेक्टर द्वारा वसूल करेगी, जो या तो मासिक वेतन पर रखे जायेंगे या निर्धारित शुल्क (कमीशन) पर जैसा कि निर्धा-

रित अधिारी निश्चित करे। ऐसे सदस्य या टैक्स कलेक्टर को अपने कर्त्तव्य की नकद जमानत जमा करनी होगी जिनकी पंचायत द्वारा निर्धारित हो।

२२१—व्यवसायों पर निर्दिष्ट दर लाइसेन्स देना—जिस पंचायत को अधिकार होगा कि प्रस्ताव द्वारा यह बात अधिनियम में है कि कोई व्यक्ति तोलाई करनेवाले, पल्लेदार, शकर याफ करनेवाले या शकर के व्यापारी, अनाज के व्यापारी, कपड़े के व्यापारी या निर्यात के लिये कोई गाड़ी रखने या कामे करनेवाला उस समय तक न करेगा जब तक कि वह उसके लिये ठीक वार्षिक शुल्क अदा करे। अनुमति (लाइसेन्स) न ले ले, जो नीचे दिये हुए दरों से अधिक न हो—

(क) तोलनेवालों, व्यापारियों और पल्लेदारों के लिये ₹ २० वार्षिक

(ख) अनाज, कपड़ा और चीनी मण करने या ऐसा

करनेवालों और व्यापारियों के लिये ₹ २० वार्षिक

(ग) बिराये पर चलनेवाली गाड़ियों के मालिक ₹ २० प्रति वर्ष प्रति गाड़ी

(२) उभरोवत अनुमति ( लाइसेन्स ) के नतिबिबत अनाज और कपड़े के व्यापारी और शकर के व्यापारी द्वारा याफ करनेवाले और कोई ऐसे दूसरे व्यक्तियों के लिये जो ऐसे दूसरे कामे करते हों जो निर्धारित अधिकारी (इन्स्पेक्टर) नियत करे या यात अनुमति की जा सकती है यदि पंचायत इस प्रकार का प्रस्ताव रखेगा करे कि वह अपने ऐसे ही वार्षिक आय पर टैक्स अदा करे, परन्तु ५०० रु० से कम की जिना कपड़ा पर टैक्स न लगाया जायगा और किसी ऐसी वार्षिक आय पर, जो ६०० रु० से कम हो, टैक्स की शरह ₹ पाई १० रु० और ६०० रु० से ऊपर परन्तु १,२०० रु० से कम प्रति १०० रु० या उसके किसी अंश के लिये

६ पाई प्रति रुपया और १,२०० रु० से ऊपर प्रति १०० रुपया या उसके किसी अंश के लिये १ आना प्रति रुपया से अधिक न होगी।

**तौलाई करनेवाले पत्तेदार और ऐसे गाड़ा के मालिक पर, जो किराये के लिये हों, (टैक्स)**

**कर-निर्धारण और उसकी वसूली के नियम**

२२२—अनुमति ( लाईसेन्स ) के लिये प्रार्थना पत्र—प्रत्येक व्यक्ति को मान्य होगा कि उसे तारीख से १५ दिन के अन्दर जिस तारीख को कर देना उसके लिये आवश्यक हो जाय, सेक्रेटरी को अनुमति ( लाईसेन्स ) के लिये एक प्रार्थनापत्र दे। प्रार्थना-पत्र देनेवाला वह अवधि भी लिखेगा जिसके लिये अनुमति मांगी गई हो, यदि कर की रकम प्रार्थना-पत्र के साथ-साथ न प्राप्त हो, तो सेक्रेटरी एक पत्र तैयार करायेगा और प्रार्थी के सामने पेश करायेगा और नियमों के अधीन निर्धारित तरीके पर उक्त कर वसूल करेगा।

२२३—अनुमति (लाईसेन्स) या विल्ले के रखने और जमा करने का अधिकार—प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिये जिसके पास ऊपर बताये हुए नियम के अनुसार अनुमति हो, अनिवार्य होगा कि—

(१) सब समय जब वह अपना धन्धा कर रहा हो अपना अनुमति पत्र या ऐसा विल्ला रखे जो पंचायत उसे उसके खर्च पर देगी।

(२) किसी दूसरे व्यक्ति को अपना विल्ला न दे।

(३) अपना अनुमति-पत्र या त्रैज ( विल्ला ) निरीक्षण के लिये उपस्थित करे जब भी प्रधान, सेक्रेटरी या पंचायत का सदस्य या पंचायत का कोई ऐसा दूसरा अफसर या कर्मचारी जिसे इस बारे में नियमानुकूल अधिकार दिया गया हो उससे ऐसा करने के लिये कहे।

(५) अनुमति की अवधि के पूरा होने के ४८ घंटे के अन्दर अन्तर्-चैज ( विल्ला ) पंचायत के कार्यालय में वापस कर दे ।

## दंड

उन अधिकारों को काम में लाकर जो ऐक्ट की धारा ६८ में प्रदान किये गये हैं, प्रान्तीय सरकार यह आदेश करती है कि इन दिनों में किसी आदेश का उल्लंघन होने पर जुर्माना या दंड प्रशासकीय कोड द्वारा दिया जायगा जो १० रुपये तक हो सकता है ।

२२४—समान, भूमि समान अथवा भवन पर वारंवारता—  
(१) जब धारा २७ (१) के अधीन कर निर्धारित कर लगा गया हो तो पंचायत प्रत्येक वर्ष के आरम्भ के बाद जितनी जल्दी हो सके, अक्टूबर १४ में कर देनेवालों की और घरों, भवनों या भूमियों के जो सूचीबद्ध हो चुके हों, स्वामियों या उन पर अधिकार रखनेवालों की एक सूची तैयार करेगी और कर निर्धारित करने का काम आरम्भ करेगी । घरेलू भवनों पर कर निर्धारित करने की दर उनके वार्षिक भाड़े के मूल्य के १ प्रतिशत से अधिक न होगी । उन व्यक्तियों पर जो निर्धनता के कारण कोई कर नहीं दे सकते हैं, कर निर्धारित नहीं किया जायगा । कर निर्धारण सभा के क्षेत्र में जन साधारण के सामने घोषित कर दिया जायगा, और निर्धारित कर की सूची किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिन पर कर लगाया गया हो, और जो इसे देखना चाहता हो जिसे किसी हुकूम से दिखाई जायगी, और वह पंचायत के कार्यालय में भी लटक ही जायगा और किसी स्थानीय समाचारपत्र में प्रकाशित की जायगी ।

(२) २१ दिसम्बर की समाप्त होनेवाले वर्ष की, जो कर-निर्धारण की तिथि से पहले हो आय या लाभ पथारम्भ कर निर्धारण के आदेश समने जायगे ।

( ३ ) जब कोई व्यक्ति सभा के क्षेत्र की सीमा के भीतर एक से अधिक व्यापार या धन्धा स्वयं या विभिन्न नामों से करता हो, तो ऐसे सब साधनों से प्राप्त होने वाली वार्षिक आय या लाभों के योग पर कर लगाया ( निर्धारण किया ) जायगा !

( ४ ) पंचायत किसी ऐसी आपत्ति पर जो कर निर्धारण की घोषणा की तिथि से या कर निर्धारण के प्रकाशित होने की तिथि से जो भी बाद की हो १५ दिन के भीतर उसके विरुद्ध प्रस्तुत की जाय, विचार करेगी ।

( ५ ) ऐसी आपत्तियों पर यदि कोई हों, जो प्रस्तुत की गई हों विचार हो जाने के बाद कर निर्धारण की सूची में यदि आवश्यक हो, तो संशोधन किया जायगा और सरपंच तथा दो पंच उस पर हस्ताक्षर करेंगे । सूची की एक प्रतिलिपि संशोधनों के सहित, यदि कोई हों, फिर से उसी स्थान पर घोषित की जायगी और निर्धारित अधिकारी ( जिला पंचायत अधिकारी ) के पास भेज दी जायगी ।

२२५—कर के विरुद्ध अपील—कोई व्यक्ति जो निर्धारित किये हुए अपने कर से असन्तुष्ट हो, निर्धारित अधिकारी ( जिला पंचायत अधिकारी ) के सामने कर निर्धारण की सूची के नियम २२४ ( ५ ) के अधीन दोबारा प्रकाशित होने की तिथि से ३० दिन के भीतर, फिर से विचार करने के लिये प्रार्थनापत्र दे सकता है ।

२२६—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का निर्णय—( १ ) अपील करने के लिये नियत की हुई अवधि के समाप्त होने पर या नियम २२५ के अधीन किसी अपील पर निर्धारित अधिकारी द्वारा विचार हो जाने के बाद ऐसी भी दशा हो, जिला बोर्ड या तो कर निर्धारण की सूची की जैसी कि वह पहले-पहल तैयार हुई हो या संशोधित की गई हो अस्वीकृत कर सकता है या उस पर ऐसे परिवर्तनों के साथ जिनको वह उपयुक्त समझे स्वीकृति दे सकता है ।

( २ ) इसके उपरान्त कर निर्धारण सूची दोहगढ़ जायगी और दोहराये हुए कर निर्धारण की घोषणा पंचायत द्वारा प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर के पहले ही सबके सामने की जायगी ।

२२७—टैक्स का रजिस्टर और इसका गामयिक संग्रह—  
( १ ) पंचायत एक देय कर और संग्रह रजिस्टर बनाने की दायित्व संख्या १५ में होगा और कर मासिक, त्रैमासिक, षट्मासिक या वार्षिक आधार पर जो भी अच्छा समझा जाय, संग्रह किया जा सकता है । और यदि कर मास, त्रैमास, षट्मास या वर्ष के आरम्भ होने के बाद जैसी भी दशा हो, १५ दिन के भीतर चुकाया न जाय तो वह देय कर समझा जायगा । इस नियम के प्रयोजन के लिये वर्ष पहली अप्रैल के और वर्ष के त्रैमासिक पहिली अप्रैल, पहली जुलाई, पहली अक्टूबर और पहिली जनवरी से प्रारम्भ होंगे ।

( २ ) यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर, कर या शुल्क देने से बचने का यत्न करेगा तो उस पर जुर्माना किया जायगा जो १० रुपये तक हो सकता है ।

२२८—कर न देने वालों की सूची—यदि कच्चा या खाली इच्छा से करों को उनके देय शेष हो जाने के पहले ही न दें तो पंचायत होने लगी की एक सूची जितने कर न दिया हो, अपनी तहसील के तहसीलदार के पास तीन-तीन महीने के अन्तर से उन विधियों पर भेजेगी, जो तहसीलदार शेषों की राशियों को अधिशेष महसुसगी के रूप में वसूल करने के उद्देश्य से नियत करे ।

२२९—अप्राप्य करों को माफ कर देना—पंचायत का अधिकार है कि वह अप्राप्य धन राशियों को जो राजस्व राशियों में अधिक न हो, नियत अधिकारी ( 'डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर ऑफ़ रेव्यू' ) स्वीकृति से, बही खाते से माफ कर दे ।

२३०—सरकार या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सम्पत्ति पर कर लगाने का अधिकार—किसी ऐसे घर, भवन या भूमि पर जो सरकार या जिला बोर्ड की हो और रहने के काम में न लाई जाती हो, किसी प्रकार का कर निर्धारण नहीं किया जायगा किन्तु सरकार या जिला बोर्ड पर पंचायत को कर के स्थान पर ऐसी राशि देने का दायित्व रहेगा यदि जिला मैजिस्ट्रेट किसी दशा में ऐसा करने का आदेश दे, जिसको वह समय-समय पर उपयुक्त और उचित समझकर नियत करे।

२३१—घर, भवन या भूमि के मालिक या काम में लानेवाले दोनों में से एक से कर लेने का निर्णय—जब किसी घर, भवन या भूमि पर जो सरकार या जिला बोर्ड की हो और रहने के काम में लाई जाती हो, कर निर्धारित किया जाय तो वह कर स्वामी या रहनेवाले के द्वारा, जैसा भी सरकार या जिलाबोर्ड निश्चय करे दिया जायगा।

२३२—व्यापार या धन्धा शुरू या बन्द करने की सूचना—एक निश्चित अवधि तक प्रत्येक व्यक्ति को, जो सभा के क्षेत्र में कोई व्यापार या धन्धा करना आरम्भ करे या बन्द करे, पंचायत के प्रधान या मंत्री को इस बात की लिखित सूचना इस प्रकार से काम आरम्भ करने या बन्द करने के ३० दिन के भीतर देनी होगी।

२३३—व्यापार या धंधे के हस्तान्तरण या नाम बदलने की सूचना—प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर कर या लाइसेन्स शुल्क लगता हो और जो या तो अपने व्यापारी संघ का नाम बदले या अपने व्यापार या धन्धे की प्रकृति बदले या अपना व्यापार करने का स्थान या व्यापार का हस्तान्तरण करे इस बात की लिखित सूचना ऐसे परिवर्तन या हस्तान्तरण करने के ६० दिन के भीतर देनी होगी।

२३४—कर की वापिसी—कोई व्यक्ति जिसने कोई कर या नुमांत शुल्क पूरे आधे वर्ष के लिये दिया हो और जिस पर ऐसे

अवधि के भीतर कर या लाइसेन्स शुल्क देने का दायित्व न रहे, उद्योग नियमों का पालन करते हुए, कर या शुल्क की आनुमानिक राशि के वापस पाने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जो पंजीयनों वापस की जायंगी वे केवल पूरे-पूरे महीनों के सम्बन्ध में ही की जायेंगी महीने से कम समय की अवधि की उपेक्षा की जायगी ।

### दंड

उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो इस विधान की धारा १८ द्वारा दिये गये हैं, शासन यह आदेश करती है कि नियम २३१ और २३२ के आदेशों का उल्लंघन होने पर दोषी को पंचायत अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत दंड दिया जायगा जो १० रुपये तक हो सकता है ।

## अध्याय १२

### विधि

### विद्यालय, पुस्तकालय और औषधालयों की स्थापना

२३५—प्रारम्भिक शिक्षालय—प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, संरक्षण और प्रबन्ध उन नियमों के अनुसार उनके प्रादेशिक परिवर्तन के साथ किया जायगा जो सरकार ने इस सम्बन्ध में शिक्षा बोर्ड के विचार बनाये हैं सिवाय उनके भवनों के निर्धारित नियमों के ।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा स्थापित अथवा सहायता प्राप्त वर्तमान प्राथमिक स्कूलों का पूरा व्यवसायिक और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर आज के समान ही रहेगा ।



२३६—वाचनालय, पुस्तकालय व औषधालय—(क) पंचायत अपने कोष के अनुसार, अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय, वाचनालय या औषधालय स्थापित कर सकती है और चला सकती है और तदनुरूप जनता से दान लेकर धन एकत्र कर सकती है और अपने कोष से भी धन दे सकती है।

(ख) पुस्तकालय और वाचनालय प्रारम्भिक विद्यालय से संलग्न रहेंगे और विद्यालय के प्रधान अध्यापक के अधिकार में रखे जायेंगे जिसको उस सम्बन्ध में विद्यालय के समय के अतिरिक्त काम करने के उपलक्ष्य में उपयुक्त मासिक भत्ता दिया जायगा।

२३७—प्रारम्भिक विद्यालयों के साथ औषधालय संलग्न करना—प्राप्त पूंजी के अनुसार छे टे छे टे औषधालय प्रारम्भिक विद्यालयों से संलग्न रहेंगे और उसमें औषधियाँ ऐसे प्रतिबन्धों के साथ रखी जायगी जो निर्धारित अधिकारी ( डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ़ हेल्थ ) द्वारा नियत की जाय।

२३८—निरीक्षण और नियंत्रण—पंचायत के सदस्य और उसके अधिकारी विद्यालयों, औषधालयों, पुस्तकालयों तथा अन्य ऐसी संस्थाओं का जो किसी पंचायत द्वारा स्थापित की गई या चलाई जाती हो निरीक्षण और नियंत्रण करेंगे और उनका कर्त्तव्य होगा कि वे जनता की इन संस्थाओं में सहायता देने के लिये प्रोत्साहित करें।

२३९—गांव सभाओं द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालयों इत्यादि का स्थापित करना और उनको चलाना—यदि आसपास की सभाओं का एक समूह मिलकर एक विद्यालय, औषधालय या चिकित्सालय स्थापित करें और चलायें तो एक संयुक्त समिति जिसमें प्रत्येक पंचायत के तीन-तीन निर्वाचित सदस्य उन्हीं के सदस्यों में से रहेंगे, उक्त संस्थाओं का प्रबन्ध और नियंत्रण करेगी और तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यय, स्थानी

क क्रमवादी अनुगत से बराबर-बराबर भागों में प्रत्येक पंचायत हाउस बना दिया जायगा ।

## स्वयंसेवक दल

२४०—ग्रामीण स्वयंसेवक दल ( १ )—पंचायत निर्माण अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करके और गांव-सभा से परामर्श करने के बाद एक ग्राम स्वयंसेवक दल ऐसे प्रतिबन्धों के साथ जो निर्माण अधिकारी (जिला पंचायत, आ.प्र.म.र. और ग्रामस्थानीय सहायक दल के जिला आ.प्र.म.र.) द्वारा निश्चित किया जाय, रखेगी ।

( २ ) इस दल का व्यय, अदालतों के जुर्मानों से पंचायत के पास जिला बोर्ड की आर्थिक सहायता और जनता के दान से पूरा किया जायगा ।

( ३ ) सब प्रौढ़ पुरुष जिनकी अवस्था ४५ वर्ष से अधिक न हो, स्वयंसेवकों के रूप में भर्ती होने के योग्य समझे जायेंगे ।

२४१—स्वयंसेवक-दल का कार्य—स्वयंसेवक दल के निम्न लिखित काम होंगे—

( १ ) गांव में चौकी-पहरे का काम करना ।

( २ ) पंचायत तथा न्यायलय के गोदियों और सम्मनों को पहुँचाना और अन्य आदेशों को कार्यान्वित करना जो वहाँ उनके सौंपे जायें ।

( ३ ) अन्य कानूनों में पंचायतों की सहायता करना, जैसे जन-स्वत्वा के सम्बन्ध में आदेशों का देना करना में, जैसे पशुओं का रक्षा और मनुष्य की रक्षण करना ।

( ४ ) विभिन्न सम्प्रदायों में सद्भाव और सामाजिक एकता का मित्रता बढ़ाने के काम में पंचायत का सहायता करना ।

( ५ ) दुर्भिक्ष या अन्य आगति के दुःख निवारण करने में पंचायत की सहायता करना ।

( ६ ) मेलों, पठ्यस्थानों ( पैठों ) और हाटों का संगठन और उनकी व्यवस्था करने में पंचायत की सहायता करना ।

( ७ ) किसी अन्य कर्त्तव्य का पालन करना या कोई अन्य काम सम्पादन करना जिसके करने की आज्ञा निर्धारित अधिकारी ( जिला पंचायत अफसर और प्रांतीय रक्षा दल के जिला अफसर ) या सरकार द्वारा पंचायत को दी जाय या जो उसके लिये नियत किया जाय ।

२४२—विशेष अधिकारी के कर्त्तव्य—पंचायत स्वयंसेवक दल का प्रधान नियुक्त करेगी जो स्वयंसेवक दल का सन्निहित उत्तरदायी होगा और अन्य ऐसे अधिकारी जिनको कि प्रांतीय सरकार निर्धारित करे और अनिवार्य आवश्यकता पर उपयुक्त अधिकारी निर्धारित अधिकारी ( जिला पंचायत अफसर और प्रांतीय रक्षा दल के जिला अफसर ) द्वारा ऐसे प्रतिबन्ध के साथ अधिकार दिया जा सकता है जिसको वह चाहे ।

( अ ) दल के किसी सदस्य को हटा दे या ऐसे व्यक्ति को हटाने की आज्ञा दे जिसकी उपस्थिति से दल के यथोचित कार्य में बाधा पड़ती हो ।

( ब ) स्वयं या दल की सहायता से किसी भवन में यथासम्भव कम हानि पहुँचाते हुए घुस जा सकते हैं या तोड़कर घुस सकते हैं या गिरा सकते हैं ।

( स ) निकटवर्ती ग्राम स्वयंसेवक दल की ऐसी सहायता के लिये बुलावे जो आवश्यक हो ।

( द ) साधारणतया ऐसे उपाय कार्य में लावे जो जन और धन दोनों की रक्षा के लिये आवश्यक हो ।

## उपनियम बनाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

२४३—उपनियमों की पांडुलिपि का प्रकाशन—उपनियम बनाने से पहले पंचायत उपनियमों की एक पांडुलिपि सभा के क्षेत्र में

किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करा के सभा के क्षेत्र में विशेष स्थानों में लगवाकर और पंचायत के कार्यालय के सामने लगवाकर, प्रकाशित करायेगी और निश्चित समय के भीतर उसके विरुद्ध आपत्तियों को आमंत्रित करेगी ।

२४४—उपनियमों का लागू करना—आपत्तियों पर विचार करने और उनके सम्बन्ध में निर्णय कर लेने के बाद, पंचायत उनमें निर्धारित अधिकारी ( जिला बोर्ड की कार्य कारिणी समिति ) के पास भेज देगी जो या तो उसमें संशोधन करेगा या उनकी स्वीकृति देगा या उनके सम्बन्ध में कोई अन्य उपयुक्त आदेश देगा ।

जब उपनियम निर्धारित अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो जाय तो वे उसी ढंग से प्रकाशित किये जाने के बाद जिस ढंग से उनकी पाहुलियां प्रकाशित की गई थी, प्रचलित होंगे ।

२४५—निर्धारित अधिकारी द्वारा प्रकाशन—(१) निर्धारित अधिकारी ( जिला बोर्ड की कार्य कारिणी समिति ) उपनियमों की स्वीकृति के समय उनकी पाहुलियां प्रकाशित करेगा जैसी कि उसकी स्वीकृति पिछले नियम में की गई है और निर्धारित समय के भीतर आपत्तियों को आमंत्रित करेगा ।

## पत्र-व्यवहार का माध्यम

२४६—पत्र व्यवहार का माध्यम—पंचायत का व्यवहार का पत्र-व्यवहार जो शासन के साथ या किसी विभाग के सम्पर्क में किसी विभाग के कमिश्नरी के प्रतिनिधि के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो या तो मजिस्ट्रेट के नीचे काम करता हो या सचिव के उसके निम्नस्थ में हो और उसके आदेशों को पालन करता हो, जिसे जायदाद, निर्धारित अधिकारी (जिला पंचायत सचिव, तथा इन्स्पेक्टर) के पास से होकर जायगा ।

## ऋण लेने का अधिकार ।

२४७—ऋण लेने का अधिकार—सभा को उन दशाओं के अधीन सरकार से ऋण लेने का अधिकार होगा जो (लोकल अथारिटीज क्लब, १९१५) स्थानीय संस्थाओं द्वारा ऋण लेने के नियमों, सन् १९१५ ई० में जो भारतीय सरकार के अर्थ-विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६२० अ, तारीख १० नवम्बर, सन् १९१४ ई० के साथ प्रकाशित किये गये थे, दी गई है ।

## धारा ६ के अन्तर्गत जांच

२४८—सभापति के लिये अयोग्यता रखने पर जांच—धारा ६ के अधीन जा जांच की जायगी उसमें प्रधान मौखिक या लिखित साक्षी द्वारा अपने सन्तोष के लिये इस बात की परीक्षा करेगा कि आया अयोग्यता उपयुक्त वैधानिक अधिकारी द्वारा हटा दी गई है या यह कि सम्बन्धित व्यक्ति सभा के क्षेत्र में अपने स्थायी निवास स्थान में फिर से बस गया है और उसके बाद तदनुसार आदेश देगा ।

## धारा १०४ के अन्तर्गत नियम

२४९—ऐक्ट नियम या उपनियमों के अन्तर्गत अपराधों का कुछ रकम देने पर क्षमा कर देना—इस ऐक्ट के या इसके अधीन बनाये हुए किसी नियम या उपनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसे प्रार्थनापत्र पर जो सम्बन्धित पक्ष के व्यक्ति द्वारा दी गई हो और ऐसी रकम देने पर जो प्रधान द्वारा नियत की जाय और जो १० रुपये से अधिक न हो, पंचायत के प्रधान द्वारा समझौता कराया जा सकता है और वह रकम गांव-कोष में जमा की जायगी ।

## अध्याय ५

## पंचायती अदालत

## उसका निर्माण और कार्य विधि

नियम ८३—अधिकार क्षेत्र—जिलाधीन जिले की प्रत्येक तहसील को मंडलों ( सर्किलों ) में इस प्रकार बंटवारा कि अदालत स्थापित करने के लिए एक मंडल में साधारणतया तीन से लेकर पाँच गाँव सभाओं के क्षेत्र सम्मिलित हो सकें।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस प्रकार बंटवारा की जाये वाली अदालत का क्षेत्र जिलाधीन की प्रत्येक तहसील का एक बड़ा प्रतीय हो तो उने अधिकार है कि वह प्राचीन सरायों के पहले से स्वीकृति लेकर ऐसा मंडल बनाये जिसमें इससे अधिक या कम गाँव-सभाएँ हों।

नियम ८४—( बाद में प्रकाशित किया जाएगा )।

नियम ८५ पंचायती अदालतों के पक्षों का निर्वाचन :—  
कोई व्यक्ति जो किसी गाँव पंचायत का पञ्च निर्वाचित होने जाने की योग्यता रखता हो और जो हिन्दी जिन पद रखता हो वह इस विधान ( ऐक्ट ) की धारा ४२ के अन्तर्गत पंचायतों अदालत का पञ्च निर्वाचित होने जाने के योग्य होगा।

नोट—धारा ४२ में प्रत्येक गाँव नन्दा अपने अपने के रहने वालों में से ५ प्रौढ़ नागर पञ्चायती अदालत के अपने पञ्च चुनेगी। जिले को क्षेत्रों में बाँटा जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में एक पञ्चायती अदालत होगी। इन क्षेत्र में जितनी गाँव सम्मिलित होंगी। वे हर एक ५-५ पञ्च चुन कर पञ्चायती अदालत के निर्देश में होंगे और इन पञ्चों का पञ्चमंडल बन जाएगा।

भाग १

कुटुम्ब का रजिस्ट्रार

गाँव-सभा का नाम

गाँव का नाम.

तहसील

15

सक्रिय-मूल	सक्रिय	कुटुम्ब के नाम	पिता का नाम	धर्म और परिगणित जातियों की दशा में जाति	आयु और जन्म की सम्भावित तारीख, यदि ज्ञात हो	पेशा	पढ़ा या अनपढ़	क्या पंचायत राज ऐक्ट की धारा ५ के अर्थीन प्रौढ़ और योग्य है ? यदि अयोग्य हो तो अयोग्यता का कारण	नाम जो जेड़े गये या काटे गये व्योरे सहित	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	१०	११	१२

# भाग २

## योग्य प्रौढ़ों का रजिस्टर

गौव-सभा का नाम.....  
 गौव का नाम.....

तहसील..... जिला.....

क्रम-संख्या	व्यक्ति का नाम मुम्तिम या परिवारिक नाम	पिता का नाम	पेशा	भाग १ की प्रुष्ठ संख्या		नाम जो जोड़े गये या काटे गये, कारणों के सहित	अन्य विवरण
				जिस पर नाम दर्ज किया गया हो	तत्पर मकान		
१	२	३	४	५	६	७	८



# जय स्वतन्त्र भारत की

वी० पी० खर्च छोटी पुस्तकों का बहुत लगता है इसलिये यह सुविधा कर दी है जो पुस्तकों का मूल्य आडर के साथ भेज दौं उनके लिये डाक खर्च माफ़ कर दिया है इससे लाभ उठाइये और आठ आना तक के आडर वी० पी० से बहुत कम भेजते हैं क्योंकि सात आना वी० पी० खर्च लगता है तो वो पुस्तक ॥) की ॥३) में पड़ती है तो लोग वी० पी० वापस कर देते हैं। जो सिर्फ नियम पंचायत राज के आडर भेज चुके हैं उनसे निवेदन है सनीआडर भेजे और उसी फार्म में आडर और पता साफ पूरा लिखें :—

१—पंचायत राज एक्ट नं० २६ सन् ४७ नवीन नोट सहित द्वितीय संस्करण १)

२—संयुक्त प्रान्तीय कास्तकारी ( तरमीम ) एक्ट नं० १० सन् १९४७ मय नोट ॥)

३—दुकान कानून मय शंसाधन ॥=)

४—भारत का नया विधान (Constitution) नोट समेत ६)

५—विक्री कर मय संशोधन एक्ट ४८ व आखिरी विज्ञप्तियां नोट सहित ॥=)

६—ग्राम मुधार (भूमि अधिकरण) एक्ट ४८, १)

७—ग्राम आवादी एक्ट ४८, ३)

८—नया कानून सीरीज नं० १, ३) ॥, नं० २, ३) ॥

९—U. P. (Temporary) Control of Rent and Eviction Act NO 3 with new amendment Act. NO 44 of 48 with notes Price -8-as

हर शहर म विक्रेताओं की सख्त जरूरत है उनके लिये विशेष रियायतें दी जाती हैं जैसा बड़ा विक्रेता हो पत्र व्यवहार करें।—कानून महल १ सी वाई० चिन्तामणि रोड

श्री सुरेन्द्र नारायण अग्रवाल एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद।

मुद्रक—महावीर प्रसाद, प्रेम प्रेस, कटरा प्रयाग।

## रूपपत्र

## सिक्क्योरिटी बॉण्ड

चूँकि.....को पंचायत ने यह स्वीकार कर लिया किया है कि वह—

मुझे-पिता का नाम.....	}	प्रस्तावना को उग दिगन्त में
क ख		देना चाहिए हैं कि
ख क—निवासी .....		निम्नलिखित में से किसी के लिए
		हो:—

जिला.....को	क—निजी जमानत
.....के पद पर	ख—निजी जमानत जमानतदार
.....	के सहित या
	ग—केवल जमानतदारों के लिए

विभाग में	}	मेरे जमानत देने पर	कि कर्मनिष्ठ होकर
		हमारे जमानत देने पर	परिष्कार के
		हमारे जमानतदार होने पर	

साथ	}	मेरे कर्त्तव्य को पालन करने पर.....
		उसके कर्त्तव्य नियुक्ति करे ।
		अपने कर्त्तव्य

( क, ख और ग आवश्यकतानुसार पञ्चायत द्वारा उनेवने वाक्य-खण्ड हैं, जिनमें से किसी एक को परिस्थिति के अनुसार चयन करना चाहिए ) ।

क—सर्वसाधारण को विदित हो कि मैं क, ख उक्त संस्करण के प्रति.....हमारे की स्तुति के लिए कोर उत्तरदायी

और दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हूँ और यह रकम, मुझे उक्त पंचायत को देनी होगी और इस भुगतान के लिए मैं अपने आपको और अपने उत्तराधिकारियों, मृतलेख प्रवर्तकों तथा सम्पत्ति के प्रबन्धकों को दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध करता हूँ और इस रकम की भुगतान को और अधिक निश्चित करने के लिए मैं इसके द्वारा उक्त पंचायत के पास जैसा कि इसके साथ नत्थी किये हुए परिशिष्ट में विवरण दिया हुआ है ( रेहन करता हूँ या रेहन के तौर पर हस्तान्तरित करता हूँ ) ।

ख—सर्वसाधारण को विदित हो कि हम ( कं, ख, ग, और ङ च ) उक्त पंचायत के ..... रुपये की रकम के लिए उत्तरदायी और दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हूँ और यह रकम हमें उक्त पंचायत को देनी होगी और इस भुगतान के लिए हम अपने आपको सम्मिलित रूप में और पृथक्-पृथक् और अपने उत्तराधिकारियों मृतलेख प्रवर्तकों को तथा सम्पत्ति के प्रबन्धकों को दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध करते हैं और इस भुगतान को और अधिक निश्चित करने के लिए हम इसके द्वारा उक्त पंचायत के पास जैसा कि इसके साथ नत्थी किये हुए परिशिष्ट में दिया हुआ है ( रेहन करते हैं या रेहन के रूप में हस्तान्तरित करते हैं ) ।

ग—सर्वसाधारण को विदित हो कि हम ( ग, घ और ङ, च ) उक्त पंचायत के ..... रुपये की रकम के लिये दृढ़तापूर्वक वचनबद्ध हूँ और यह रकम हमें उक्त पंचायत को देनी होगी और इस भुगतान के लिये हम अपने आपको सम्मिलित रूप में और पृथक्-पृथक् और अपने उत्तराधिकारियों, मृतलेख प्रवर्तकों तथा सम्पत्ति के प्रबन्धकों को वचनबद्ध करते हैं और इस भुगतान को और अधिक निश्चित करने के लिए हम इसके द्वारा उक्त पंचायत के पास जैसा कि इसके साथ नत्थी किये हुए परिशिष्ट में विवरण दिया हुआ है ( रेहन करते हैं या रेहन के रूप में हस्तान्तरित करते हैं ) ।

उपरोक्त बाण्ड का प्रतिबन्ध ऐसा है कि यदि ( मैं )

( क ख )

( क ख )

कर्मनिष्ठा और परिश्रम के साथ ( अपना )

( अपने )

( अपने ) सम्पत्तियों को

..... के पद पर करता हूँ और शत्रु-पक्ष पर और उन सब समयों पर जब मुझसे ऐसा करने को कहा जाय, तब समस्त धन, सिक्कोरिटियों और सम्पत्तियों का बिगड़ने, बिना, या किसी सम्बन्ध में मैं क ख/क ख उत्तरदायी या जिम्मेदार भीतिव निवेदना या जिसे मैं क ख/क ख वसूल करूँ/करूँ या मुझे/हमें सौरी जमा दान पंचायत को पूरा हिस्सा दूँगे, सौंप दूँगे और दे दूँगे और हम वादा देते हैं कि हम ऊपर दी हुई किसी-ऐसी दशा में सिक्कोरिटियों को होने सम्पत्तियों में श्रवण न करेंगे, लौटाने से इन्कार न करेंगे, नष्ट न करेंगे या किसी और तरह से उसे हानि न पहुँचायेंगे । ऐसी दशा में हमारा लिखित बाण्ड निष्प्रभाव होगा, अन्यथा वह पूर्णरूप से लागू रहेगा ।

यह वाक्य-खण्ड उस दशा में

प्रयोग में नहीं लया जायगा

जब कोई जमानतदार न हो

और इस वाक्य-खण्ड में जमानत

की ओर से क ख के पद में नहीं

वह कर्तव्य न मानने करेंगे

किसी और किसी दशा में

के प्रतिबन्ध को पूरा न करने से

कोई जमानतदार न मानेगा

..... के पद में

में मैं किसी एक को या हमारे

उत्तराधिकारियों को, नष्ट

के प्रवर्तकों को या सम्पत्ति के प्रबन्धकों को या इसके द्वारा रेहन की हुई सम्पत्ति को किसी प्रकार भी उपरोक्त बाँड के अन्तर्गत उत्पन्न होनेवाली दायित्वों से मुक्त न करेगी ।

### परिशिष्ट

उपरोक्त व्यक्ति.....ने दो गवाहों.....( के सामने ).....हस्ताक्षर किये ।

नोट—( १ ) जब अचल सम्पत्ति रेहन की गई हो तो यह आवश्यक है कि बाँड रजिस्टर्ड हो ।

२) जब बाँड में कर्मचारी द्वारा हस्तगत पद का नाम दिया गया हो, तो बाँड केवल उस पद के लिये चालू रहेगा जब तक उक्त कर्मचारी उस पद पर रहें । यदि यह सम्भव हो कि कर्मचारी एक से अधिक पद पर या तो उन्नति करके या किसी और प्रकार काम करे, तो काम में परिवर्तन करना आवश्यक होगा ।

山, 上, 上, 上, 上

१० आग्नि-अय्यक (वज्र) का नक्षत्र

23

-28-

Wille in die Wille

上

14

十一

प्रश्न	उत्तर	विवरण	पृष्ठ
१. ...	...	...	...
२. ...	...	...	...
३. ...	...	...	...
४. ...	...	...	...
५. ...	...	...	...
६. ...	...	...	...
७. ...	...	...	...
८. ...	...	...	...
९. ...	...	...	...
१०. ...	...	...	...

John J. White

 $\frac{1}{2}(\frac{1}{2})$ 

Billie (7)

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने की वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनु- मानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०	₹०

(ख) अस्थायी

(२) चिकित्सा (मेडिकल) —

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

(३) सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) —

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

(४) सड़क —

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

( ५ ) अन्य प्रयोजन—

( क ) शायी

( ख ) शय्याली

२—५२—

( १ ) किताबों व लपान पर

( २ ) शायर आदि पर

( ३ ) दूधमन्त्री पर

इ-पुस्त में शायरीन संग्रह में मिलनेवाली अन्य अन्य

( ४ ) शायी

( ५ ) शय्याली

२—५३—

( १ ) शायरी से शीत, शय्या कोड़े से

( २ ) अन्य शय्याली को शीत

( ३ ) शय्याली

( ४ ) शय्याली



देख और मद	१					अन्य विवरण
	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने की वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनु- मानित आय	आय व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	
	२	३	४	५	६	७
	६०	६०	६०	६०	६०	६०

( ३ ) अथ साधनों के चंदे

( ४ ) अन्य आय

देख ४ का जोड़

५—चिकित्सा ( मेडिकल )—

- ( १ ) रोगियों से आय  
 ( २ ) दवाओं की बिक्री  
 ( ३ ) धर्मार्थ दान से आय  
 ( ४ ) स्थानीय बोर्डों से चंदे  
 ( ५ ) दूसरे साधनों से चंदे  
 ( ६ ) दूसरी आय

६—सामयिक म्याग्ज ( पब्लिक हेल्थ )—

- ( १ ) मच्छरों की क्षीम और बुनियाद
- ( २ ) रोग प्रसारण, व्यक्तिगत द्वारा चंदे
- ( ३ ) स्थानीय बोर्डों से चंदे
- ( ४ ) दूसरी आय

७—पंचायत अदालत से आय—

- ( क ) दीवानी न्याय
- ( ग ) पंचद्वारी सुकृष्ण
- ( ग ) माल की मायकादी

८—सेने प्रदर्शनी, माला—

९—समय से आय—

- ( १ ) दसगनी प्रोग्राम (मजल भूमि को छोड़कर)
- माला
- ( २ ) मजल माला (मजल माला को छोड़कर)
- की माला

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने का वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
	२	३	४	५	६	७
१	६०	६०	६०	६०	६०	६०

- ( ३ ) नजूल इमारतों और भूमि का किराया  
( ४ ) नजूल इमारतों और भूमि की बिक्री का  
रकपा और अधिशुल्क (नज़राना)

### १०—विविध—

- ( १ ) पुराने सामान और चीजों की बिक्री  
( २ ) स्थानीय नोडों से चंदे  
( ३ ) गैरसरकारी व्यक्तियों द्वारा चंदे  
( ४ ) मेले और प्रदर्शनी से आय  
( ५ ) फुटकर आय

११—अथाधारणं श्रीर ऋणं—

( १ ) ऋण

( २ ) नरोद्धर या धन

१२—गोच्छृ वाकीं ग्याने जया—

## अथ

१—आधारणं आगम प्रत्यय श्रीर नमूल करने के अर्थ

( १ ) आगम

( २ ) आगम्य का प्रत्यय न नमचागी

( ३ ) आगम्यक, अगम

( ४ ) आगम्य निमित्त के अर्थ

( ५ ) नमूल करने के अर्थ

( ६ ) नमचागी

( ७ ) आगम्यक, अगम

२—आगम

( १ ) नमचागी

क्षेत्र और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने का वास्तविक आय	वर्तमान वर्ष की दुहराई हुई अनुमानित आय	आय-व्यय (बजट) की अनुमानित आय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	र०	र०	र०	र०	र०	र०

(२) आकस्मिक व्यय

(३) पुस्तकालय तथा वाचनालय

(४) विविध

(३)—चिकित्सा (मेडिकल)—

(१) कर्मचारी

(२) आकस्मिक व्यय

(३) विविध

१—सार्वजनिक निर्माण (पब्लिक वर्क्स)—

(१) निर्माण

(२) मरम्मत

(३) विविध

१—सार्वजनिक (पब्लिक हेल्थ) —

- (१) कर्मचारीवर्ग
- (२) आकस्मिक व्यय
- (३) चचा तथा शिशु-मालन
- (४) विविध

२—पंचायती अदालत —

- (१) कर्मचारीवर्ग
- (२) आकस्मिक व्यय
- (३) विविध

३—प्रसीटेंट फन्ड —

विभाग के नाम के मद्तिन

४ विविध —

- (१) कृषि-व्यापार तथा प्रयोग
- (२) कर्मचारी या सामान
- (३) भारतीय स्वतन्त्रता दिवस

(४) निर्वाचन व्यय

९—असाधारण औप ऋण—

- (१) ऋण का सुगतान
  - (२) जमा की हुई रकमें
  - (३) दूसरी पेशगी दी जानेवाली रकम
- १०—रोकड़ बाकी खाते नाम (व्योरा)—

१४०

हेड और मद	गत वर्ष की वास्तविक आय	गत वर्ष की अनुमानित आय	पहिले महीने का वर्तमान वर्ष की तुलनाई हुई अनु वास्तविक आय मानित आय	आय-व्ययक (बजट) की अनुमानित आय	अस्य विवरण
१	२	३	४	५	७
	२०	२०	२०	२०	२०

‘६, ६६६६

ग्राम या गाँव का नाम	ग्राम का नाम
ग्राम या गाँव का नाम	ग्राम का नाम



इन ऐक्ट की धारा में

५ और ६

१२ की उपधारा ३ और ४

१७ ( ड ) व २० और २२

२७ की उपधारा १

२७ की उपधारा २

३० की उपधारा २

३६

४१ की उपधारा ३

४२

४४

४७

६६

६८

१०६ (दो या अधिक गांव पंचायतों  
के बीच झगड़ों में)

१०६ गांव-(पंचायत और या उन  
एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड या

ज़िला बोर्ड के बीच झगड़ों में) प्रान्तीय शासन ।

१११ व ११२ की उपधारा २

नियम संख्या

३

३६

४७ क ४८ और ६०

५४-५८ जिला पंचायत अफसर

निर्धारित अधिकारी, ये हैं

हाकिम परगना ।

हाकिम परगना ।

जिला पंचायत अफसर ।

जिला पंचायत अफसर ।

संचालक (डायरेक्टर) पंचायत राज ।

जिला पंचायत अफसर ।

प्रधान (प्रेसीडेंट) जिला बोर्ड ।

इन्सपेक्टर ।

जिला पंचायत अफसर ।

जिला पंचायत अफसर या कोई

निर्दिष्ट न्यायाधिकारी ।

इन्सपेक्टर ।

जिला पंचायत अफसर ।

जिला बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

संचालक पंचायत राज ।

जिला बोर्ड की कार्यकारिणी समिति ।

जिला पंचायत अफसर ।

इन्सपेक्टर ।

इन्सपेक्टर ।

चाकी नियमों में दे दिये हैं ।

